R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 14
16 से 30 अप्रैल 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

विपक्ष की केमिस्ट्री पर चेहरा कौन?

मोदी का मुकाबला करने जुगलबंदी की एक और कोशिश

2024 में 2004 वाले फॉर्मूले पर विपक्षी एकता की कवायद

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

वल्लभगाथा

8 | 2 साल का इंतजार अब होगा खत्म

मप्र में 2 साल से आईएएस और आईपीएस बनने का इंतजार कर रहे राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपीएससी ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की तारीख...

राजपथ

10-11 | जातियों के भरोसे जीत

मप्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ सत्ता चाहती हैं। इसलिए दोनों पार्टियों की कोशिश है कि हर वर्ग को किसी न किसी तरह साधा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह...

विकास

15 | 33 लाख आबादी की बुझेगी प्यास

सतना और रीवा जिले को पूरी तरह से पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने 6000 करोड़ रुपए की बाणसागर और टमस समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। योजना के जरिए 33.90 लाख आबादी को...

स्मार्ट सिटी

19 | भोपाल 10 फीसदी भी स्मार्ट नहीं

केंद्र की नजर में भोपाल स्मार्ट सिटी देश में नंबर वन है। जबकि हकीकत यह है कि 7 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद शहर 10 फीसदी भी स्मार्ट नहीं हुआ है। 24×7 पानी सप्लाई, स्मार्ट बिजली और स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी अन्य सुविधाओं और वॉकिंग...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन विपक्षी एकता का तानाबाना बुना जाने लगा है। इस बार वाया नीतीश कुमार यह प्रयास शुरू हुआ है। वे 2024 में विपक्ष को एकजुट करने का मकसद लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश ने राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल तक से मुलाकात कर विपक्ष की केमिस्ट्री मजबूत करने की कोशिश की है। 2024 में 2004 वाले फॉर्मूले पर शुरू हुई विपक्षी एकता की कवायद क्या गुल खिलाएगी यह तो...

राजनीति

30-31 | क्षत्रपों को दरकिनार...

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो गई हैं। लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, ऐसे में यह बात तो तय है कि आगामी चुनाव में क्षेत्रीय क्षत्रपों का दम दिखेगा। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कारण था कि इंदिरा...

महाराष्ट्र

35 | विपक्षी एकता में आई दरार

कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि सभी विपक्षी दल राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं। खासकर जब उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हुई, तो तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और समाजवादी पार्टी भी उनके पीछे खड़ी दिखाई देने लगी थीं। ये चारों दल वे हैं, जो गैर कांग्रेस...

बिहार

38 | जाति जनगणना का प्रपंच

बिहार के लिए जाति एक विकट प्रश्न है। इसे सीधे समाजशास्त्रियों वाले अध्ययन के तौर पर परिभाषित करने के बदले लोकोक्तियों से उधार लें, तो जाति के बारे में कहा जाता है कि जो कभी नहीं जाती, उसे जाति कहते हैं। बिहार में जाति जनगणना...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

आखिरकार थर्ड जेंडर को मिला जातिगत आरक्षण

किसी ने थर्ड जेंडर के बारे में लिखा है...

नहीं चाहिए देव सा मान, ना अलौकिक दिव्यता का सम्मान।
देना हो तो दीजिए हमें सम जीवन जीने का अधिकार।

उपरोक्त पंक्तियों को मप्र की शिवराज सरकार ने साकार कर दिखाया है। गौरतलब है कि आज हम भले ही आधुनिकता के दौर में हैं, लेकिन अब भी थर्ड जेंडर को उपेक्षित और निम्न नजरों से देखा जाता है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रखी हैं, लेकिन इस दिशा में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और उन्हें जातिगत आरक्षण की श्रेणी में ला खड़ा किया है। यानि प्रदेश में अब थर्ड जेंडर भी पिछड़ा वर्ग का हिस्सा होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद थर्ड जेंडर भी सरकारी भर्ती में 14 फीसदी आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। सरकार की यह पहल प्रदेश के 30 हजार थर्ड जेंडर के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। गौरतलब है कि अब थर्ड जेंडर भी मुख्यधारा में आकर सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम से उन्हें फायदा पहुंचेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पिछले दिनों एक आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के तहत अब राज्य सरकार थर्ड जेंडर को ओबीसी वर्ग की सूची में शामिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग के तीसरे वर्ग के रूप में थर्ड जेंडर को मान्यता दी है। कोर्ट ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि थर्ड जेंडर सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय है और ऐसे में उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के आर्टिकल 14, 16, 2 का हवाला देते हुए कहा था कि थर्ड जेंडर देश के नागरिक हैं। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता पर समान अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रदेश में अभी 64 से ज्यादा जातियां ओबीसी वर्ग में शामिल हैं। जिन्हें संवैधानिक रूप से 14 फीसदी का आरक्षण मिला है। गौरतलब है कि देश में मप्र उन राज्यों में शामिल है, जहां थर्ड जेंडर राजनीति में भी पहचान बना चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ सालों में थर्ड जेंडर के प्रत्याशियों ने कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को भी कुछ चुनाव में धूल चटा दी। थर्ड जेंडर कैटेगरी से आने वाली मप्र की शबनम मौसी बानो ने 25 साल पहले इतिहास रचा था, जब वे देश की पहली किन्नर विधायक बनी थीं। वे शहडोल जिले की सोहागपुर विधानसभा अब (जैतपुर) से विधायक रही थीं। यहां तक कि उन्होंने 2018 के मप्र विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा था। कटनी जिले में भी साल 2000 में इतिहास रचा गया था। जब निर्दलीय किन्नर प्रत्याशी कमला मौसी कांग्रेस व भाजपा के दिग्गज प्रत्याशियों को हराकर कटनी नगर निगम की मेयर बनीं थीं। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन कमला मौसी का कार्यकाल लोगों को आज भी याद है। कमला मौसी 2000 से 2003 तक कटनी की महापौर रहीं। अगर उनकी सदस्यता नहीं जाती तो वो आज देश की पहली मेयर होतीं। वहीं सागर में भी कमला बुआ ने 2009 में मेयर का चुनाव जीता था। 2009 से 2011 तक वह मेयर की सीट पर रहीं। हाईकोर्ट ने कमला बुआ का भी चुनाव रद्द कर दिया था। बता दें कि कमला बुआ और कमला मौसी के केस में यह चीज सामने आई थी कि यह दोनों सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं और यह दोनों पुरुष किन्नर थीं। इसलिए इनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। अब नए आरक्षण से इस वर्ग को काफी लाभ होगा।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 14, पृष्ठ-48, 16 से 30 अप्रैल, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

पार्टियों की तैयारियां

प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने जहां विधायकों और मंत्रियों को चुनाव की तैयारियों के लिए जनता से रूबरू होने की सलाह दी है, वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

● **अमित मिश्रा,** ग्वालियर (म.प्र.)

किसानों पर ध्यान दें सरकार

बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश की सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की तैयारी करनी चाहिए। जिससे बेबस किसान परेशान न हो और अगली फसल के लिए फिर तैयारी कर सके।

● **शफीक कुरैशी,** राजगढ़ (म.प्र.)

प्रदूषण से नदियां खत्म हो रही

मप्र में प्रदूषण से नदियों का दम घुट रहा है। जीवनदायिनी नर्मदा के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगह पानी पीने लायक तक नहीं है। कई नदियों में प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि उनका पानी छूने योग्य भी नहीं है। इससे जलीय विविधता खत्म हो रही है। जीव-जंतु दम तोड़ रहे हैं।

● **मेघा सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

लोकतंत्र को बचाना जरूरी

देशभर इस समय जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल चल रहा है, वह लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। जिसकी मर्जी में जो आ रहा है, वे वही बोल रहा है। इस प्रकार राजनीति को दूषित किया जा रहा है। नेताओं को अपनी भाषा को मर्यादा में रहकर उपयोग करना चाहिए। जिससे राजनीति में मनभेद न हों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा व 15 हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया था। इस प्रकार कई अन्य नेता भी हैं जिन पर मानहानि का केस चल रहा है। लेकिन इन्हें ये सोचना होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां ये सब सहन नहीं किया जा सकता।

● **पवन सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

अच्छी व्यवस्था बनाए सरकार

एक समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज हर रोज गली में दरवाजे पर आकर आवाज लगाने वाले दर्जनों भिखारियों को देखा जा सकता है। भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि इनकी क्षेत्र और जगह भी बंट चुकी हैं। स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन भिखारियों को कुछ बांटने के लिए पहुंचता है, तो उसे भीख मांगने वालों की एक भीड़ घेर लेती है। इस प्रकार से दुनिया में हमारी छवि अच्छी नहीं बन रही है। सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और एक अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए।

● **हेमेंद्र पांडे,** नई दिल्ली

घोटालेबाजों पर कार्यवाही हो

प्रदेश सहित देशभर में आयुष्मान घोटाले के कई मामले सामने आए हैं। जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों की चपत लगी है। वहीं एक बार फिर कोरोना अपने रौद्र रूप में वापस आ रहा है। इससे अस्पतालों में एक बार फिर इस प्रकार के घोटाले होने की संभावना है। इसलिए सरकार को पहले से सतर्क रहकर जांच शुरू करनी चाहिए और ऐसे घोटालेबाजों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ताकि अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे।

● **सुरेश शर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

पंजाब कांग्रेस में बढ़ेगी हलचल

रोडरेज मामले में एक साल की सजा काटकर हाल ही में रिहा होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने संकेत दिया कि वह पंजाब की राजनीति में पूरी तरह सक्रियता दिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों के लिए काम करने के उनके संकल्प को कोई डिगा नहीं सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, 'मेरे मेंटर राहुल जी और मित्र, दार्शनिक, गाइड प्रियंका जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता न तो झुकेगी और न ही एक इंच पीछे हटेगी! मेरे नेता न तो झुकेंगे और न ही एक इंच पीछे हटेंगे।' सिद्धू के इस ट्वीट से यह संकेत मिलता है कि वह अब फिर से पंजाब कांग्रेस में सक्रिय होने वाले हैं। इससे एक कयास यह लगाया जाने लगा है कि क्या पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा? इधर सिद्धू की रिहाई के बाद से पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह की खामोशी साध ली है। उससे साफ है कि सिद्धू की वापसी से सूबे के कांग्रेसी नेता उत्साहित नहीं हैं।

मनीष तिवारी का होगा पुनर्वास!

पंजाब से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी वैसे तो अब भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन संचार विभाग की ओर से उनको प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बुलाया जाता है। जबसे उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले जी-23 नेताओं की चिट्ठी पर दस्तखत किया था तबसे वे हाशिए में हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनका पुनर्वास होने वाला है। बतौर प्रवक्ता उनका पुराना पद बहाल हो सकता है। यानी नियमित प्रेस ब्रीफिंग से लेकर मीडिया को बयान देने या विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा उनको मिल सकता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनका अधिकतम इस्तेमाल करने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों तिरूवनंतपुरम में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको भेजा गया था। संसद की गतिविधियों में भी उनकी भूमिका बढ़ी है। उन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद काम रोको प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। केंद्र सरकार ने जब वन संरक्षण संशोधन विधेयक संसद की स्थाई समिति को नहीं भेजा तो तिवारी ने इसका विरोध किया। इस मंत्रालय की कमेटी के प्रमुख जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस के संचार विभाग के भी प्रमुख हैं। रमेश ने भी वन संरक्षण विधेयक संसद की स्थाई समिति को नहीं भेजने के विरोध में चिट्ठी लिखी है। उन्हीं की तर्ज पर मनीष तिवारी ने भी विरोध किया।

दादा की टीम में युवाओं की एंट्री

गुजरात में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसमें 6 से 7 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा युवा चेहरों में शामिल हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर को भी जगह मिलने की उम्मीद की जा रही है। अल्पेश ठाकोर गांधीनगर दक्षिण से जीते थे, तो वहीं हार्दिक पटेल अहमदाबाद जिले की ग्रामीण सीट विरमगाम से जीते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत भी हुई थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि गुजरात के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लिया। गुजरात विधानसभा चुनावों में गांधीनगर की लड़ाई में उलझे अल्पेश चुनाव जीतने के बाद असम गए थे और उन्होंने वहां जाकर मां कमाख्या के मंदिर में मत्था टेक आशीर्वाद लिया था। तब ऐसी अटकलें लगी थीं कि शायद फिर से विधानसभा पहुंचने पर ठाकोर मां के दरबार में हाजिरी लगाने गए थे। अल्पेश अपने असम दौरे में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से भी मिले थे।

तो तीसरी शक्ति बनेंगे सचिन!

सचिन पायलट को कांग्रेस में अशोक गहलोत के रहते अपना कोई सियासी भविष्य नजर नहीं आता। तभी तो अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया। जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी अशोक गहलोत पर कटाक्ष का मौका मिला। पायलट के सामने अब अपनी अलग पार्टी बनाने के सिवा कोई विकल्प नजर नहीं आता। भाजपा में जाकर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। वहां तो मुख्यमंत्री पद पर महारानी नजर टिकाए हैं। वसुंधरा इतनी ताकतवर हैं कि आलाकमान को झुकना पड़ा है। दो साल पहले जब सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों को साथ लेकर पार्टी से बगावत की थी तब भी उनकी असफलता के पीछे अशोक गहलोत से ज्यादा भूमिका वसुंधरा की थी। जिन्होंने चेतावनी दे दी थी कि पायलट मुख्यमंत्री बने तो वे पार्टी तोड़ देंगी। पायलट चाहते हैं कि आलाकमान उन्हें बाहर कर दे। जब पहली बार बगावत की थी तो सूबे के उपमुख्यमंत्री भी थे और पार्टी के सूबेदार भी। बगावत के बाद गहलोत ने ये दोनों हैसियत भी उनसे छीन ली थी।

मुश्किल डगर

कर्नाटक में भाजपा को दक्षिण के अपने इकलौते दुर्ग को बचाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहने को येदियुरप्पा अभी पार्टी के सिरमौर बने हैं पर उनके करीबी नेता तो एक-एक कर लगातार भाजपा छोड़ रहे हैं। किसी से छिपा नहीं है कि येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद पार्टी आलाकमान के दबाव में छोड़ा था। बसवराज बोम्मई भी उनके पसंदीदा नहीं हैं। होते तो येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को अपनी सरकार में मंत्री बना देते। येदियुरप्पा का दूसरा बेटा राघवेंद्र लोकसभा सदस्य है। विजयेंद्र अभी कर्नाटक भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और उन्हीं को येदियुरप्पा का सियासी उत्तराधिकारी माना जाता है। दक्षिण के किसी राज्य में पहली बार भाजपा को सत्ता में लाने का श्रेय येदियुरप्पा को ही दिया जाता है। उन्होंने ही जोड़-तोड़कर कांग्रेस और जनता दल (एस) के विधायकों की बगावत कराकर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद लिंगायत समाज के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाने वाले येदियुरप्पा के समर्थकों में निराशा बढ़ गई।

कौन कहता है, जुगाड़ काम नहीं आती

भारतीय राजनीति हो या प्रशासन यहां जुगाड़ पर कुछ भी किया जा सकता है। इसका ताजा नजारा प्रदेश के सबसे बड़े जिले में देखने को मिला। इस जिले के पुलिस कप्तान के खिलाफ शाम को हाईकोर्ट ने सस्पेंशन का आदेश दे दिया, जिससे प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में हलचल मच गई। लेकिन अगले ही दिन यानि सुबह उनका सस्पेंशन का आदेश वापस ले लिया गया। सवाल उठता है कि आखिर कप्तान ने ऐसी कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था, जिसके लिए कोर्ट ने इतना बड़ा आदेश निकाल दिया और रातभर में कप्तान ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आदेश बदल दिया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने एक वारंट तामिल न करा पाने की वजह से कप्तान को सस्पेंड करने का आदेश पारित कर दिया था। अगर देखा जाए तो प्रदेश में ऐसे न जाने कितने वारंट तामिल नहीं हो पाते हैं। फिर ऐसी क्या वजह थी कि एक बड़े जिले के पुलिस कप्तान के खिलाफ इतना बड़ा आदेश जारी कर दिया गया। इस निर्णय के पीछे कौन है, इस बात की खोज खबर में पुलिस जुट गई है। वहीं कप्तान साहब ने भी यह दिखा दिया कि उनके पास भी जुगाड़ कम नहीं हैं। तभी तो अगले दिन कोर्ट में पेश होकर उन्होंने सस्पेंशन का आदेश निरस्त करवा लिया। दरअसल, साहब के पिता न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और साहब भी लॉ में मास्टर की पढ़ाई किए हुए हैं। वहीं साहब की संघ में भी अच्छी खासी जुगाड़ है, जो समय पर काम आ गई।

उगाही का नायाब तरीका

प्रदेश में कुछ वर्ष पहले हुआ बहुचर्चित हनीट्रैप कांड कुछ अफसरों के लिए उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। आए दिन किसी न किसी की फाइल खोलकर जांच एजेंसियों में बैठे अधिकारी मोटी-चौड़ी रकम वसूल रहे हैं। इस कांड को अंजाम देने वाले सारे दोषी सलाखों के बाहर आ गए हैं। वे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का इस कांड में शोषण हुआ है उनका आज भी दोहन हो रहा है। यही नहीं जांच एजेंसियां अपनी सूत्रों का हवाला देकर किसी भी अफसर को नोटिस भेजकर तलब कर लेती हैं और उनसे वसूली कर लेती हैं। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है और फैसला अंतिम निर्णय पर है। ऐसे में ईडी इस मामले में कूद पड़ा है। अभी हाल ही में ईडी ने प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस भेजा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दो लोगों के बीच हुई लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई। सूत्रों का कहना है कि ईडी मुख्यालय में एक ऐसा अधिकारी बैठा है, जो अफसरों, व्यापारियों आदि को नोटिस भेजकर वसूली करवाता है। हनीट्रैप कांड में अफसरों और व्यापारियों को नोटिस भेज-भेजकर करोड़ों रुपए की वसूली हुई है।

बड़े साहब का जलवा

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के जलवे चर्चा में हैं। वर्तमान समय में साहब महाकौशल क्षेत्र में पुलिस के बड़े ओहदे पर काबिज हैं। बताया जाता है कि साहब जबसे इस क्षेत्र में बड़े ओहदे पर पदस्थ हुए हैं, तबसे उनका पूरा ध्यान लक्ष्मी की कृपा बटोरने में लगा हुआ है। साहब रात-दिन लक्ष्मी के चक्कर में लगे रहते हैं। बताया जाता है कि विगत दिनों साहब ने एक सट्टा किंग से लक्ष्मी की कृपा अर्जित की। इस बात की खबर उनके विभाग के राजनीतिक मुखिया को भी लगी तो उन्होंने भी अपने माध्यमों से उसमें से हिस्सा मांग लिया। यह बात कानोंकान होते हुए सरकार के मुखिया तक पहुंच गई। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि साहब पर गाज गिरेगी और उनका कहीं और तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों ने जब इसकी पड़ताल की तो बताया गया कि साहब को संघ के एक बड़े पदाधिकारी का वरदहस्त प्राप्त है। वर्तमान समय में मप्र की राजनीति में बड़ा रोल निभाने वाले ये पदाधिकारी साहब के ही राज्य से संबंध रखते हैं। इसलिए जब भी साहब पर कोई संकट आता है, ये खड़े हो जाते हैं। यहां यह बता दें कि साहब के लिए उगाही करने की जिम्मेदारी एक एडिशनल एसपी के पास है। जो वर्षों से क्षेत्र के एक बड़े जिले में पदस्थ हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब के फ्रेम में फिट न बैठने पर साहब ने पूर्ववर्ती एसपी को खूब परेशान किया था।

प्रोटोकॉल की समझ नहीं

प्रदेश में कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली का भी कमतर ज्ञान है। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी के बारे में प्रशासनिक वीथिका में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, साहब जिस विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उस विभाग ने ग्वालियर-चंबल अंचल के एक बड़े जिले में एक महाकुंभ का आयोजन किया है। उस महाकुंभ में राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक शामिल होने वाले हैं। बताया जाता है कि इस संदर्भ में जब साहब ने नोटशीट तैयार की तो वे प्रोटोकॉल भी भूल गए। या यूं कहें कि उन्हें प्रोटोकॉल का ज्ञान ही नहीं रहा। दरअसल, नोटशीट में उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का पदनाम लिख दिया, उसके बाद राज्यपाल का पदनाम। जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि सबसे पहले राज्यपाल का नाम आना चाहिए, उसके बाद मुख्यमंत्री व अन्य। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विभाग में प्रमुख सचिव को पता ही नहीं कि प्रोटोकॉल में कौन आगे होता है। अब इस नोटशीट को लेकर लोग साहब के संदर्भ में तरह-तरह की चर्चा कर मजे ले रहे हैं। पता नहीं साहब के पास यह बात पहुंची है कि नहीं।

चट मंगनी, पट ब्याह

यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस समय इसकी तर्ज पर प्रदेश के खेती-किसानी वाले विभाग में काम हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के दिशा-निर्देश पर उनके एक चहेते राजदार इन दिनों प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में मजमा जमाए हुए हैं। वे वहां प्रदेशभर के बीज व्यावसायियों को एक-एक कर आमंत्रित कर रहे हैं और प्रमाणीकरण के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में कई कंपनियां बीजों की सप्लाई करती हैं। हर साल किसानों को करोड़ों रुपए के नकली बीज सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे में विभाग ने इस बार अभियान छेड़ा है कि केवल सरकार द्वारा प्रमाणित कंपनियों को ही प्रदेश में बीज बेचने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में सरकार की इस कोशिश की आड़ में बीज व्यावसायियों से अवैध वसूली का धंधा बढ़ गया है। बताया जाता है कि साहब के राजदार जिनको भी तलब करते हैं उनके साथ बंद कमरे में प्रमाणीकरण की बोली लगवाते हैं। यह बात बाहर न पहुंच जाए, इसके लिए आगंतुक का मोबाइल कमरे से बाहर रखवा दिया जाता है। बताया जाता है कि इससे मोटी रकम बटोरी जा रही है।

2 साल का इंतजार अब होगा खत्म

मप्र में 2 साल से आईएएस और आईपीएस बनने का इंतजार कर रहे राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। यूपीएससी ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की तारीख तय कर दी है। डीपीसी की बैठक 2 मई को दिल्ली में होगी। वर्ष 2021 और 2022 के लिए पहले यह बैठक जनवरी-फरवरी में भोपाल में होनी थी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का समय नहीं मिलने और अन्य कारणों से डीपीसी टलती चली गई। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, गृह विभाग के एसीएस डॉ. राजेश राजौरा, कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना डीपीसी में शामिल होंगे।

आईएएस अवॉर्ड के लिए 2002 और 2006 बैच के अधिकारियों के नाम पर विचार होगा। 2021 के 14 और 2022 के 19 पदों पर डीपीसी होना है। इसमें विवेक सिंह, पंकज शर्मा, सुनील दुबे, राजेश जैन, जयेंद्र विजयवत, प्रमोद शुक्ला, गजेंद्र सिंह नागेश, प्रताप नारायण यादव, सरोधन सिंह, अनुराग सक्सेना, मल्लिका निगम नागर, अजीजा जफर, सपना सोलंकी, मंजूषा राय, संघमित्रा गौतम, संजना जैन, सुष्मिता सक्सेना, कीर्ति खुरासिया, जगदीश गोमे, दिशा प्रणय नागवंशी, कमल नागर, डीके नागेंद्र, मनोज सरयाम, डीपी वर्मा, जीएस धुर्वे, रामप्रसाद अहिरवार, कमलेश भार्गव, अभय सिंह ओरिया, संदीप केरकेट्टा, अंजलि जोसफ, रेखा राठौर, नवीत धुर्वे, सोजान सिंह रावत, वंदना शर्मा, अर्चना सोलंकी, नंदा भलावी, अनिल दामोदर, सविता झारिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, जितेंद्र सिंह चौहान सहित 57 अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा। इसमें 6 से 7 अधिकारियों के पुरानी जांच के नाम पर लिफाफे बंद किए जा सकते हैं। वहीं, आईपीएस के लिए वर्ष 2021 के लिए 10 पद और वर्ष 2022 के लिए 6 पदों पर डीपीसी होगी। इसमें रापुसे के अनिल कुमार मिश्रा, देवेंद्र सिरोलिया, प्रकाश चंद्र परिहार, विनोद कुमार सिंह, मनीष खत्री, राजेश कुमार त्रिपाठी, वीरेंद्र जैन, देवेंद्र कुमार पाटीदार, राय सिंह नरवरिया, राम शरण प्रजापति, गोपाल प्रसाद खंडेल, सुंदर सिंह कनेश, अरुन कुमार मिश्रा, राजेश व्यास, पदम दिलोचन शुक्ला, सुधीर कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार पांडेय, अजय पांडे, डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, मुन्नालाल चौरसिया, दिलीप कुमार सोनी, सीताराम सासत्या, अवधेश प्रताप सिंह बागरी, राजेंद्र कुमार वर्मा, अमृत मीना, विक्रांत मुराब, सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे आदि शामिल हैं। इनमें भी कुछ अधिकारियों के कोर्ट में मामले होने से उनके नाम रोके जा सकते हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

करे कोई, भरे कोई

यह कहावत 2014 बैच के एक आईएएस अधिकारी पर सटीक बैठ रही है। दरअसल, ये साहब जहां भी पदस्थ रहते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निशाने पर आ जाते हैं। इसकी वजह है इनका ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करना। ये हैं आईएएस आदित्य सिंह। साहब पहले राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम संभाले हुए थे यहां भी उन पर तोहमत लगाकर उन्हें विदा कर दिया गया। फिर साहब ग्वालियर-चंबल अंचल के गुना जिले में एडीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विगत दिनों जब जिले के कलेक्टर अवकाश पर थे तब उन्होंने जिले के विकास से संबंधित एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने दिया। यह प्रेजेंटेशन कलेक्टर द्वारा तैयार करवाया गया था। प्रेजेंटेशन ठीक न होने के कारण एडीएम साहब को वहां से रवानगी दे दी गई। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें उनकी गलती क्या है। जब इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा- आंकड़े एकदम सही थे, एडीएम का प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था। दरअसल, प्रदेश में कुछ अफसर ऐसे हैं, जो काम तो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन दूसरों को साधने के चक्कर में खुद नप जाते हैं।

अब तक नहीं मिला मुरैना को एसपी

मप्र में आईपीएस अधिकारियों की कमी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश के मुरैना जिले में कई दिनों का समय बीत जाने के बाद भी एसपी की कुर्सी खाली पड़ी है। अब तक पुलिस अधीक्षक का नाम तय नहीं कर पाए हैं। प्रदेश सरकार में कई दिनों से मंथन चल रहा है। दरअसल, मुरैना दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्थानीय लोगों ने मुरैना एसपी आशुतोष बागरी की कार्यशैली को लेकर शिकायत की थी। कुछ मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग नाराज थे। शहर के हृदय स्थल बसारी बाजार में 4 दिन से लगातार चोरियां हो रही थीं। जिसे लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसपी आशुतोष बागरी को हटा दिया था। इसी के बाद से जिले में एसपी की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। शहर में कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। अब देखना होगा कि कुर्सी कितने दिन और खाली रहती है या फिर किसी पुलिस अधीक्षक को कुर्सी की कमान सौंपी जाएगी। दरअसल, चुनावी साल में सत्ता और संगठन के साथ नेता भी चाहते हैं कि उनकी पसंद का अफसर उनके जिले में पदस्थ हो।

सरकार के निर्णय से हुई किरकिरी

कभी-कभी शासन और प्रशासन स्तर पर कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जिससे सरकार की किरकिरी हो जाती है। ऐसी ही किरकिरी कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद सरकार की हो रही है। दरअसल, विगत दिनों कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया, फिर आदेश बदलना पड़ा। हुआ यूं कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का तबादला जल निगम में कर दिया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया था। फिर इसे निरस्त करते हुए कौशलेंद्र विक्रम सिंह को पर्यटन विकास निगम में भेजा गया और तर्क दिया गया कि उन्हें शंकराचार्य की मूर्ति निर्माण जैसे राजनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट से जोड़ रखना था। सवाल उठता है कि कौशलेंद्र विक्रम सिंह मूर्ति कला में क्या इतने पारंगत हैं कि उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। वहीं लवानिया को जल निगम से हटाकर एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एमडी बना दिया गया। जल निगम और रोड विकास दोनों ही सरकार की प्राथमिकता हैं और सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबद्ध हैं। फिर भी एमपीआरडीसी बड़ा विभाग है।

...तो बढ़ेगा 100 करोड़ का राजस्व

मप्र के सबसे कमाऊ विभागों में से एक परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 15 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया। यही नहीं उसने पूरे वर्ष में रिकार्ड राजस्व भी कमाया। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभाग नया लक्ष्य बनाकर काम कर रहा है। इसके लिए विभाग नई गाइडलाइन बना रहा है। जिसके तहत प्रदेश में अधिक राजस्व कमाने के लिए रोड टैक्स और वाहन रजिस्ट्रेशन की दरें कम करने पर विचार कर रहा है।

गौरतलब है कि मप्र में रोड टैक्स तो महंगा है ही, वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी महंगा है। खासकर पड़ोसी राज्यों से मप्र में महंगी दरों पर गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं। इसका असर यह हो रहा है कि मप्र के लोग दूसरे राज्यों में अपने वाहन रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इससे प्रदेश को बड़ी राजस्व हानि हो रही है। इन तथ्यों को देखते हुए सरकार ने मप्र में भी रजिस्ट्रेशन की दरें कम करने की कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मप्र में वाहन रजिस्ट्रेशन की दर 8 प्रतिशत है। इस कारण यहां कम संख्या में वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं। खासकर परिवहन कार्यों में लगे वाहन दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कराए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर मप्र में भी गुजरात की तर्ज पर 5 प्रतिशत की दर से वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने की गाइडलाइन बनाई जा रही है। विभाग का कहना है कि इससे कम से कम 100 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। इसके अलावा परमिट की दरें भी कम की जाएंगी।

दरअसल मप्र में नेशनल परमिट वाली बस पर 700 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में यह टैक्स 200 रुपए प्रति सीट से कम है। विगत दिनों मंत्रालय में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में माल-यानों के कर का युक्तिकरण करने के लिए गठित समिति की बैठक हुई। इस बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह स्वीकार किया कि मप्र के बस ऑपरेटर और मालवाहक वाहनों के स्वामी प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करवा रहे हैं। स्वाभाविक है इससे मप्र के सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। पड़ोसी राज्य में नेशनल परमिट वाली यात्री बसों के आरटीओ टैक्स का अध्ययन करने के बाद अब मप्र में नेशनल परमिट की बसों में मासिक कर प्रति सीट 700 रुपए के स्थान पर 200 रुपए प्रति सीट करने का निर्णय लिया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कंडम वाहनों पर बकाया मोटरयान कर की वसूली के लिए 31 मार्च 2021 तक दी गई छूट को फिर से बढ़ाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। बकाया राशि की वसूली हेतु सरल समाधान योजना बनाई गई है, जिसमें 5 से 10 साल पुराने वाहनों पर 40 फीसदी, 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर 50 तथा 15 साल पुराने वाहनों पर 70 फीसदी और 20 साल पुराने वाहनों पर 90 फीसदी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना से परिवहन विभाग के बकाया खातों की राशि में कमी आएगी और शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर मोटरयान कर की बकाया वसूली हेतु सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के तहत निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना है। इन वाहनों पर विज्ञापन शुल्क अधिरोपित करने से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

पहले मप्र का व्यक्ति यदि किसी अन्य राज्य में जाता था और उसका चालान कट जाता था तो मप्र में उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। अब यदि मप्र का व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर नियम तोड़ता है और उसका चालान कटता है तो मप्र के सभी आरटीओ को भी उसकी जानकारी प्राप्त होगी। इसी तरह यदि किसी भी राज्य से लाइसेंस सस्पेंड किया तो फिर यह पूरे देश के लिए सस्पेंड हो जाएगा। पहले इस तरह की कार्यवाही नहीं हो पाती थी। इसी तरह परिवहन विभाग ने कई ऐसे नवाचार किए हैं, जिससे जनता को लाभ मिलेगा ही, साथ ही इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचार का ही प्रतिफल है कि आज विभाग राजस्व कमाई का बड़ा केंद्र बना है।

● **सुनील सिंह**

आरटीओ का 90 प्रतिशत काम डिजिटल

मार्च अंत से मप्र में आरटीओ की 90 प्रतिशत व्यवस्था वाहन पोर्टल पर शिफ्ट हो चुकी है। देश के अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू हो रही है और परिवहन विभाग के प्रयास हैं कि देशभर के आरटीओ एक ही पोर्टल पर आ जाएं और सभी काम इसी पोर्टल के माध्यम से करें। इस पोर्टल की वजह से न सिर्फ लोगों को फायदा होगा, अधिकारियों का भी लोड कम होगा। पोर्टल पर काम शुरू होने के बाद अब आरटीओ का 90 प्रतिशत काम डिजिटल हो चुका है। अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन और अन्य काम वाहन पोर्टल पर ही होंगे। फिटनेस, परमिट जैसे काम भी वाहन पोर्टल पर ही होंगे। आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि पहले रोज सैकड़ों लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आते थे। अब एक भी व्यक्ति आपको यहां लर्निंग लाइसेंस के लिए नहीं दिखेगा। सभी अपने घर या अन्य जगहों से ऑनलाइन लाइसेंस निकाल लेते हैं। इससे हमारा भी बहुत काम कम हुआ है। फाइनल ट्रायल के लिए लोग यहां पर आते हैं और इसके बाद लाइसेंस भी उन्हें घर पर ही मिल जाता है। अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द मप्र के लोग दूसरे राज्यों में जाकर भी अपना वाहन बेच सकेंगे और उन्हें मप्र के आरटीओ में नहीं आना पड़ेगा। यह सुविधा उन्हें ही मिलेगी जिसमें बेचने वाला और खरीदार दोनों ही मप्र के होंगे। वे दोनों जिस भी राज्य में होंगे वहां से वाहन को बेचने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकेंगे। दोनों का आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। वाहन पोर्टल से दोनों के पास ओटीपी आएंगे और दोनों गाड़ी को खरीदने-बेचने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसके सभी कागज ऑनलाइन ही डाउनलोड होंगे और फिर ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। इसके लिए विभाग ने प्रपोजल भेज दिया है। बहुत जल्द यह सुविधा शुरू होने वाली है।

मप्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ सत्ता चाहती हैं। इसलिए दोनों पार्टियों की कोशिश है कि हर वर्ग को किसी न किसी तरह साधा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां सरकारी योजनाओं में हर वर्ग को महत्व दे रहे हैं, वहीं भाजपा हर जाति के घर पर पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस ने भी ओबीसी, एससी-एसटी के साथ ही अन्य वर्गों को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर दी है।

जातियों के भरोसे जीत

मप्र में 6 महीने बाद यानी अक्टूबर में चुनावी बिगुल बज जाएगा। इसको देखते हुए भाजपा-कांग्रेस के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटबंदी तेज कर दी है। प्रदेश में यह बात तो तय है कि भाजपा और कांग्रेस में से कोई एक पार्टी ही सरकार बनाएगी। ऐसे में दोनों पार्टियां इस कवायद में जुट गई हैं कि अधिक से अधिक सीटें कैसे जीती जाएं। इसके लिए फिलहाल दोनों पार्टियों का फोकस जातियों को साधने पर है। दोनों पार्टियां एक ही रणनीति पर काम कर रही हैं और इनका मंत्र है कि जातियों को साधो, सत्ता का सेहरा बांधो। अपनी रणनीति के तहत दोनों पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटी हुई हैं, यानी क्षेत्रवार, जातिवार नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। यानी नेताओं को अपनी-अपनी जाति को साधने की जिम्मेदारी दी जा रही है।

गौरतलब है कि मप्र की राजनीति में बिहार और उप्र की तरह जातिवाद भले ही हावी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से यहां जातियों का थोकबंद वोट पड़ने लगा है। इसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जाति को चुनावी राजनीति का आधार बना लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों ने जातिगत वोटों का समीकरण तैयार कर टिकट वितरण का भी फॉर्मूला बनाया है। वैसे विधानसभा चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों के टिकटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस बार चुनावी मैदान में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश में हैं जिसके सहारे सत्ता पर उसका कब्जा हो सके। विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बड़े स्तर पर सर्वे करा रही हैं। सत्तारूढ़ दल होने के चलते भाजपा में टिकट के दावेदारों की संख्या सबसे अधिक है और इस लिहाज से पार्टी में टिकटों की मारामारी भी सबसे अधिक है। टिकट के दावेदारों की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए भाजपा में कई स्तरों पर सर्वे का काम चल रहा है। पहला और महत्वपूर्ण सर्वे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है जिसमें प्रदेश में भाजपा की जमीनी हकीकत जानने के साथ चुनाव में जीत की संभावनाओं को टटोलने का काम किया जा रहा है। गुजरात से जुड़ी एक एजेंसी इस पूरे सर्वे के काम को बड़ी गोपनीय तरीके से अंजाम दे रही है। सर्वे में पार्टी हाईकमान प्रदेश की मौजूदा सरकार और संगठन के कामकाज और उसकी लोकप्रियता को लेकर भी जनता का फीडबैक ले रहा है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे की रिपोर्ट पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ चुनाव से पहले बड़े जरूरी बदलाव करेगा। वहीं भाजपा में दूसरा महत्वपूर्ण सर्वे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अपने स्तर पर करा रहा है। इस सर्वे के जरिए प्रदेश में पार्टी के मौजूदा हालात और लोगों के बीच सरकार की योजनाओं के फीडबैक को देखा जा रहा है। सर्वे में पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की मौजूदा स्थिति का आंकलन कर सीधे रिपोर्ट सरकार और संगठन को सौंपी जा रही है। बताया जा रहा है कि सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लगातार पार्टी के विधायकों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ पार्टी संगठन इन सर्वे से मिलने वाले रिपोर्ट के आधार पर ही संगठन को मजबूत करने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है।

मप्र की राजनीति में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग ऐसा है जिनका वोट जिस पार्टी को मिल जाता है उसकी सरकार बननी तय है।

भाजपा ने हर समाज को साधा

भाजपा ने प्रदेश में लगभग हर समाज को साधने की कोशिश की है। इसके लिए बोर्ड बनाए गए हैं। तैलिक समाज की 50 लाख आबादी को साधने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। सोनी समाज की 27 लाख आबादी का विदिशा की शमशाबाद, जबलपुर, पन्ना की पवई, सतना की मैहर व अमरपाटन विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव को देखते हुए सोनी समाज के आराध्य देव महाराज अजमीढ़देवजी की मूर्ति भोपाल में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। विश्वकर्मा समाज की 45 लाख आबादी को साधने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पारंपरिक और स्किल्ड प्रोफेशन में लगे लोगों को इसके जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। मप्र में 2013 में ये भाजपा के साथ था, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने इस वोट बैंक में सेंध लगा दी थी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा। विश्वकर्मा समाज के कल्याण के लिए योजनाएं भी बनाई जाएंगी। वहीं मिट्टी शिल्प कला में निखार लाने के लिए वर्ष 2008 में सरकार ने माटी कला बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन इसका लाभ प्रजापति समाज को नहीं मिला।

इसलिए भाजपा-कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस वोटबैंक पर नजर गड़ाए रहती है। भाजपा ने तो 2020 में सत्ता में आने के बाद से ही दलित, आदिवासी, ओबीसी को साधने की कवायद शुरू कर दी थी। पार्टी ने इस दौरान सबसे अधिक आदिवासी वर्ग पर फोकस किया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज आदिवासियों का बड़ा वर्ग भाजपा को अपना हितैषी मान रहा है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासी बहुल जिलों से यात्रा निकालकर इस वर्ग पर अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। इन दोनों पार्टियों के अलावा अन्य पार्टियां भी इस बड़े वोटबैंक को साधने में जुटी हुई हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 1.13 करोड़ से अधिक है। ये प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। इसमें भी जाटव, मोची, सतनामी की आबादी 47 प्रतिशत से अधिक है। इंदौर, उज्जैन व सागर जिले में 5 लाख से अधिक आबादी एससी की है। मुरैना व छतरपुर में 4 लाख से अधिक आबादी है। उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़ में कुल आबादी की 25 प्रतिशत आबादी एससी वर्ग से आती है। शाजापुर, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल व शहडोल में भी एससी वाले किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने की कूवत रखते हैं।

प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। इसमें 2018 में भाजपा 16 सीट ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने जयस के साथ मिलकर 30 सीटें जीत ली थीं। आदिवासी सीटों के परिणाम ने ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। प्रदेश में 47 सीटों के अलावा 4 सामान्य देवसर, परासिया, आमला, महेश्वर विधानसभाओं में भी आदिवासी वोटरों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में आदिवासियों की राजनीति जहां महाकौशल में गोंगपा करती है। वहीं मालवा-निमाड़ में ये कमान जयस ने संभाल रखी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो महीने पहले सतना आए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा आने वाले हैं। प्रधानमंत्री पंचायत राज कार्यक्रम और 6 हजार करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन की बाणसागर समूह जल प्रदाय परियोजना फेस-2

का शुभारंभ करेंगे। इस क्षेत्र में बड़े नेताओं के दौरों से चर्चा है कि विंध्य क्षेत्र में केंद्रीय नेतृत्व को भी उथल-पुथल का डर है। 2018 में विंध्य की 30 सीटों में से 25 सीटें भाजपा ने जीती हैं। इसके बाद भी क्षेत्र की उपेक्षा के कारण लोगों में नाराजगी है। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने भी भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने महापौर का चुनाव जीता है। रीवा और सतना में भी पार्टी का प्रसार बढ़ रहा है।

2023 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों का बड़ा रोल होगा। चुनाव के कई महीनों पहले से ही छोटे दल एकजुट होकर भाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। आम आदमी पार्टी गुजरात में चमत्कारिक रूप से सभी को चौंका चुकी है। उसकी नजर अब मप्र पर है। इस विधानसभा चुनाव में दलित, आदिवासी और ओबीसी का गठजोड़ बनाकर छोटे दल बड़ा मैदान मारने की जुगत में हैं। सपा भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। गठबंधन ने आकार लिया तो महाकौशल की 46, बुंदेलखंड की 26, ग्वालियर-चंबल और विंध्य की 22-22 सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। ये ऐसी संख्या है, जो मप्र में किसी भी दल को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए जरूरी है। भीम आर्मी की राजनीतिक शाखा आजाद समाज पार्टी ने बीती 12 फरवरी को राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में पहली बार अपनी ताकत दिखाई थी। तब उसकी सभा में एक लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। भीम आर्मी के इस कार्यक्रम में जय युवा आदिवासी संगठन (जयस), ओबीसी महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी शामिल हुए थे। सभा में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मप्र की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। भीम आर्मी की नजर प्रदेश की 35 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों पर है। भोपाल रैली में भीम आर्मी ने जिस तरह से बिना किसी संगठन और विशेष संसाधन के भीड़ जुटाई थी, उससे पार्टी का उत्साह चरम पर है। भीम पार्टी की 35 रिजर्व सीटों के अलावा सामान्य वर्ग की 19 सीटों गोटेगांव, बीना, गुन्नौर, तराना, रैगांव, आष्टा, जतारा, सांवेर, नारावाली, भांडेर, चंडला, गोहद, सोनकच्छ, अशोकनगर, करेरा, अंबाह, बरासिया, आलोट, मल्हारगंज पर भी नजर है। यहां एससी वोटरों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है। ये किसी भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। मप्र बंटवारे से पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों में एक मजबूत आधार रखती थी। अब भी महाकौशल और बुंदेलखंड की 46 सीटों पर इसका जनाधार है। पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 1.8 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा और कांग्रेस के बीच रहे 0.1 प्रतिशत के अंतर से ये अधिक है।

● **कुमार विनोद**

52 फीसदी आबादी पर कांग्रेस का फोकस

मप्र में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग ही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय करने के लिए अब कांग्रेस ने जातिगत समीकरण साधने की योजना बनाई है। इसके तहत कांग्रेस अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जाति के सम्मेलन करने की रणनीति पर अमल करने जा रही है। इन सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को कांग्रेस के पक्ष में लाने का प्रयास करेगी। दरअसल, हाल ही में पार्टी के विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठ की बैठक में यह बात उठी थी कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर कुछ जातियों के लोगों को ही महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से अन्य जातियों के लोगों को महत्व नहीं मिल पाता है। इसके बाद अब पार्टी ने ओबीसी की सभी जातियों को साधने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले ओबीसी को साधने के लिए कांग्रेस अब जिलेवार सामाजिक सम्मेलन करेगी। इसमें वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग क्षेत्र दिए जाएंगे। सम्मेलनों में भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ किए जा रहे अन्याय को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। साथ ही 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की मांग करके फिर इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी है।

आदर्श गृह निर्माण समिति का जंजाल

पहले दिए गए थे नोटिस, फिर दर्ज कराया प्रकरण

जेआर व प्रभारी उपायुक्त सहकारिता विनोद सिंह ने बताया कि आदर्श गृह निर्माण समिति की 12 एकड़ जमीन है। यहां पर पुराने सदस्यों को प्लाट नहीं दिए गए हैं। जबकि नए सदस्यों को ऊंचे दामों पर प्लाट बेच दिए गए हैं। यही नहीं ईडब्ल्यूएस की जगह पर डुप्लेक्स बने हुए मिले हैं। खुले क्षेत्र को खत्म कर दिया गया है। इसके पहले संस्था को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी न तो संचालक सामने आए और न ही दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। इसे देखते हुए पिछले दिनों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडल के साथ ही अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमने समिति का रिकार्ड जब्त करने की कार्रवाई की है, इसे जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। बता दें कि आदर्श गृह निर्माण समिति में हुई गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद से ही सहकारिता विभाग का अमला लगातार रिकार्ड जब्त करने की कार्रवाई कर रहा था, लेकिन संचालक बताए गए पते पर नहीं मिल रहे थे। जो मिल भी रहे थे तो रिकार्ड देने में आनाकानी कर रहे थे।

म प्र में गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं किस तरह लोगों को आशियाने का सपना दिखाकर ठग रही हैं, इसका ताजा उदाहरण आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था के घपले में सामने आया है। संस्था के कर्ताधर्ताओं ने सहकारिता विभाग के अफसरों के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को चपत लगाई है। हालांकि सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था का रिकार्ड जब्त करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। अब इस रिकार्ड को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। इससे पहले पुलिस द्वारा समिति में गड़बड़ी करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकों व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। दरअसल गृह निर्माण समिति की जमीन पर कोरल लाइफ नाम की कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया है। यहां ईडब्ल्यूएस की जगह पर डुप्लेक्स बना दिए गए हैं। बंधक प्लाट पर भी डुप्लेक्स बने हुए हैं। खुले क्षेत्र पर भी मकान बना दिए गए हैं। समिति के 750 सदस्यों में से एक को भी प्लाट नहीं मिला है। कारण यह है कि समिति के पदाधिकारियों ने जमीन इंदौर के किसी बिल्डर को बेच दी और बिल्डर ने यहां अपनी मर्जी के अनुसार कॉलोनी विकसित कर दी है।

सहकारिता उपायुक्त विनोद सिंह ने विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त अरविंद सिंह सेंगर सहित 45 लोगों के खिलाफ थाना निशातपुरा में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें कोरल लाइफ कॉलोनी विकसित करने वाली आदर्श गृह निर्माण समिति में हुई गड़बड़ियों के लिए समिति के पदाधिकारियों और अनय के साथ सेंगर को भी आरोपित बनाया गया है। सहकारिता विभाग की जांच में 165 रजिस्ट्रियां सामने आई हैं। इसका रजिस्ट्री मूल्य 11.82 करोड़ और बाजार मूल्य 13.54 रुपये हैं, इसमें चेक और नकद से 11.77 करोड़ प्राप्त किए गए हैं। रजिस्ट्री से हुई आय में से 3.37 करोड़ रुपए बैंक खाते की बजाय इधर-उधर करने के साथ ही यहां विकास सहित अन्य कार्य करने वालों को दे दिए गए हैं। इसके अलावा लोगों को भ्रमित करने के लिए नाम भी आदर्श नगर से बदलकर कोरल लाइफ कॉलोनी कर दिया गया है।

राजधानी के थाना निशातपुरा में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनमें राकेश कुमार उपाध्याय, केशव कुमार नाचानी, अब्दुल लतीफ, अरविंद सिंह सेंगर, वसीम मियां, शहजाद खान, अब्दुल सलीम खान, अब्दुल जलील खान, अजीम बक्श, हफीजुद्दीन, अब्दुल अजीज, जहीर बक्श, सरंत जहां, छोटी बाई, अशोक मिश्रा, (तत्कालीन संचालक मंडल समस्त) शमी खान, मनीषा साहू, रामप्रकाश, मजहर खान, संजय गुप्ता, आनंदी सिंह, चंदप्रकाश दांगी, उधम साहू, श्रीमाया नामदेव, नवीन रघुवंशी (वर्तमान अध्यक्ष एवं संचालक मंडल समस्त) तथा संस्था के खाते से जिनके खाते में पैसा अंतरित हुआ है उन लोगों क्रमशः जी नेक्स्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर्स, राकेश कुमार उपाध्याय, राधा उपाध्याय, बालाजी कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स के भागीदार, शुभ कंस्ट्रक्शन के भागीदार, रामनारायण शुक्ला, अनिल चौधरी, सुनील चौधरी, तारिक रशीद. आशु कंस्ट्रक्शन के भागीदार, हजीरा इंटरप्राइजेज के भागीदार, अल्फेज कंस्ट्रक्शन के भागीदार, एसके कंस्ट्रक्शन के भागीदार, एमके मेटल के भागीदार, अमन ट्रेडर्स के भागीदार, आरएस फ्लोर के भागीदार, तैयबा डेयरी फार्म के भागीदार, अकबर अली, आरएस कंस्ट्रक्शन, नवदी कंस्ट्रक्शन के भागीदार, प्रोपराइटर्स एवं अन्य शामिल हैं। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 415, 419, 420, 409, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता 1860 का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा कुल रकबा 12.08 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 27.04.2000 को क्रय की गई। वर्ष 2002 की स्थिति में सोसायटी के सदस्यों की कुल संख्या 785 थी, जिसमें से 500 सदस्य भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित थे। तद्समय भूमि के संबंध में शासकीय अनुमतियां प्राप्त कर 340 भूखंड सदस्यों को आवंटित कर दिया गया था, जो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 6994/2002 से प्रमाणित होता है। इसके पश्चात लंबे समय तक सदस्यों को यह गुमराह किया जाता रहा कि प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है तथा उन्हें रजिस्ट्रियां नहीं की गईं। जब अधिकांश सदस्य थक-हार गए तब वर्ष 2018-19 में तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने राकेश कुमार उपाध्याय निवासी भोपाल भूमाफिया एवं केशव कुमार नाचानी निवासी इंदौर भूमाफिया से मिलीभगत कर षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित योजना के आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के स्थान पर कॉलोनी का नाम कोरल लाइफ बदलकर शासकीय अनुमतियां प्राप्त कर आधा अधूरा विकास कार्य कर विकास कार्य पूर्ण होने से पहले ही ये व्यक्तियों को उनकी रजिस्ट्रियों में फर्जी सदस्यता क्रमांक-953 से 1243 तक दर्शाते हुए मनमाने मूल्य पर प्राप्त कर रजिस्ट्रियां करा दी गई। जबकि संस्था में वर्ष 2017-18 की स्थिति में 784 सदस्य थे फिर भी मनमाने तौर पर सदस्यों का निष्कासन कर दिया गया तथा नवीन सदस्यता क्रमांक दर्शित करते हुए नवीन व्यक्तियों की रजिस्ट्रियां करा दी गई।

● **सिद्धार्थ पांडे**

हजारों को मिलेगा जमीन पर पट्टा!

चुनावी साल में सरकार प्रदेश में हर जाति और वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सरकारी जमीनों पर 2020 से काबिज लोगों को सरकार पट्टा देने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम से हजारों लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि सरकार पूर्व में इसकी घोषणा कर चुकी है।

मप्र में सरकारी जमीन पर काबिज हजारों लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक जल्द मिलेगा। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। अभी तक केवल वर्ष 2014 तक के कब्जाधारक पट्टे के लिए पात्र थे अब इसे बढ़ाकर 2020 किया जा रहा है। इससे प्रदेश के लाखों आमजन लाभांवित होंगे। शासकीय भूमि का पट्टा मिलने के बाद प्रदेश के इन पट्टाधारकों को भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रदेश में पुनः शुरू होने पर इस योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इससे निशुल्क पट्टा और पीएम आवास में राशि मिल सकेगी। इसके लिए बिजली बिल, जल प्रदाय बिल, किसी सरकारी दफ्तर का कोई पत्र या दस्तावेज, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता संपत्ति कर, मतदाता सूची में नाम आदि के दस्तावेज देने होंगे।

प्रदेश में शासकीय जमीन पर काबिज गरीब आवासहीनों को निशुल्क पट्टा देकर जमीन का मालिकाना हक देने के लिए मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 बना हुआ है। इसमें अभी तक केवल 31 दिसंबर 2014 तक के काबिज ही पात्र माने गए हैं। इस अवधि के बाद शासकीय जमीन पर रहने वालों को कोई पट्टा नहीं दिया गया है और फिलहाल वे अतिक्रमणकारी की श्रेणी में आते हैं। अब सरकार इस अधिनियम में पात्रता की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने जा रही है। यानि इस अवधि तक शासकीय भूमि पर काबिज गरीब भूमिहीन, आवासहीन व्यक्तियों को सरकार जमीन का निशुल्क पट्टा जारी कर उन्हें उस जमीन का मालिक बनाएगी। अधिनियम की मंजूरी मिलने के बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारी पटवारी, राजस्व निरीक्षकों का दल शहरी क्षेत्रों में ऐसे शासकीय भूमि पर काबिज लोगों का सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद सूची तैयार की जाएगी। जो पात्रता की श्रेणी में आएंगे उनका विभिन्न स्तर पर परीक्षण कराए जाने के बाद उन्हें शासकीय जमीन का पट्टा दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार दिसंबर 2014 के अनुसार करीब 30 हजार परिवारों को फायदा मिलता, अब नए नियम के मुताबिक इसका लाभ 90 हजार परिवार उठा सकेंगे। इसके साथ ही अब तक करीब 9 हजार 560 परिवारों ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है। जिसमें 2 हजार 453 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा चुका है। शेष तीन हजार आवेदनों की जांच की जा रही है। सरकार ने सरकारी जमीन पर काबिज परिवारों को 4 रुपए प्रति वर्गमीटर सालाना भू-भाटक पर जमीन की लीज देना पड़ेगी। जिसके तहत एक हजार वर्गफीट के मकान का सिर्फ चार सौ रुपए लीज रेंट सालाना जमा करना पड़ेगा। ऐसी जमीनें जो पहले से सरकारी थीं, वहां पर काबिज लोगों को वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन के रेट से 5 फीसदी प्रीमियम देना पड़ता था, जिसे घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है। धारण अधिकार के तहत वर्ष 1989 से 31 दिसंबर 2014 तक 25 साल रहने का प्रूफ पेश करना पड़ रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2020 कर दिया है। जिसके तहत वर्ष 2020 तक काबिज होने का वेरिफिकेशन गूगल मैप से किया जाएगा, जिससे पता लगाया जा सके कि 2020 तक यहां पर मकान बना था या नहीं। नगरीय क्षेत्र की सरकारी भूमि पर जो लोग 31 दिसंबर 2020 या उससे पूर्व रह रहे हैं, वे वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन की दर से एक प्रतिशत प्रीमियम चुकाकर पट्टा ले सकेंगे। ऐसे लोग 31 जुलाई 2023 में आवेदन कर सकते हैं।

जिस अधिनियम के तहत सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाएगा उसमें पहले से प्रदेश में कहीं जमीन, भवन होने की जानकारी छुपाते हुए खुद को भूमिहीन या आवासहीन बताकर योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को 7 साल की कैद का प्रावधान भी है। इस अधिनियम में पट्टे की जमीन को बेचकर दूसरी बार योजना का लाभ लेने, पट्टे पर प्राप्त जमीन को किराए पर देने, योजना के तहत पट्टा पाने वाले व्यक्ति की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर जमीन हथियाने वाले व्यक्ति को भी 7 साल की सजा का प्रावधान है। एक परिवार को पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

कहां कितनी जमीन का पट्टा

नगर निगम क्षेत्र में शासकीय जमीन पर काबिज आवासहीन, भूमिहीन व्यक्तियों को 45 वर्गमीटर यानि 450 वर्गफीट जमीन का पट्टा जारी किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र के आवासहीन, भूमिहीनों को 60 वर्गफीट और नगर परिषद क्षेत्र में काबिज लोगों को 80 वर्गमीटर जमीन का पट्टा दिया जाएगा। यह पट्टा केवल 31 दिसंबर 2014 के बाद से 21 दिसंबर 2020 के बीच की अवधि में सरकारी जमीन के कब्जाधारी होना चाहिए। एक परिवार के कब्जे में इससे अधिक जमीन होगी तो उन्हें इस पात्रता सीमा तक ही पट्टा दिया जाएगा। आवासीय पट्टा के लिए 150-200 वर्गमीटर तक एक प्रतिशत भू-भाटक देना होगा। कमर्शियल पट्टा के लिए 20 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 5 प्रतिशत भू-भाटक चुकाना होगा। पहले यह 25 प्रतिशत था।

मुफ्त बिजली ने बनाया कर्जदार

मप्र देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है। इसके बावजूद यहां के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक बिजली मिलती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों पर 48 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है। यह कर्ज मुफ्त की बिजली यानी संबल योजना के कारण बढ़ा है। मप्र ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की स्थिति यही है। पावर मिनिस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि 36 में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 1.32 लाख करोड़ रुपए देशभर में अकेले 2020-21 वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए हैं। मप्र, राजस्थान और कर्नाटक ने 36.4 प्रतिशत या 48,248 करोड़ की सबसे ज्यादा बिजली सब्सिडी दी। तीन साल के डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि दिल्ली ने 2018-19 और 2020-21 के बीच अपने सब्सिडी एक्सपेंडिचर में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी। ये 2018-19 में 1,699 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 3,149 करोड़ रुपए हो गई। ये सभी राज्यों में दूसरी सबसे अधिक है। मणिपुर ने इन तीन वर्षों में बिजली सब्सिडी में सबसे बड़ी 124 प्रतिशत की उछाल देखी गई। 120 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 269 करोड़ पर पहुंच गई।

मप्र की बात करें तो यहां 2018 के चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने संबल योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत संबल बिल माफी ने मप्र की तीनों बिजली वितरण कंपनियों का कर्ज अरबों रुपए बढ़ा दिया है। राज्य को मौजूदा वित्तीय वर्ष का ही 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिजली कंपनियों को देना है। यह राशि ऊर्जा विभाग की उन तमाम विभिन्न जनहित की योजनाओं की है, जिस पर सरकार लोगों को सब्सिडी देती है। उधर, बिजली कंपनियों का कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी भरपाई के लिए कंपनियां उपभोक्ताओं पर भार डाल रही हैं। उधर, हर साल मप्र में 20 से 25 हजार करोड़ से अधिक की बिजली खरीदी हो रही है। वर्ष 2021-22 में ही 27 हजार 500 करोड़ से अधिक राशि खरीदी पर इस्तेमाल हुई है। इसी तरह हर साल फिक्स चार्ज के रूप में भी मप्र 4000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र की कंपनियों को दे रहा है, जिनके साथ 25 वर्ष का एग्रीमेंट है। इनमें लैंको अमरकंटक, टोरेंट पॉवर गुजरात, बीना पॉवर, बीएलए पॉवर, सासन, एमबी पॉवर, जयप्रकाश निगरी टीपीएस और झाबुआ पॉवर हैं।

जानकारी के अनुसार सरकार ने जो संबल योजना शुरू की है उसके कारण बिजली कंपनियों पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। सरकार द्वारा इसकी भरपाई होनी थी, लेकिन मप्र सरकार ने अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए नहीं दिए। बिजली मामलों के जानकार व रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि कर्ज बढ़ने की यह बड़ी वजह थी। सरकार इसकी भरपाई करती तो उपभोक्ताओं पर भार कम होता। अग्रवाल ने बिजली कंपनियों के टैरिफ प्रस्तावों पर कहा कि वे 3 प्रतिशत प्रति यूनिट दर बढ़ाना चाहती हैं, जबकि बड़े कर्जों को छोड़ भी दिया जाए तो आज की तारीख में कंपनियां करीब 5 हजार करोड़ के फायदे में हैं। उन्हें तो 10 प्रतिशत तक राशि कम करना चाहिए। बहरहाल, कर्जों की बात है तो 2017-18 से लेकर 2021-22 तक कंपनियों पर कर्ज 11625 करोड़ बढ़ा है। कुल कर्ज अब 48 हजार करोड़ से अधिक है। यह नाबार्ड, आरईसी व अन्य वित्तीय कंपनियों का पैसा है। कर्ज की यह जानकारी सरकार ने विधानसभा को दी है।

राज्य सरकार ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित लोकहित की योजनाओं के जरिए लोगों को राहत देती है। पिछली कमलनाथ सरकार ने अगस्त 2019 से इंदिरा गृह ज्योति योजना का विस्तार करते हुए इसका लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देना शुरू किया था। हालांकि बाद में शिवराज सरकार ने इसे सिर्फ बीपीएल तक सीमित कर दिया। इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वित्तीय वर्षों की राज्य सरकार पर 3016 करोड़ की सब्सिडी बकाया है। वहीं साल 2019 में सरकार को 17506 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी थी। जिसमें से 13870 करोड़ की देनदारी देने के बाद 3636 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना बाकी है।

भले ही बिजली कंपनियों पर सरकार की देनदारी हो, लेकिन इसके बाद भी बिजली कंपनियों पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार पहले ही बिजली कंपनियों का 26055 करोड़ रुपए कर ओढ़ चुकी है। इसके बाद भी बिजली कंपनियां लगातार घाटे में हैं। आंकड़ों को देखें तो मप्र में बिजली कंपनियों का घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। साल 2014-15 में 5156.88 करोड़ रुपए का घाटा, साल 2015-16 में 7156. 94 करोड़ रुपए का घाटा, साल 2016-17 में 7247.55 करोड़ रुपए का घाटा, साल 2017-18 में 5327.54 करोड़ रुपए का घाटा, साल 2018-19 में 7053 करोड़ रुपए का घाटा बिजली कंपनियों को हुआ है।

● **जितेंद्र तिवारी**

बिजली चोरी पर लगे रोक तो बचेंगे 2 हजार करोड़

बिजली कंपनियों ने घाटे को कम करने के लिए इसका भार एक बार फिर जनता पर डाल दिया है। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को पिछले दिनों बिजली की दरें घटाने की मांग की थी। जिसके बाद 1.98 फीसदी रेट बढ़ा भी दिए गए हैं। लेकिन एक बात और सामने आई है कि अगर बिजली चोरी रोक ली जाए तो करीब 2000 करोड़ की बचत हो सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का सबसे ज्यादा लाइन लॉस प्रदेश की तीनों पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दरें बढ़ाने की मप्र ऊर्जा नियामक आयोग को जो याचिका सौंपी है, उसमें बिजली चोरी की बात स्वीकार की गई है। कंपनियों का कहना है कि 28 फीसदी बिजली चोरी होने से उसे 2 हजार करोड़ का नुकसान होता है। सबसे ज्यादा लाइन लॉस 36.67 फीसदी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाइन लॉस 30.87 फीसदी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाइन लॉस 16.65 फीसदी है। बिजली कंपनियां सालों बाद भी लाइन लॉस को 15 फीसदी तक नहीं ला सकीं हैं।

33 लाख आबादी की बुझेगी प्यास

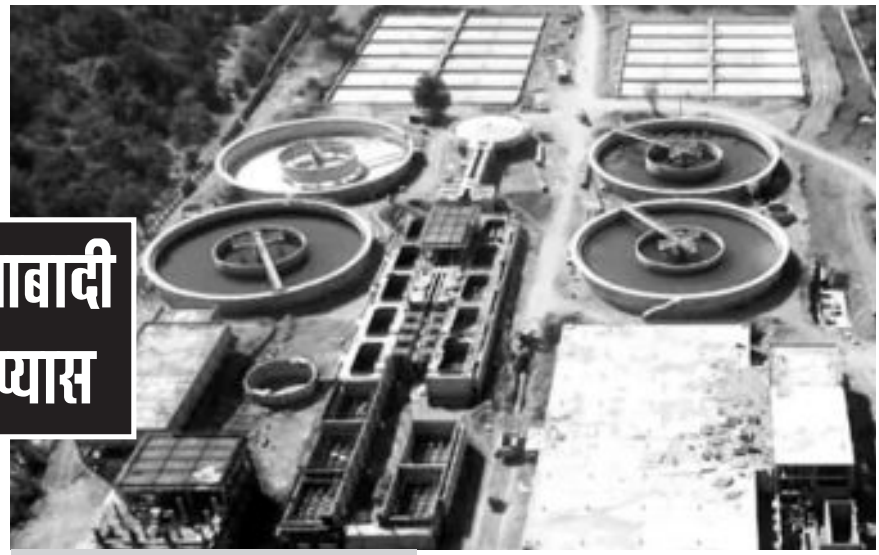

सतना और रीवा जिले को पूरी तरह से पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने 6000 करोड़ रुपए की बाणसागर और टमस समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। योजना के जरिए 33.90 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत सतना जिले के 785 गांवों को और रीवा जिले के 2251 गांवों को घर-घर पेयजल सप्लाई किया जाएगा। इस योजना में रीवा जिला पूरी तरह कवर हो जाएगा तो सतना जिले के शेष तीन ब्लॉक भी कवर होंगे जिसके बाद पूरा सतना जिला इस योजना से कवर हो जाएगा। इस योजना के पूरे होने के बाद लोगों को पेयजल संकट से पूरी तरह निजात मिल जाएगी और घर पर बारहों महीनें टोंटी के जरिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

6000 करोड़ की यह योजना जल जीवन मिशन के तहत जल निगम पूरा करेगा। यह योजना तीन हिस्सों में है। पहला हिस्सा सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना फेज-2 होगी, जो 2319 करोड़ की होगी। इसमें सतना जिले के 785 और रीवा जिले के 210 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाएगा। दूसरा हिस्सा 2319 करोड़ की रीवा बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना है। इसमें रीवा जिले के 1411 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाएगा। तीसरा हिस्सा 951 करोड़ रुपए की टमस ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना है। इसमें रीवा जिले के 630 गांवों को पेयजल पहुंचाया जाएगा।

सतना बाणसागर फेज-1 में सतना जिले के सोहावल, मझगवां और नागौद विकास खंड छूट गए थे। फेज-2 में इन्हें शामिल कर लिया गया है। इसमें कुल 995 गांवों को पेयजल दिया जाएगा। जिसमें सोहावल के 238 गांव, मझगवां के 304 और नागौद के 243 गांवों सहित रीवा विकासखंड के 88 और सिरमौर के 122 गांव शामिल किए गए हैं। इससे 12.37 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट का ठेकेदार केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड कोलकाता है। दो साल में प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसका इंटेक वेल सतना जिले के रामनगर विकासखंड के झिन्ना गांव में बनाया जाएगा। पेयजल सप्लाई के लिए 3527 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें 16,323 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 291 टंकिया बनाई जाएंगी।

रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय परियोजना में कुल 1411 गांवों को पेयजल दिया जाएगा। जिसमें विकासखंड गंगेव के 183 गांव, रायपुर कर्चुलियान के 242, रीवा के 107, सिरमौर के 122, मऊगंज के 284, हनुमना के 293 और नई गढ़ी विकासखंड के 180 गांव शामिल किए गए हैं। इससे 14.47 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट का ठेकेदार दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड एंड स्काईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। दो साल में प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसका इंटेक वेल सतना जिले के रामनगर विकासखंड के झिन्ना गांव में बनाया जाएगा। पेयजल सप्लाई के लिए 4067 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें 1.29 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 392 टंकिया बनाई जाएंगी।

टमस ग्रामीण समूह जल प्रदाय परियोजना में कुल 630 गांवों को पेयजल दिया जाएगा। जिसमें नईगढ़ी विकासखंड के 66 गांव, जवा 237, त्यौंथर 261 और गंगेव के 66 गांव शामिल किए गए हैं। इससे 7.04 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट का ठेकेदार एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद है। दो साल में प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसका इंटेक वेल रीवा जिले के जवा विकासखंड के भटिगवां गांव में बनाया जाएगा। पेयजल सप्लाई के लिए 1937 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें 1,31,715 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 197 टंकिया बनाई जाएंगी।

उधर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सतना जिले के स्वीकृत 220 ग्रामों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और शेष 1554 ग्रामों में जल निगम द्वारा हर घर नल जल पहुंचाने की महत्वकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत सतना जिले के 4 लाख 19 हजार 455 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जिनमें से अब तक 83 हजार 995 परिवार घरेलू नल कनेक्शन से युक्त हो चुके हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री रावेंद्र सिंह ने वर्ष 2022 में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर बताया कि सतना जिले के 5 विकासखंडों मैहर, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर तथा रामपुर बघेलान के 989 ग्रामों में सतना-बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना-1 के तहत 1135 करोड़ लागत की परियोजना का क्रियान्वयन जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

● **राजेश बोरकर**

जल प्रदाय योजना में भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत है

अब तक इस परियोजना में 41 हजार घरेलू कनेक्शन किए गए हैं। शेष तीन विकासखंड मझगवां, सोहावल एवं नागौद के 565 ग्रामों के लिए सतना-बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना फेज-2 में 2153 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसके टेंडर किए जा रहे हैं। सतना-बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना में भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत है। जिसके तहत बाणसागर मारकंडेय में इंटेकवेल, सुखबारी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड मेजर बैलेंसिंग रिजरवायर 90 से 96 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। योजना के तहत रामनगर के अलावा गोरसरी पहाड़ से सुरंग के जरिए पानी अन्य विकासखंडों के लिए ले जाया जाएगा। जिसके लिए 1500 मीटर लंबी सुरंग में 695 मीटर अर्थात् 38 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इसी प्रकार 7156 किलोमीटर पाइपलाइन में से 5800 किलोमीटर पूर्ण, 292 उच्च स्तरीय टंकियों में से 90 पूर्ण और 87 प्रगतिरत है। परियोजना को 31 दिसंबर 2023 में पूर्ण किया जाएगा। सुरंग बनने के पूर्व 233 ग्रामों में 51 हजार 736 क्रियाशील घरेलू कनेक्शन मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।

गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का देशभर में किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, इसका नजारा मप्र में देखा जा सकता है। यहां सरकार से मिलकर अस्पताल संचालक जमकर योजना में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वर्तमान समय में इंदौर का इंडेक्स अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों के साथ मिलकर इस अस्पताल ने सारे नियमों को ताक पर रखकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। आलम यह है कि घोटाला उजागर होने के बाद अस्पताल संचालक ने मंत्रालय से लेकर मंत्रियों तक के दर पर दस्तक दी। अंत में उन्हें अपनी ही बिरादरी का साथ मिला, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिली है।

आयुष्मान योजना

इलाज कम, घपले ज्यादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गरीब तबकों को बेहतर और निशुल्क इलाज मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। लेकिन इस योजना में घपले ज्यादा और इलाज कम हो रहे हैं। दरअसल, गरीबों के लिए सालाना 5 लाख रुपए इलाज वाली इस योजना में गड़बड़ी पहले दिन से ही शुरू हो गई। गरीबों की जगह रसूखदारों ने भी इस योजना में अपने आपको शामिल कर लिया। वहीं इस योजना में कड़े नियमों का प्रावधान नहीं होने के कारण अस्पतालों ने जमकर मनमानी की। आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध मप्र के 620 निजी अस्पतालों में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। करीब 200 करोड़ रुपए का यह घोटाला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के कई नामी निजी अस्पतालों में सामने आया है। मामले में भोपाल और जबलपुर के कुछ अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार कराई गई एक जांच में यह खुलासा हुआ है।

इसी कार्रवाई के बीच अब निजी अस्पतालों के संचालकों द्वारा बनाए गए यूनाईटेड हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 15 अप्रैल से आयुष्मान योजना के नए मरीजों का इलाज नहीं करने की बात कही है। ये स्थिति तब है जबकि आयुष्मान भारत योजना में इलाज कराने वाले मरीजों के इलाज पर खर्च होने वाली 75 फीसदी राशि प्राइवेट अस्पतालों के खातों में पहुंच रही है। लेकिन अस्पताल के संचालकों का आरोप है कि गलती कुछ अस्पताल कर रहे हैं जबकि मरीजों का इलाज करने पर हर अस्पताल का भुगतान रोका जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के एमओयू के तहत मरीज का इलाज करने के 30 दिन के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन 300-300 दिन बीतने के बाद मरीज के इलाज पर खर्च हुई राशि नहीं मिल रही है। ऐसे में मजबूरी में आर्थिक तंगी के कारण नए मरीजों का इलाज करने में कठिनाई खड़ी हो गई है। भोपाल संभाग के 200 से ज्यादा अस्पताल 15 अप्रैल से इलाज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास अस्पताल संचालन की राशि भी नहीं बची है। निजी अस्पतालों द्वारा जिन मरीजों का इलाज किया गया। उनके इलाज में खर्च हुई राशि करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। लेकिन राज्य सरकार ये बजट जारी

आयुष्मान भारत योजना से इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को किया बाहर

आयुष्मान योजना में शहर के कई अस्पतालों की भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की टीम जांच के लिए इंदौर आई थी। जांच में गड़बड़ी मिलने पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया है। दरअसल 5 मार्च को भोपाल से आई टीम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में जांच करने के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान यहां भारी गड़बड़ियां सामने आई थीं। यहां पिता के आयुष्मान कार्ड पर बच्चे का इलाज किया जा रहा था। साथ ही मामूली बुखार में ही कई लोगों को यहां 20 दिनों तक भर्ती रखा पाया गया। आयुष्मान भारत योजना में भारी गड़बड़ी मिलने पर योजना का संचालन करने वाले राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की योजना के अंतर्गत संबद्धता निलंबित कर दी है। निलंबन अवधि में अस्पताल योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार नहीं कर सकेगा। इंडेक्स के अलावा भी शहर के 6 अन्य अस्पतालों में प्राधिकरण की टीम ने जांच की थी। इन अस्पतालों में भी अनियमितताएं मिली थीं। यहां से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके बाद इनकी संबद्धता खत्म करने का निर्णय भी हो सकता है। जिन अस्पतालों के दस्तावेजों में धोखाधड़ी साबित होगी, उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में लगभग 500 मरीज पंजीकृत थे, जबकि मौके पर जांच दल को मौके पर 76 मरीज ही मिले।

नहीं कर रही है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी यदि किसी अस्पताल ने 50 मरीजों का इलाज किया है तो 10 मरीजों के इलाज का खर्च ही समय पर दिया जा रहा है। शेष खर्च को पेंडिंग कर दिया जाता है। इधर, आयुष्मान भारत की सीईओ का तर्क है कि 31 मार्च तक जिस निजी अस्पताल ने भी मरीजों का इलाज किया था उन सभी का भुगतान कर दिया गया है। प्रदेश के 70 अस्पताल जांच के दायरे में है। इसलिए उनका भुगतान रोका गया है। जिन अस्पतालों का भुगतान रोका जाता है, उसकी कोई न कोई कहानी होती है। ये अस्पताल के संचालकों को भी पता है।

जानकारी के अनुसार मप्र में 1037 निजी और सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसमें से 542 निजी अस्पताल हैं। जबकि 495 सरकारी अस्पताल हैं। रोजाना 4 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज इन अस्पतालों में हो रहा है। सरकार करीब 950 करोड़ रुपए मरीजों के इलाज पर खर्च कर रही है। 75 प्रतिशत राशि तो अकेले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों पर खर्च हो रही है। यानी हर साल प्राइवेट अस्पतालों को 712 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में भी यदि वो इलाज नहीं करते हैं तो वो खुद बता दें सरकार उनको योजना से हटा देगी।

प्रदेश में 1037 अस्पताल आयुष्मान योजना के दायरे में हैं। इसमें 542 निजी हैं। इनमें से 70 अस्पतालों को जांच के दायरे में रखा गया है। गौरतलब है कि घोटाले के बाद सकते में आया स्वास्थ्य विभाग अब इन निजी अस्पतालों पर जुर्माना लगाकर वसूली कर रहा है। विभाग ने 15 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कुल 104 अस्पतालों से जुर्माना वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं भोपाल के वैष्णव मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। अस्पताल की आयुष्मान योजना की संबद्धता भी समाप्त कर दी गई है। वहीं अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया।

वहीं प्रदेश के 104 अस्पतालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इनमें बीआईएमआर अस्पताल ग्वालियर, बॉम्बे अस्पताल रिसर्च सेंटर जबलपुर, कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जन विकास न्यास ट्रस्ट, केयर मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, सेंट्रल, चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्रालि, चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड चेरिटेबल फाउंडेशन, सीएसएस एप्पल मल्टीस्पेशियलिटी, सिटी अस्पताल, सिटी अस्पताल दमोह, सिटी अस्पताल जबलपुर, धर्मलोक अस्पताल प्रालि, डीएनएस अस्पताल प्रालि, गैलेक्सी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जबलपुर, जीडी अस्पताल रतलाम, गीता अस्पताल उज्जैन, ग्लोबल स्पेशियलिटी, ग्रेटर कैलाश अस्पताल

मप्र में 200 करोड़ का घपला

मप्र में आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध 120 निजी अस्पतालों ने 200 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के ख्यातिप्राप्त निजी अस्पताल भी शामिल हैं। भोपाल और जबलपुर के कुछ अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार कराई गई एक जांच रिपोर्ट में सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग अब इन निजी अस्पतालों पर अर्थदंड लगाकर वसूली कर रहा है और 15 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुल 104 अस्पतालों से अर्थदंड वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। भोपाल के वैष्णव मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही आयुष्मान योजना की संबद्धता भी समाप्त कर अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया है। बता दें कि आष्युमान योजना के अंतर्गत कुल 620 निजी अस्पतालों को 3 साल (वर्ष 2019 से जुलाई 2022 तक) में 1048 करोड़ 98 लाख 19 हजार 481 रुपयों का भुगतान किया गया है।

प्रालि, गुप्ता नर्सिंग होम, गुरू आर्शीवाद, इंफिनिटी हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ए यूनिट ऑफ आईएचआरसी जबलपुर, जेके अस्पताल एंड एनएल अस्पताल, जबलपुर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, जेश अस्पताल शाजापुर, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, जय आरोग्य, जेके, कैलाश सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ग्वालियर, एलबीएस, लीलावती मेमोरियल अस्पताल भोपाल, लाइफ मेडिकल अस्पताल, एकेजी हाईटेक अस्पताल अशोकनगर, लोटस, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, माहेश्वरी नर्सिंग होम, मार्बल सिटी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, मेडिस्क्वर मेट्रो अस्पताल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर जबलपुर, एमजीएम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कटनी, मिरेकल्स अस्पताल, मिशन अस्पताल दमोह, मिताली अस्पताल बालाघाट, मोहनलाल हरगोविंद पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, मोना अस्पताल, एमपी बिरला अस्पताल सतना, भोपाल का एके अस्पताल, आधार, अजय, अक्षय, ऑल इज वेल मल्टीस्पेशियलिटी, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, अर्मिता अस्पताल, आनंद, अपेक्स, आराधना मल्टीस्पेशियलिटी एंड किडनी, अरेरा ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर, आयुष्मान भारत, बाालाजी चिल्ड्रन, बंसल, भोपाल केयर, मल्टीकेयर अस्पताल भोपाल, नागपुर अस्पताल, नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद, नर्मदा ट्रामा सेंटर भोपाल, नवजीवन अस्पताल भोपाल और ग्वालियर, न्यूरो ट्रामा सेंटर एंड मल्टी स्पेशियलिटी, निरामय, पालीवाल, पांडेय, पाटीदार सेंटर एंड मल्टीस्पेशियलिटी मंदसौर, पाटीदार अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, पीपुल्स सेंटर अस्पताल प्रालि, प्राइम अस्पताल देवास, राम हाईटेक, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज एंड सीआर गार्डी अस्पताल, रीवा अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, आरजेएन अपोलो स्पेशल, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, रोशन, सागरश्री अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रालि, सहारा फ्रैक्चर एंड जनरल अस्पताल, संस्कारधानी अस्पताल प्रालि, सराफ, सर्वोत्तम, सेठ मन्नूलाल जगन्नाथदास ट्रस्ट अस्पताल, सेवा सदन आई अस्पताल, शेल्बी अस्पताल, शांता नर्सिंग होम, श्रीगुरुनानक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, श्रीसाईं, सिंगरौली अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, एसएनजी, एसएसआईएमएस ग्वालियर, स्वास्तिक मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, तृप्ति मल्टी स्पेशियलिटी एंड ट्रामा सेंटर, उबंतू अस्पताल भोपाल, उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, उज्जैन आर्थो, वंदना अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर, विंध्या अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर शामिल है।

● **अरविंद नारद**

कूनो नदी से ग्वालियर-चंबल होगा आत्मनिर्भर

ग्वालियर-चंबल अंचल को सदानीरा बनाने के लिए सरकार अंचल की कूनो नदी पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्यीय परियोजना के तहत 6 बांध बनाने जा रही है। इस परियोजना से ग्वालियर-चंबल अंचल को पेयजल भी उपलब्ध होगा, साथ ही बिजली उत्पादन भी हो सकेगा। श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्यीय परियोजना के नाम से प्रस्तावित इस परियोजना पर 6600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कूनो नदी पर बनने वाली यह परियोजना ग्वालियर-चंबल अंचल को आत्मनिर्भर बनाएगी।

कूनो नदी पर बनने वाली श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्यीय परियोजना पर कुल 6 हजार 601 करोड़ की लागत आएगी। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में पेश बजट में इस साल माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना के लिए मद का प्रावधान करते हुए 1000 रुपए की टोकन मनी रखी गई है। इस परियोजना से 4 जिलों के 800 गावों में 2 लाख परिवारों को पेयजल और 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई प्रस्तावित है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि कूनो नदी पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना में 6 बांध बनेंगे, 4 की डीपीआर बन गई है। यह परियोजना मुख्यमंत्री के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के विजन और आत्मनिर्भर मप्र के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे बारिश में चंबल की बाढ़ कंट्रोल होगी और 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

परियोजना के तहत कूनो नदी पर प्रस्तावित 6 बांधों में फेस-1 में गुना और शिवपुरी जिले में 4 बांधों की डीपीआर तैयार हो गई है, जिनका निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देश्यीय वृहद सिंचाई परियोजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले फेज-1 में गुना और शिवपुरी इलाके में 4 छोटे बांध बनेंगे। जबकि फेस-2 में श्योपुर जिले में एक बड़ा और एक छोटा बांध बनाया जाएगा। फेस-1 के चार बांधों में से एक गुना जिले के धनवाही गांव में, एक गुना-शिवपुरी बॉर्डर पर नैनागढ़ में और दो बांध शिवपुरी के पोहरी के सोमनपुरा और बदरवास के पवा गांव में बनेंगे। इन चारों बांधों के निर्माण पर 2006.31 करोड़ की लागत आएगी। इससे 60 हजार 620 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता भी विकसित होगी। फेज-2 में प्रस्तावित श्योपुर जिले में कटीला और श्यामपुर बांध का सर्वे पूरा हो गया है, अभी डीपीआर तैयार नहीं हुई है। कटीला बांध कूनो पार्क के दक्षिण में पोहरी-श्योपुर मार्ग पर और श्यामपुर बांध कूनो पार्क के उत्तर में बीरपुर में बनेगा। कटीला बांध से कूनो में बारिश में आने वाली अचानक बाढ़ नियंत्रित होगी, जबकि श्यामपुर बांध के बैक वाटर से कूनो में सालभर जल उपलब्धता बनी रहेगी।

25 बांधों की मरम्मत पर 551 करोड़ खर्च

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में 27 पुराने बांधों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए विश्व बैंक के सहयोग से 551 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के प्रावधान मप्र में लागू कर दिए गए हैं। डेम सेफ्टी रिव्यू पैनल भी मप्र में गठित हो गया है, जो प्रतिवर्ष संवेदनशील बांधों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजल का गंभीर संकट है। इसे दूर करने के लिए अटल भू-जल योजना लागू की गई है। योजना में शामिल 678 गांवों में पानी के भू-जल स्रोत का संवर्धन किया जा रहा है। 314.54 करोड़ रुपए की लागत से यहां के 6 जिलों के 9 विकासखंडों में यह काम चल रहा है।

गुना से निकलकर मुरैना में चंबल में मिलने वाली कूनो नदी मप्र की ऐसी नदी है, जिसमें हर साल बारिश में अचानक तेज बाढ़ आती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह किसी पहाड़ के बजाय एक ओवरफ्लो होने वाले कुएं से निकलती है। सिर्फ 180 किलोमीटर लंबी यह नदी गुना-शिवपुरी के बॉर्डर पर बहने के बाद राजस्थान के बारां जिले में प्रवेश कर वापस शिवपुरी के पोहरी से मप्र में दाखिल होती है और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के बीचों-बीच होकर बहती है। कूनो पार्क को कूनो नदी दो हिस्सों में बांटती है। पार्क के कुछ ही किलोमीटर दूर से मालवा के मऊ से निकली चंबल नदी बहती है। यह श्योपुर जिले में पाली गांव से दाखिल होती है। श्योपुर जिला राजस्थान के कोटा, बारां, सवाई माधोपुर और करौली से जुड़ा है। कूनो-पालपुर नेशनल पार्क में पानी का मुख्य स्रोत कूनो नदी है। इसके अलावा जंगल में बना एक प्राकृतिक झरना कैरी-खो है। इस झरने के पानी से पार्क में बने तमाम तालाब और जलकुंड बिना पंप के भरे जाते हैं। यहां झरने से निकलने वाला पानी पाइपलाइन में नेचुरल ग्रेविटी से आता है। यह पाइपलाइन 18 किलोमीटर लंबी है।

मप्र अगले कुछ सालों में भारत का सबसे ज्यादा सतही जल स्टोर करने वाला राज्य बन सकता है। मप्र जल संसाधन विभाग ने बीते दो साल में जल संरक्षण से जुड़े 126 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इनमें 4 वृहद्, 10 मध्यम और 112 लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। सभी प्रोजेक्ट की कुल लागत 6 हजार 700 करोड़ रुपए है। परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो इनसे 3.34 लाख हेक्टेयर जमीन में नई सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएगी। राज्यों के मंत्रियों के जल सम्मेलन में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मप्र का प्रेजेंटेशन देते हुए यह जानकारी दी। सिलावट ने केन-बेतवा राष्ट्रीय परियोजना से मप्र को होने वाले फायदों के बारे में बताया। सिलावट ने निर्माणाधीन कारम डेम के क्षतिग्रस्त होने की आशंका के बाद बिना जनहानि के डेम से पानी निकालने को आपदा प्रबंधन के मॉडल के रूप में पेश किया। जल संसाधन विभाग के प्रेजेंटेशन में बताया गया कि प्रदेश के जल संकट वाले इलाके ग्वालियर-चंबल में सिंचाई और पेयजल दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीमंत माधवराव सिंधिया नवीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना शुरू की जा रही है। इससे गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिले को लाभ मिलेगा। 6601 करोड़ रुपए लागत से 6 नए जलाशय बनाए जाएंगे। इससे 2 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। सिलावट ने बताया कि प्रोजेक्ट का सर्वे हो चुका है, डीपीआर का परीक्षण चल रहा है।

● **प्रवीण सक्सेना**

भोपाल 10 फीसदी भी स्मार्ट नहीं

केंद्र की नजर में भोपाल स्मार्ट सिटी देश में नंबर वन है। जबकि हकीकत यह है कि 7 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद शहर 10 फीसदी भी स्मार्ट नहीं हुआ है। 24×7 पानी सप्लाई, स्मार्ट बिजली और स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी अन्य सुविधाओं और वॉकिंग डिस्टेंस पर ही घर, स्कूल, कॉलेज, वर्क स्पेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात ही करना बेकार है। अब बात पैन सिटी की। यहां लगे स्मार्ट पोल स्ट्रीट लाइट पोल बन गए हैं। 16 ऑनलाइन सुविधाओं वाला भोपाल प्लस एप पूरी तरह बंद हो चुका है। करोड़ों खर्च में बनी बुलेवर्ड स्ट्रीट और स्मार्ट रोड के साथ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आईटीएमएस के अलावा स्मार्ट सिटी की कोई और उपलब्धि नहीं है। न्यू मार्केट और एमपी नगर की दो मल्टीलेवल पार्किंग और छोटे तालाब पर आर्च ब्रिज के जिन प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट सिटी के खाते से पेमेंट हुआ, वह वास्तव में नगर निगम के प्रोजेक्ट थे। अब केंद्र और राज्य सरकार ने 31 मार्च को पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के साथ ही तय कर लिया कि स्मार्ट सिटी को किसी काम के लिए पैसा नहीं देंगे।

स्मार्ट सिटी के जिन प्लॉट को बेचकर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, उन पर कब्जे कर मंदिर बन रहे हैं। प्लेटिनम प्लाजा के पास जहां 1 एकड़ का एक प्लॉट 19 करोड़ रुपए में बेचा गया है उसके पास 5000 वर्ग फीट में एक पुराना मंदिर है, इसे दोगुना करने के लिए स्लैब डाल दी गई थी। इसे अब तोड़ दिया गया है। होटल पलाश के सामने भी एक मंदिर को लेकर इसी तरह का विवाद हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट सिटी शब्द ही गलत है। शहर स्मार्ट नहीं डेवलप, अंडर डेवलप और अनडेवलप्ड होते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों को स्मार्ट नहीं कहता। सरकार का एक प्रोजेक्ट आया और कुछ लोगों ने बिना किसी विजन के इन्हें लागू किया। केवल बजट ठिकाने लगाने जैसा काम किया गया। निर्माण में कहीं भी क्वालिटी और वर्कमैनशिप का ध्यान नहीं रखा गया।

शहर को स्मार्ट बनाने के लिए एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी दो श्रेणियों में विकास होना था। टीटी नगर की 342 एकड़ जमीन पर एबीडी के तहत 3440.90 करोड़ रुपए में 70 प्रतिशत आवासीय और 30 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्र के साथ नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के सिद्धांत के तहत साइकिल लेन, चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली व पानी का काम होना था। ऑटोमेटेड कचरा प्रबंधन, गैस आधारित पावर प्लांट, सौर ऊर्जा के प्लांट, स्मार्ट मीटरिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट पार्किंग, और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी आदि की व्यवस्था होनी थी। 875.70 करोड़ में पैन सिटी प्रोजेक्ट में शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईटी बेस्ड साल्यूशन डेवलप किए जाना थे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की रैंकिंग का एक सिस्टम बनाया है। फंड यूटिलाइजेशन के आधार पर यह रैंकिंग तय होती है। इस रैंकिंग में भोपाल हमेशा टॉप के शहरों में ही शामिल रहा।

पूरे स्मार्ट सिटी एरिया में 6000 से ज्यादा पेड़ थे। इनमें से ज्यादातर पेड़ यहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों ने ही लगाए थे। इसमें से 2000 पेड़ काट दिए गए। शेष का भी कटना तय है। नॉर्थ-साउथ टीटी नगर मिलाकर 1000 सरकारी मकान खाली कराए। कट्‌र्सी, प्लेटिनम प्लाजा और पीएचई विभाग के ऑफिस के पास कुछ मकानों को खाली कराना शेष है। 600 मकान तोड़े जा चुके हैं, लेकिन खाली मकान पर कब्जे, खाली जमीन पर झुग्गियां बस रही हैं। 40 करोड़ की बुलेवर्ड स्ट्रीट पर सरफेस ड्रेनेज तक का ध्यान नहीं रखा गया है। सरफेस ड्रेन के होल साइकिल ट्रैक पर हैं। होटल पलाश के सामने टावर में एएसी ब्लॉक की जुड़ाई भी गलत हो रही। यहां नाला साफ दिख रहा, फिर भी 14 व 16 मंजिल टॉवर बना दिए गए।

स्मार्ट सिटी की शुरुआत में पहला प्रोजेक्ट शहर में 100 स्मार्ट पोल लगाने का था। इन स्मार्ट पोल से केवल स्ट्रीट लाइट मिल रही है। ई-व्हीकल चार्जिंग, वाई-फाई और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाओं का कोई अता-पता नहीं है। भोपाल प्लस एप से प्रॉपर्टी टैक्स, वॉटर टैक्स पेमेंट, बर्थ, डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन, पेमेंट गेटवे जैसी 16 सुविधाएं देने का वादा था। यह एप बंद हो गया। 5 करोड़ रुपए खर्च करके शहर में अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाईं गईं। लगने के बाद इन डस्टबिन की हकीकत सामने आई कि इनमें कचरा मिक्स हो रहा है। ऑटोमेटिक ढक्कन खुलने और बंद होने जैसी बातें भी शिगूफा निकलीं। एमपी नगर में ज्योति टॉकीज से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक 9.5 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट स्ट्रीट बनाई गई है। नगर निगम यहां वेंडर्स को जगह नहीं दे सका और उद्घाटन से पहले ही इसके शेड फट गए हैं।

● **डॉ. जयसिंह सेंधव**

ये काम भी अधूरे पड़े हैं

जेएनएनयूआरएम के बाद शहरों के विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने अमेरिका और यूरोप के मॉडल को अपनाकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन यह फेल हो गया। शहर को अपनी प्राथमिकता तय करके उस दिशा में काम करना था वह करने की बजाय बिना सोचे समझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बना दिए गए। शहर की मांग के विपरीत होने से यह सब अधूरे रह गए। 42 करोड़ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अधूरा रह गया। 525 करोड़ के गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज-2 और फेज-3 का काम ठप है। 180 करोड़ से महालक्ष्मी परिसर बीडीए के 551 फ्लैट तैयार हैं, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। 31 करोड़ की लागत से स्मार्ट दशहरा मैदान का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। 41 करोड़ के वाटर स्काडा सिस्टम को अब अमृत 2.0 में जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट सिटी में हमने प्रकृति, पर्यावरण और शहर की पहचान किसी का भी ध्यान नहीं रखा। केवल कांक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है। बिना सोचे समझे हो रहे इस डेवलपमेंट के उपयोग के लिए शहर तैयार है या नहीं? क्या भोपाल को एक ही जगह पर इतने सारे मॉल और होटल की जरूरत है?

नर्मदा का होगा सर्वे

चुनावी साल में धर्म और आस्था के साथ सियासत का केंद्र नर्मदा नदी को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पर्यावरण विभाग ने नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा नदी की वास्तविक स्थिति का सर्वे किया जाएगा। मप्र में नर्मदा की कुल लंबाई 1 हजार 77 किलोमीटर है। ऐसा भी पहली बार होगा कि जिलेवार घाटों के आधार पर नर्मदा की गहराई, तट की स्थिति, कैचमेट का जीआईएस सर्वे, वनस्पति के साथ नदी पर आश्रित जंगलों का पूरा खाका भी तैयार किया जाएगा। नर्मदा के जलीय जीवों का अपडेट डाटा भी सरकार के पास होगा। प्रोजेक्ट पर चरणबद्ध तरीके से काम होगा। पहले फेस में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच माह पहले गोवर्धन पूजन के दौरान लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए अधिकारियों को वृहद स्तर पर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नर्मदा नदी का यह प्रोजेक्ट एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट होगा। फिर प्रदेश की अन्य बड़ी नदियों में शामिल चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा समेत अन्य नदियों के संरक्षण संबंधित कवायद की जाएगी। राज्य सरकार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की भी मदद लेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने नर्मदा के रियल टाइम मॉनीटरिंग प्रोजेक्ट का मसौदा भी पांच माह पहले तैयार किया था। अब इस प्रोजेक्ट का विस्तार किया है।

पर्यावरण विभाग ने पांच माह पहले नर्मदा नदी के प्रदूषण की रियल टाइम मॉनीटरिंग के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। प्रोजेक्ट में चिन्हित घाटों को शामिल किया गया। इसमें ककराना घाट (अलीराजपुर), राजघाट (बड़वानी), धरमपुरी (धार), मंडलेश्वर और ओंकारेश्वर, नेमावर (देवास), शाहगंज (सीहोर), बरमान घाट (नरसिंहपुर), ग्वारीघाट (जबलपुर), डिंडौरी, मंडला और अमरकंटक को शामिल किया गया था। यहां रियल टाइम वॉटर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम लगाए जाने हैं। सेंसर और फ्लोटिंग सिस्टम से **जल प्रदूषण पर अत्याधुनिक तकनीक** से नजर रखी जाएगी। प्रदूषण की स्थिति को सार्वजनिक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड में ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी, पीएच लेवल की स्थिति और तय मानकों की जानकारी भी दी जानी है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नर्मदा नदी के तट पर लगे बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाएं हैं। सीवेज का पानी नर्मदा में सीधे तौर पर न मिले इसके लिए संबंधित स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियां भी तय हैं। लेकिन गांवों या छोटे कस्बों में सीवेज प्रबंधन को सख्ती से लागू कराने की दिशा में काम किया जाएगा। नर्मदा नदी तट पर कई ऐसे स्थान हैं यहां रहवासी क्षेत्रों से दूर सीवेज सीधे तौर पर मिलता है।

नर्मदा नदी के प्रवाह के लिए जरूरी प्रमुख रूप से 41 सहायक नदियां बताई जाती हैं। इसके अलावा ऐसी भी कई छोटी नदियां, झरने, उपसहायक नदियां सैकड़ों की संख्या में हैं जिनका विलय नर्मदा में होता है। आश्चर्य इस बात का है कि इनके संरक्षण के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। सैटेलाइट एक्टिविटी सिस्टम के जरिए नर्मदा में मिलने वाली तमाम छोटी-बड़ी नदियों या नदी नुमा जलधारा को चिन्हित किया जाए। स्थानीय स्तर पर संरक्षित करने के साथ पुनर्जीवित करने के लिए पहल का खाका तैयार किया गया है। जागरूकता अभियान के संचालन के साथ समाज सेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। बता दें कि नर्मदा कि सहायक नदियों में तवा, शेर, शक्कर, मान, हिरन, कानर, बरना, तिंदोली, बनास समेत अन्य नदियों का नाम शामिल है।

पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए हर स्तर पर प्लान तैयार किया गया है। रियल टाइम मॉनीटरिंग से लेकर कई बिंदुओं पर संरक्षण की कवायद की जाएगी। उन्होंने बताया कि नर्मदा संरक्षण के लिए इस प्लानिंग में कई नवाचार भी होंगे। अभियान के दौरान नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) हैदराबाद से नर्मदा नदी की सैटेलाइट इमेज बुलाई जाएंगी। नर्मदा नदी के दोनों ही तट (उत्तर और दक्षिण) का जीआईएस सर्वे किया जाएगा। नर्मदा के ग्रीन लैंड और कैचमेंट एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नर्मदा नदी से 300 मीटर तक हुए निर्माणों की सूची तैयार की जाएगी। इनमें पुरातात्विक महत्व के निर्माण, प्राचीन निर्माण, मठ-मंदिरों की भी जानकारी दी जाएगी। हाई फ्लड लेवल (एफएचएल) का एरिया को जीआईएस सर्वे के जरिए चिन्हित किया जाएगा। जिलों के आधार पर नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों (कच्चे और पक्के घाट) पर गहराई की रिपोर्ट, प्रदूषण की स्थिति, मिट्टी के प्रकार आदि का सर्वे होगा। पथरीले, मैदानी, दलदली, मिट्टी, रेतीले जैसे श्रेणियों में घाटों को वर्गीकरण किया जाएगा। जलीय जीवों, वनस्पति, पेड़-पौधों की प्रजातियों का डाटा तैयार किया जाएगा। नर्मदा नदी के वनों की स्थिति जानने के लिए वर्तमान सैटेलाइट इमेज का डाटा तैयार होगा। इसके अलावा इमेज रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। जो वन परिक्षेत्र के प्रतिशत पर आधारित होगी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

प्रदेश की प्रमुख नदियों के संरक्षण का होगा काम

अधिकारियों ने बताया कि नर्मदा नदी के इस प्रोजेक्ट के आधार पर अन्य नदियों का भी संरक्षण किया जाएगा। लिहाजा इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी लिया जा रहा है। अन्य नदियों का संरक्षण भी चरणबद्ध तरीके से होगा। चंबल, क्षिप्रा, खान, काली सिंध, तवा समेत अन्य नदियों को लेकर प्रोजेक्टों पर काम किया जा रहा है। बता दें कि मप्र में पार्वती, सोन, बेतवा, तवा, बेनगंगा, कालीसिंध, ताप्ती, शक्कर, शेर, हिरन, चंबल, क्षिप्रा, खान समेत अन्य प्रमुख नदियां हैं। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट में अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी होगी। प्रमुख रूप से प्रोजेक्ट पर वन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, पुरातत्व विभाग काम करेंगे। जनअभियान परिषद और एनजीओ की भी मदद ली जाएगी।

हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस

मप्र में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश की सियासत गर्माने लगी है। इस सियासत में धर्म का भी सहारा लिया जा रहा है। गत दिनों पीसीसी मुख्यालय में धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए मुख्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया गया। इस पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया। वहीं, पलटवार करते हुए कांग्रेस ने पूछा कि क्या भगवा भाजपा का ट्रेडमार्क है? मप्र की सियासत में धर्म के नाम पर क्या-क्या हो रहा है? कांग्रेस का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ क्या है? राम वन गमन पथ क्या है जिसकी घोषणा कांग्रेस ने पिछले चुनाव में की थी? मप्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों भाजपा की राह पर है? मप्र में विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को कांग्रेस ने मुख्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल यहां मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेशभर के मठ, मंदिरों के पुजारी शामिल हुए। इस दौरान प्रकोष्ठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को गदा भेंटकर धर्म संवाद कार्यक्रम में उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, यही शक्ति समाज के लोगों को जोड़कर रखने का काम करती है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के लिए पहल उनकी सरकार ने की थी।

मप्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2022 में कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया। कहा जा रहा है कि इस प्रकोष्ठ के जरिए कांग्रेस हिंदुत्व की छवि चमकाना चाहती है। कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर शिवनारायण शर्मा को अध्यक्ष बनाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकोष्ठ के जरिए पार्टी ब्राह्मण वोटों को साधना चाहती है। इस प्रकोष्ठ के जरिए कांग्रेस मंदिर और पुजारियों के मुद्दे भी उठाना चाहती है। पिछले दिनों रामनवमीं के पावन पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भगवामय दिखे थे। इस दिन वो रघुवंशी समाज छिंदवाड़ा द्वारा निकाली गई शोभायात्रा में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पूजा-अर्चना की। पिछले साल (अप्रैल 2022 में) भी प्रदेश कांग्रेस ने रामनवमीं और हनुमान चालीसा पर अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, विधायकों को रामलीला, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश दिए थे। ताकि चुनाव से पहले कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ को और मजबूत कर सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भव्य हनुमान मंदिर बनाया है। यही कारण है कि वह अपने आप को राम भक्त हनुमान का भक्त कहलाना पसंद करते हैं।

5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया था। भूमिपूजन से पहले मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर बदल ली थी। इस तस्वीर में वे भगवा चोला पहने हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस नेता ने अपनी तस्वीर बदली और लिखा था, श्रीराम के हनुमान करो कल्याण। इसके अलावा उन्होंने भोपाल स्थित अपने आवास में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मप्र में कांग्रेस धर्म के मुद्दे पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश पिछले चुनाव से ही कर रही है।

2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राम वन गमन पथ को अपने वचन पत्र में शामिल किया था। इसमें उन धार्मिक स्थानों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की योजना है जिन पर वन गमन के समय भगवान राम के चरण पड़े थे। चुनाव के बाद कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कार्ययोजना बनाकर 22 करोड़ रुपए का बजट भी अध्यात्म विभाग को दिया, लेकिन 15 महीने बाद ही सरकार चली गई। शिवराज सरकार बनने के बाद दोबारा राम वन गमन पथ को लेकर काम शुरू किया गया। अब इसका काम अध्यात्म विभाग से लेकर संस्कृति विभाग को सौंपा गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राम वन गमन पथ को लेकर काम शुरू हो गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को आठ माह का समय बचा है। इसके साथ ही फिर भगवान राम सियासत के केंद्र में आ गए हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हिंदू वोटरों को साधने के लिए धर्म का सहारा ले रही हैं। भाजपा अक्सर कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताती रही है।

● **राकेश ग्रोवर**

क्या मप्र की सियासत में है धर्मगुरुओं का दबदबा?

मप्र की सियासत में धर्म का तड़का कोई नई बात नहीं है। पिछले चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सरकार ने नर्मदा विकास के लिए समिति बनाकर कम्प्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था। मार्च 2018 में नर्मदा नदी के किनारे पेड़ लगाने में हुए कथित घोटाले को लेकर यात्रा निकाली गई थी, जिसमें शिवराज सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा दिया और एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में कम्प्यूटर बाबा को शामिल किया गया और उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा मिला। लेकिन जब सरकार बदली तो कम्प्यूटर बाबा ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसके अलावा कम्प्यूटर बाबा ने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विरोध किया था और दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए मिर्ची यज्ञ किया था। वहीं, इस चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में दो धर्मगुरु-धीरेंद्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा केंद्र बने हुए हैं। पिछले कुछ समय में बागेश्वर धाम में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज पहुंचे हैं। इसमें भाजपा सांसद मनोज तिवारी, मप्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आदि शामिल हैं। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 18 फरवरी को बागेश्वरधाम पहुंचे। वे यहां आयोजित 121 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। माना जा रहा है कि चुनावी साल में बहुसंख्यक वोटों को हासिल करने की कोशिश में राजनीतिक दल दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।

500 वर्ग किलोमीटर में बाघों का बसेरा

बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 4 साल में टाइगर दोगुने हो गए हैं। 2018 की गणना में 124 थे, जो अब 220 हैं, जबकि इस बीच यहां 40 टाइगरों की मौत हो चुकी है। अभी ताजा आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बांधवगढ़ पार्क में 185 वयस्क टाइगर कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं। अन्य 35 से ज्यादा की मौजूदगी के निशान मिले हैं। इसलिए इनकी संख्या 220 है। इनमें से करीब 70 टाइगर पार्क से बाहर निकल चुके हैं। इनके बाहर होने से बांधवगढ़ से लेकर कान्हा, पेंच और संजय टाइगर रिजर्व तक 500 वर्ग किमी क्षेत्र में टाइगर कॉरिडोर बन गया है। पूरे इलाके में हर जगह टाइगर हैं।

टाइगर की क्षेत्रफल के हिसाब से संख्या को लेकर 2018 में उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क पहले नंबर पर था, लेकिन इस बार बांधवगढ़ का नंबर-1 आना तय है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के रेंज ऑफिसर रंजन परिहार बताते हैं कि हमारे ताला की झूमरी नाम की बाघिन तकरीबन 300 किमी दूर छत्तीसगढ़ के अचानकमाल के जंगल में है। यानी हमारे बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इसलिए हमने 2500 वर्ग किमी एरिया बढ़ाने की योजना बनाकर सरकार को दी है।

टाइगर रिजर्व में पहाड़ी क्षेत्र और कई गुफाएं हैं, जिनमें 6 महीने तक बाघिन अपने बच्चों को सुरक्षित और छिपाकर रख लेती है। यहां अधिकांश एरिया ऐसा है जहां लोगों की आवाजाही बिलकुल नहीं है। पहाड़ पर बेहतर गुफाएं हैं और पानी के लिए पहाड़ी पर प्राकृतिक 12 तालाब हैं। पानी का सोर्स बहुत बेहतर है। सबसे अच्छा पानी का सोर्स 3 किलोमीटर में माना जाता है लेकिन बांधवगढ़ में 2 किलोमीटर पर है। हमारे पास 450 जल स्त्रोत हैं। 85 हजार चीतल बाघ का नैचुरल फूड है। बांधवगढ़ में 165 किलोमीटर की 11 केवी की इलेक्ट्रिक लाइन है। हमारे पास 738 लोगों का नियमित स्टाफ है। इसके अलावा एक हजार लोग अनियमित हैं। हम 5-5 किलोमीटर का एरिया बांटकर रातभर पेट्रोलिंग करते हैं।

बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर लविद भारती कहते हैं कि संख्या बढ़ने का कारण टाइगर के लिए फूड, क्वालिटी ऑफ एरिया, पानी की उपलब्धता होने से वातावरण बहुत अनुकूल होना है। 2010 में जब बांधवगढ़ पार्क में 67 टाइगर थे, तब भी एक साल में औसतन 10 टाइगर की मौत होती थी। अब टाइगर 200 से ज्यादा हैं, लेकिन मौतें लगभग 15 होती हैं। एसडीओ सुधीर मिश्रा कहते हैं कि 2005 से 2013 तक डिंडोरी में एक भी टाइगर नहीं देखा गया। अब डिंडोरी की हर रेंज में टाइगर है। हमारे बेहतर मैनेजमेंट से टाइगर की संख्या बढ़ने का नतीजा है कि पहली बार रेंजर से नीचे के कर्मचारी बिहार से ट्रेनिंग लेने हमारे पास आए हैं। इनकी संख्या 600 है। इसी तरह लद्दाख से 80 अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिए पत्र आया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जगबीर चौहान कहते हैं कि पार्क की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि टाइगर 20 किमी भी किसी तरफ लगातार चलता है तो दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। इसलिए यहां टाइगर बढ़े हैं। शहडोल जिले के रेंजर रवि कहते हैं कि अभी केशवाही में 2 टाइगर देखे गए हैं, जबकि बांधवगढ़ से केशवाही 150 किमी दूर हैं। शहडोल व आसपास 26 बाघों का मूवमेंट है।

परिहार कहते हैं कि आमतौर पर बाघिन के 10 से 12 प्रतिशत बच्चे ही जिंदा रहते हैं, लेकिन बांधवगढ़ में एक साल में 4 बच्चों की ही मौत हुई है। बाकी सब जिंदा हैं। औसतन एक बाघिन 3 से 4 बच्चों को जन्म देती हैं। इनमें 33 प्रतिशत बच्चे भी जिंदा रह जाएं तो बेहतर होता है। एसडीओ सुधीर के मुताबिक बाघ एक रात में 30 किमी चल लेता है। उसकी खासियत होती है कि जिस रास्ते से उसके पूर्वज निकले होते हैं वो उस रास्ते पर अपने आप चलने लगता है। बाघ की विस्टा, पेड़ पर खरोंच, यूरिन आदि निशानियों को कई साल बाद भी बाघ जेनेटिक रूप से पहचान लेता है।

रेंज ऑफिसर रंजन के अनुसार बांधवगढ़ पार्क का बफरजोन भी मिलाकर 1531 वर्ग किमी का क्षेत्र है। इसमें 720 वर्ग किमी का कोर एरिया है, जिसमें टाइगर मूवमेंट करता है। संख्या बढ़ने से पूरे क्षेत्र के 132 गांवों में टाइगर मूवमेंट है। हम बाघ-बाघिन के दोनों तरफ के फोटो लेते हैं। इनमें 149 के दोनों तरफ के फोटो मैच हुए हैं। 36 टाइगर के एक साइड के फोटो मैच किए हैं। 30 से 40 टाइगर आसपास जैसे जयसिंह नगर, गुड़ावल, बरही, पाली के जंगल में हैं। कुछ दूसरे जंगलों की तरफ भी निकले हैं। हम 220 टाइगर मान सकते हैं। ये सब 2 साल से ऊपर के हैं। इनमें हमने शावकों को नहीं जोड़ा है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

बाघों के घर में बारहसिंगा का भव्य स्वागत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा के आने की करीब तीन महीने से तैयारियां चल रही थीं। गत दिनों जब कान्हा से बारहसिंगा बांधवगढ़ पहुंचे तो रिजर्व प्रबंधन का इंतजार खत्म हुआ। रिजर्व प्रबंधन से बारहसिंगा के बांधवगढ़ पहुंचने की एक खूबसूरत वीडियो आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कान्हा से ट्रकों के माध्यम से बारहसिंगा को बांधवगढ़ लाया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा विलुप्त हो चुके हैं। इनकी फिर से बसाहट के लिए कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंगा को बांधवगढ़ लाया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के वन्यप्राणी चिकित्सा विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक टीम कान्हा टाइगर रिजर्व से बारहसिंगा को विशेष वाहन से लेकर बांधवगढ़ पहुंची थी। जहां से बारहसिंगा को मगधी जोन में बनाए गए एक बाड़े में छोड़ा गया है। इस अवसर पर अनुविभागीय वन अधिकारी सुधीर मिश्रा, रेंजर धमोखर सहित अन्य लोग मौजूद थे।

टूटेगा ठेकेदार-इंजीनियर का गठजोड़

मप्र में लोक निर्माण विभाग का नाम सुनते ही लोगों के सामने एक ऐसी तस्वीर आती है, जहां लेटलतीफी, भर्राशाही, भ्रष्टाचार, इंजीनियरों, ठेकेदारों और अफसरों की सांठगांठ दिखती है। लेकिन अब विभाग में ठेकेदार और इंजीनियरों का गठजोड़ खत्म करने के कई प्रयोग हुए हैं। दरअसल, जबसे विभाग की कमान प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने संभाली है, उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सबसे अधिक जोर दिया है। अभी तक तो वे खुद सड़क या अन्य निर्माण स्थलों पर जाकर गुणवत्ता की जांच कर रहे थे, लेकिन अब निर्माण कार्यों की जांच एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों की गुणवत्ता की जांच अफसर अब तक नजरों के पैमाने से ही करते थे। नतीजा ठेकेदारों के सांठगांठ पर घटिया सड़क भी कागजों पर ओके करार दे दी जाती थी। लेकिन अब इस गठजोड़ को तोड़ेगा महकमे का हाईटेक सॉफ्टवेयर। ठेकेदारों के साथ जिम्मेदार इंजीनियर की जवाबदेही भी तय होगी। सॉफ्टवेयर की ओके रिपोर्ट पर ही ठेकेदार का भुगतान होगा। दरअसल, ठेकेदार को अपनी बनाई सड़क के निर्माण से जुड़ी जानकारी सॉफ्टवेयर पर अपलोड करनी होगी। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इस रिपोर्ट को ऑनलाइन ही मानकों से मिलान करेंगे। उसके बाद सैम्पल लिया जाएगा। सैम्पल लेते ही उसका क्यूआर कोड बनेगा। सैम्पल लेबोरेटरी में जाएगा। जहां उसके मानकों की जांच होगी। यह पूरी जांच गोपनीय रहेगी। यानी न ठेकेदार और न ही इंजीनियर को इस बात की भनक लगेगी कि सैम्पल की जांच कहां हो रही है। रिपोर्ट नकारात्मक आने पर भुगतान रोक दिया जाएगा। तब तक, जब तक कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होगा।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सरकार गहराई से नजर रखेगी, विभाग ने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया है। सेल की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग के सचिव करेंगे, यानि वे इसके प्रमुख होंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव **सुखवीर सिंह** ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल सेल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्णता पर नजर रखेगी। साथ ही समय-समय पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तकनीकी सकुंलर भी जारी करेगी। उन्होंने बताया कि ये सेल विभागीय अधिकारियों को तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए मॉडल तैयार करना एवं प्रशिक्षण व्यवस्था करना, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निर्धारित मापदंड, व्यवस्था, प्रक्रिया की समीक्षा करना और नवीन तकनीकी दिशा-निर्देश तैयार करना, विभिन्न स्तरों पर प्रचलित व्यवस्था एवं निर्माण गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण करना, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की समीक्षा एवं इन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना, विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों का संकलन, एकीकरण एवं समीक्षा करना, सभी स्तरों पर की जा रही कार्यवाहियों की सतत् निगरानी एवं समीक्षा करना, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित कराना और मासिक प्रतिवेदन प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि सेल में सचिव लोक निर्माण आरके मेहरा अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य अभियंता उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर बीपी बोरासी, अधीक्षण यंत्री सेतु मंडल एमपी सिंह, सहायक यंत्री सीवी तिवारी, सहायक यंत्री संजय कुलकर्णी और सलाहकार मंत्रालय रितेश जैन समिति सदस्य होंगे।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों और इंजीनियरों की सांठगांठ से घटिया निर्माण करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसका असर यह होता है कि निर्माण कार्य समय से पहले ही ध्वस्त हो जाते हैं। इसको देखते हुए विभाग ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने की तैयारी कर ली है। इससे हर साल खराब होने वाली सड़कों से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही निर्माण कार्य भी गुणकारी होंगे। सॉफ्टवेयर की निगरानी में आने के बाद लोक निर्माण विभाग में जो सांठगांठ का खेल चलता है, वह लगभग पूर्णत: बंद हो जाएगा। इससे सरकार को भी होने वाली राजस्व हानि से राहत मिलेगी।

● **बृजेश साहू**

हर साल उखड़ जाती हैं हजारों किमी की सड़कें

प्रदेश में हर साल हजारों किमी सड़कें बाढ़, बारिश और घटिया निर्माण के कारण खराब हो जाती हैं। मप्र की 76 हजार किमी सड़कों में से 8 हजार किमी इस बार बारिश में खराब हो गईं। ये सड़कें लोक निर्माण विभाग, मप्र सड़क विकास निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हैं। ऐसा पहली बार है जब मानसूनी बारिश में प्रदेश में इतनी ज्यादा सड़कें खराब हुईं हों। अब तक 4 से 5 हजार किमी सड़कें ही खराब होती रही हैं। 55 हजार किमी का बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसमें से सबसे ज्यादा 5500 किमी से ज्यादा सड़कें पूरी तरह उधड़ गईं। बाकी खराब सड़कों में 2500 किमी का हिस्सा आरडीसी और एनएचएआई का है। खास बात यह है कि सालभर पहले ही बनी भोपाल से नर्मदापुरम जाने वाली सड़क औबेदुल्लागंज से बुदनी के बीच खराब हो गई है। इस मार्ग पर कई बड़े-छोटे गड्ढे हो गए। इन सड़कों की मरम्मत के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सड़कें मापदंडों के अनुसार बनतीं तो इतनी मात्रा में सड़कें खराब नहीं होतीं। प्रदेश में पिछले पांच साल में 2500 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत में खर्च हो चुके हैं। इसी से समझा जा सकता है कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण किस हद तक खराब हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार की नई पहल काम आएगी और मप्र की सड़कें गुणवत्तापूर्ण होंगी।

विपक्ष की केमिस्ट्री पर चेहरा कौन?

लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन विपक्षी एकता का तानाबाना बुना जाने लगा है। इस बार बाया नीतीश कुमार यह प्रयास शुरू हुआ है। वे 2024 में विपक्ष को एकजुट करने का मकसद लेकर दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश ने राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल तक से मुलाकात कर विपक्ष की केमिस्ट्री मजबूत करने की कोशिश की है। 2024 में 2004 वाले फॉर्मूले पर शुरू हुई विपक्षी एकता की कवायद क्या गुल खिलाएगी यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन बिना चेहरे के यह कवायद सफल हो पाएगी इसको लेकर भी असमंजस है, क्योंकि जब भी चेहरे की बात आती है तो लगभग हर विपक्षी पार्टी का नेता अपने आपको भावी प्रधानमंत्री का ताज पहने देखता है।

● राजेंद्र आगाल

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि भाजपा देश में अभी 25 साल तक राज करेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष 2024 में मोदी राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहा है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए विपक्षी एकता की कई कवायदें हो चुकी हैं। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2024 से पहले पूरा विपक्ष एक मंच पर एक नारे के साथ दिखेगा। वैसे देखा जाए तो 2019 के पहले भी इस तरह की कई कवायदें हुई थीं। लेकिन विपक्षी एकता धरी की धरी रह गई। एक बार फिर से 2024 को देखते हुए विपक्षी एकता पर जोर दिया जा रहा है। इस एकता में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी चेहरे की बात आती है तो पार्टियां बिखर जाती हैं। यानी अभी तक विपक्षी पार्टियां यह तय नहीं कर पाई हैं कि किसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद ही संभावना है कि यह एकता मोदी राज के खिलाफ मजबूत हो पाएगी।

2024 का लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, विपक्ष की एकजुटता की कवायद तेज होने के साथ-साथ इस पर सवाल भी उठते जा रहे हैं। साल 2024 से पहले मौजूदा वर्ष 2023 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 6 राज्यों के चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव हो चुके हैं। कर्नाटक, मिजोरम, मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहे जा रहे इन विधानसभा चुनावों के परिणामों से कुछ हद तक यह साफ हो जाएगा कि भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के खिलाफ विपक्ष लोकसभा चुनाव में कितना एकजुट होगा और कैसा प्रदर्शन करेगा? फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों के नतीजों ने सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। इन चुनाव परिणामों से यह भी साफ हो गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों में भी अपने बलबूते सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहीं।

3 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते लड़ेगी। ममता के एकला चलो रे के नारे के एक पखवाड़े के बाद ही उनकी और उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, फिर दोनों ने मिलकर अगला लोकसभा चुनाव गठबंधन करके लड़ने की घोषणा कर दी। उन दोनों की मंशा कांग्रेस से परहेज करते हुए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की है। अखिलेश ने तो साफ तौर पर उप्र में कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वे कांग्रेस और भाजपा से दूरी बनाकर रखेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत करने के संकेत भी दिए हैं। ममता बनर्जी बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से जल्द ही मुलाकात करने वाली हैं।

विपक्षी एकजुटता की कोशिशें तेज

यह तो तय था कि आगामी वर्ष आम चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कोशिशें तेज होंगी। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले ही एकजुटता की कवायद शुरू हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कम ही थी। शायद मानहानि मामले में राहुल गांधी की सांसद के रूप में सदस्यता समाप्त किए जाने और फिर उनसे सरकारी आवास खाली कराए जाने के घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। गत दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर राहुल गांधी से हुई मुलाकात को विपक्षी एकता की दिशा में बड़ी पहल कहा जा रहा है। हालांकि, इन एकता के प्रयासों में कोई नई बात नहीं है क्योंकि बिहार सरकार में पहले ही तीनों दल शामिल हैं। इससे पूर्व फरवरी में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया रैली में कांग्रेस से मोदी सरकार के खिलाफ तुरंत एकजुट होने की बात कह चुके थे। लेकिन राहुल प्रकरण ने विपक्षी दलों को असुरक्षाबोध से भर दिया और यह निष्कर्ष समझ में आने लगा कि यदि हम एकजुट न हुए तो तंत्र के निरंकुश व्यवहार का शिकार होना पड़ सकता है। जिसके चलते कई राजनीतिक दल, जो विपक्षी एकता में कांग्रेस की भूमिका के प्रति किंतु-परंतु करते थे, वे भी अब एकता के प्रयासों को नई उम्मीद से देख रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी समान विचार वाले दलों के साथ समन्वय की बात करने लगी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव से पहले एकजुटता के जरिए विपक्ष महासमर की मॉकड्रिल करने के मूड में है। वैसे उसके बाद साल के अंत तक महत्वपूर्ण राज्यों राजस्थान, मप्र व छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस के लिए बेहतर प्रदर्शन की चुनौती यह भी होगी कि इनमें 2 राज्यों में उसकी ही सरकारें हैं। ऐसे में सवाल उठेगा कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता के फॉर्मूले का प्रयोग इन राज्यों से शुरू कर देगी?

दरअसल, विपक्षी एकता की कवायद गाहे-बगाहे होती रही हैं, लेकिन इनमें तेजी बड़े चुनाव से पहले ही आती है। फिर कई राज्यों की सत्ता में काबिज विपक्षी दलों के क्षत्रप कांग्रेस को लेकर परहेज करते रहे हैं। इनमें वे दल भी शामिल हैं जिनका जन्म ही कांग्रेस विरोध और इस पार्टी से टूटकर हुआ है। मसलन उप्र में सपा सुप्रीमो अखिलेश, बीआरएस सुप्रीमो चंद्रशेखर राव तथा तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता

विपक्षी दलों का एक मंच पर आना आसान नहीं

गत दिनों दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। वैसे, विपक्षी दलों में एकता को लेकर नीतीश बहुत ही उत्साहित और आशांवित हों, लेकिन उनकी यह राह इतनी आसान नहीं कही जा रही है। नीतीश बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन उसका बहुत उत्साह जनक परिणाम नहीं मिला था। नीतीश एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं। इधर, कहा जा रहा है कि करीब-करीब सभी दल के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। दीगर बात है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दौड़ से खुद को बाहर बता रहे हैं। इस बीच, लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान कहते हैं कि इससे पहले भी विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वर्ष 2014 में और 2019 में इसके प्रयास किए गए थे और अब फिर 2024 के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में नीतीश कुमार से कई बड़े नेता हैं और कई बड़े दल हैं। ऐसे में कोई क्यों 40 विधायकों वाली पार्टी के नेता को अपना नेता मानेगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश के लिए यह असंभव है। इधर, भाजपा के एक नेता की मानें तो राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेता प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं, इसलिए एकजुटता का प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे पूर्व हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बैठक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने यहां पर ऐतिहासिक बैठक की है और बहुत सी चीजों पर चर्चा की है। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना है और आने वाले चुनाव में एकजुट होकर लड़ना है।

विपक्षी एकता की राह में क्या है सबसे बड़ा रोड़ा?

मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। विपक्ष भी इस बार भाजपा को सत्ता से हटाने की चाहत में एकजुट होने की पूरी कोशिश में है, लेकिन अब नेतृत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की कमान उसके हाथ में होगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अन्य विपक्षी दलों को यह फैसला मंजूर होगा? सभी राजनीतिक दलों की नजर 2024 में होने वाले चुनावों पर है। अंदरखाने सियासी गुणा गणित जारी है। विपक्ष के तमाम नेता विपक्षी गठबंधन बनाने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टियों के बीच खटास नजर आ रही है। हालांकि, कई नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार भी किया है। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी शामिल है। हालांकि, वह शुरुआत से ही कांग्रेस के पाले में नजर आ रहे हैं। अब इस बीच कई ऐसे दल भी हैं जो इस गठबंधन में रोड़ा बन सकते हैं। गठबंधन के बारे में सभी विपक्षी दलों की राय एक ही है, लेकिन जब बात इस गठबंधन का नेतृत्व करने वाले की आती है तो तमाम दलों में अनबन की झलक दिख ही जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष एक चेहरे पर सहमति बना पाएगी? दरअसल, हर पार्टी की अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं। जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताती है, वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभालें और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छिपी नहीं है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा था कि उनकी पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में और वह जिस तरह से लड़ती हैं एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह लड़ता हो। पार्टी हर एक चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ रही है और जीत रही है। ऐसे बयानों से यह तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस के लिए नेतृत्व हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। भले ही खरगे इस बात को खुले मंच से बोल चुके हैं, लेकिन अंदरखाने क्या चल रहा है इसकी भनक अभी किसी को नहीं है। विपक्षी नेता एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन यह भी बताते चल रहे हैं कि फिलहाल नेतृत्व के बारे में न सोचा जाए। उद्धव ठाकरे के सामना ने लिखा- विपक्ष एकजुट हो तो भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये सब बाद में तय किया जा सकता है। रोड़ा ये भी है कि सभी दल नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी अपने ही पार्टी प्रमुख को बनाना चाहते हैं।

गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को सौंपने पर विपक्ष में असहमति

तृणमूल और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की घोषणा से पहले कांग्रेस के विपक्षी एकता को लेकर दिए गए बयान से बवाल हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 21 फरवरी को नागालैंड में दावा किया था कि अगले साल केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनेगी। इसके अगले ही दिन उन्होंने सफाई दी कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। खरगे ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को सौंपने का आह्वान किया। बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की भी पेशकश कर दी। उन्होंने इसे कांग्रेस और देश के लोगों की मन की बात निरूपित किया। कांग्रेस के रुख को लेकर विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए उसे विपक्ष का नेतृत्व करने के बजाय आत्ममंथन करने की सलाह दी। विपक्ष के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस का दावा है कि उसके अलावा सिर्फ भाजपा ही राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं और तीन राज्यों में वह गठबंधन सरकारों का हिस्सा है। कांग्रेस खुद के सबसे बड़े विपक्षी दल होने का दावा करती है क्योंकि वह 10 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। कांग्रेस को तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का साथ मिलने का विश्वास है।

बनर्जी एकता के प्रयासों में कांग्रेस की बड़ी भूमिका से परहेज करती हैं। अब भी अहम सवाल यही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? लेकिन नीतीश कुमार अब विपक्षी एकता में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के लिए मुहिम चला रहे हैं। हालांकि, अब तक अडाणी प्रकरण में जेपीसी जांच के मुद्दे पर अलग राय रखने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार को विपक्षी एकता के प्रयासों में बाधक बताया जा रहा था, लेकिन अब पवार ने भी कह दिया है कि जेपीसी मुद्दे पर अलग राय होने के बावजूद वे विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। वैसे भी पवार की पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है। कहीं न कहीं एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता खत्म होने ने भी विपक्षी एकजुटता की कवायद को बल दिया है। जिसके चलते पर्दे के आगे-पीछे एकता के प्रयासों को सिरे पर चढ़ाने की कवायद तेज हुई है। नीतीश अरसे बाद बिहार से निकलकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सक्रिय हुए हैं और लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि से मिले हैं। जिसका निष्कर्ष यह पढ़ा जा सकता है कि विपक्षी एकता की योजना सिरे चढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस, जदयू व राजद की एकजुटता के बाद अन्य क्षत्रपों को एकसाथ लाने के प्रयासों में आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है। वैसे भी तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में कांग्रेस सहयोगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी व एमएनएम एकजुटता दिखा चुके हैं। उम्मीद आप को लेकर भी लगाई जा रही है।

2004 के फॉर्मूले पर कवायद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरे दमखम के साथ जुट गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने नीतीश को विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी है। नीतीश कांग्रेस की लिखी विपक्षी एकता की पटकथा को अमलीजामा पहनाने के मिशन में जुटे हैं। कांग्रेस ने रायपुर के 85वें अधिवेशन में 2024 में विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का

यूपीए फॉर्मूले पर समान विचाराधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। नीतीश उसी पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम बताते हैं कि 2004 में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का फॉर्मूला क्या रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए केंद्र की सत्ता में और कांग्रेस विपक्ष में थी। एनडीए से मुकाबले कांग्रेस ने 2003 के शिमला अधिवेशन में गठबंधन की राह पर चलने का प्रस्ताव पास किया था। सोनिया गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का गठन किया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से दो-दो हाथ करने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी, लेकिन एनडीए के चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी के सामने विपक्ष ने किसी भी चेहरे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया था।

कांग्रेस उस चुनाव में एनसीपी, टीआरएस, डीएमके, जेएमएम, आरएलडी और एलजेपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी। कांग्रेस महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी-एलजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। इन 5 राज्यों की कुल 188 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें से 61 सीटें कांग्रेस ने जीती थी जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में सफल रहे थे। वहीं, एनडीए और अन्य विपक्षी दलों के खाते में 74 सीटें आई थीं। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 417 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 145 जीते थे। वहीं, भाजपा ने 364 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें 138 पर जीत मिली थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस की सफलता के पीछे खासकर वो 5 राज्य थे, जहां पर गठबंधन कर चुनाव लड़ा गया था और इन राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 1999 के चुनाव की तुलना में 2004 में पूरा गेम ही बदल दिया था।

2004 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने गठबंधन के दांव से भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेफ्ट फ्रंट के 59, सपा के 35 और बसपा के 19 सांसदों का समर्थन हासिल कर कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया तब जाकर प्रधानमंत्री पद के लिए नाम पर मुहर लगाई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने और उन्हें सियासी मात देने के लिए 2004 वाले गठबंधन फॉर्मूले पर आगे कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस ने साफ किया है कि 2024 में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की कवायद की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नीतीश कुमार तक उसी फॉर्मूले पर काम करते नजर आ रहे हैं।

विपक्षी एकता अभी दूर की कौड़ी

लोकसभा चुनाव में अभी लगभग एक साल शेष है लेकिन भाजपा ने सत्ता बचाने और विपक्षी दलों ने सत्ता पाने की कवायद तेज कर दी है। सत्ता पाने की कोशिश यदि दुष्कर है तो सत्ता बचा सकने का प्रयास भी कठिन है। भाजपा के समक्ष सत्ता विरोधी लहर और उसको हवा दे रहे विपक्षी दल फिलहाल फीलगुड महसूस कर रहे हैं परंतु विरोधियों के मन मे यह भी आशंका बनी हुई है कि क्या सभी बड़े विरोधी दल एकजुट हो पाएंगे? किसी मुद्दे पर बिखराव तो नहीं हो जाएगा? नेता कौन होगा, इस मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता है लेकिन नेतृत्व करना सभी प्रमुख दल चाहते हैं। बहरहाल, नेता के प्रश्न को अभी अनुत्तरित रखना ठीक ही है। अभी जरूरत है कि सभी विपक्षी दल एक जाजम पर बैठ जाएं और भाजपा से मोर्चा लेने एवं पटकनी देने की तरकीब पता करें। ऐसा लगता है कि विरोधी दल 1977 की परिस्थिति बनती देख रहे हैं जब सभी विरोधी पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हुई थीं और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। सोच दुरुस्त है लेकिन किसी एक को जयप्रकाश नारायण बनना पड़ेगा। आज जेपी कौन बनना चाहेगा? सभी को तो मोरारजी देसाई बनने की चाहत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी बनना चाहते हैं या मोरारजी भाई यह अभी कहना मुश्किल है। उनका पिछला रिकार्ड कहता है कि वे मोरारजी भाई ही बनना पसंद करेंगे क्योंकि वे सत्ता में बने रहने के लिए दो बार भाजपा से, तो दो बार लालूजी की पार्टी राजद से हाथ मिला चुके हैं। अब कह रहे हैं कि वे भविष्य में बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव को सौप देंगे। हालांकि उनकी इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है और यह भी कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री की कुर्सी की दौड़ में नहीं है लेकिन विपक्षी एकता के लिए दौड़-भाग करते दिख रहे हैं।

2004 से 2024 के हालात अलग

कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 के फॉर्मूले पर विपक्षी एकता बनाने की कवायद जरूर कर रही है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। 20 साल में देश की सियासत काफी बदल गई है। कांग्रेस 2004 की तरह मजबूत नहीं है तो उस समय साथ रहे कई क्षेत्रीय दल भी साथ छोड़ चुके हैं। 2004 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी अब भाजपा के साथ है तो लेफ्ट पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में काफी कमजोर स्थिति में है। उप्र में बसपा और सपा की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। तेलंगाना की टीआरएस भी कांग्रेस के खिलाफ है। भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मंत्र पर धीरे-धीरे अपना मजबूत वोट बैंक बना लिया है। मतदाताओं पर भाजपा की पकड़ को इस बात से भी आंका जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उप्र जैसे राज्य में मजबूत विरोधी गठबंधनों के बावजूद वह आगे निकल गई। भाजपा के खिलाफ उप्र में बसपा-सपा-आरएलडी, कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस, झारखंड में कांग्रेस के साथ जेएमएम-जेवीएम, बिहार में कांग्रेस-आरजेडी मैदान में थे। फिर भी भाजपा ने 2019 में 2014 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 के गठबंधन वाले फॉर्मूले से विपक्ष क्या भाजपा को चुनौती दे पाएगा?

यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है,

लेकिन सच को स्वीकार करने से शायद ही कोई इनकार करे। नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी को बिखरने से नहीं रोक पाते हैं तो वे विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएंगे? जार्ज फर्नांडीस, शरद यादव, जीतनराम मांझी, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसे नाम हैं, जो कभी नीतीश के साथ रहे। बड़े सांगठनिक या विधायी पदों पर यानी पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मंत्री-मुख्यमंत्री रहे। पर, सबने समय-समय पर नीतीश से तंग आकर उन्हें बाय बोल दिया। अब वही नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए नगरी-नगरी, द्वारे-द्वारे दस्तक देते फिर रहे हैं। शायद उम्र और औकात का असर है कि अपने बेटे समान राहुल गांधी के सामने उन्हें दंडवत की अदा में झुकना पड़ रहा है। राहुल के संस्कार भी देखिए कि बाप दाखिल नीतीश जी के हाथ जोड़े झुकने पर भी वे तनकर खड़े रहे। नीतीश जी अभिवादन करने नरेंद्र मोदी के सामने भी झुके थे, पर मोदी ने उतना ही झुककर अभिवादन का जवाब भी दिया था।

नीतीश कुमार की इस दुर्दशा को देखकर भाजपा का खुश होना स्वाभाविक है। इसलिए कि उसकी ही कब्र खोदने का बीड़ा नीतीश जी ने उठाया है। साथ-साथ उनको भी जरूर आनंद आ रहा होगा, जिन्हें नीतीश ने उनके बढ़ते कद के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया या जिन्हें बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था कभी। शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडीस तो इनकी हालत पर इतराने के लिए अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के मन में जरूर लड्डू फूट रहे होंगे। इतरा तो प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी रहे होंगे, जिन्होंने नीतीश की जीत तो पक्की कर दी थी, पर झटके में उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया था। इस बार तो बिना पार्टी के अपना कैंडिडेट जिताकर पीके ने नीतीश जी के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया है। जीतनराम मांझी ने तो नीतीश को चिढ़ाने-बिदकाने का नायाब तरीका अपनाया है। उनके एकता प्रयास को सांकेतिक चुनौती देने के लिए हड़बड़ी में मांझी ने दिल्ली दौड़ ही लगा दी। इधर नीतीश कुमार कांग्रेस के राहुल, खरगे और अरविंद केजरीवाल से मिलकर मन ही मन इतरा रहे थे, उधर मांझी उसी दिन दिल्ली में भाजपा से सांठ-गांठ में लगे थे। मांझी अगले ही दिन भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मिलकर बतिया भी आए। हां, इतना जरूर किया कि बाहर निकलते ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर बूझो तो जानें की स्थिति में उन्हें डाल दिया। नीतीश को पहले से ही इसका अंदाजा रहा है। तभी तो पूर्णिया में हुई महागठबंधन की रैली में उन्होंने कहा था कि मांझी का मन भी इधर-उधर होते रहता है।

कर्नाटक में जातिगत प्रभाव

कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनावी बिगुल बजा दिया हैं। भाजपा के अलावा सत्ताधारी कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के नेता भी प्रचार के दौरान हवा को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। तीनों ही दल 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से सिर्फ राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों की ही नहीं बल्कि इसी साल 2023 में होने वाले आम चुनावों की दिशा भी तय हो सकती है। बीते तीन दशकों में कर्नाटक की राजनीति एक ही पैटर्न पर चली आ रही है। जहां राज्य की तीनों प्रमुख पार्टियां इसी कशमकश में दिखती हैं कि वे अपने जातिगत आधार पर ध्यान दें या फिर नए सामाजिक समूहों को लुभाएं। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही अपनी-अपनी जुगत में लगी हैं कि किस तरह से राज्य की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया जाए। साल 2013 को अगर नजरअंदाज किया जाए तो कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी अपने बलबूते राज्य में सरकार बनाने में नाकाम रही है। मौजूदा सरकार में यूं तो मुख्यमंत्री भाजपा के हैं लेकिन पार्टी येदियुरप्पा वाले लिंगायत प्रभाव से आगे बढ़ना चाहती है। जिसको लेकर हाल ही में पार्टी ने आरक्षण का कार्ड भी खेला है। दूसरी ओर कांग्रेस इस तरह से चुनावों को सुनहरे मौके के रूप में देख रही है कि किसी तरह जनता की नाराजगी को अपनी जीत में तब्दील कर लिया जाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर भी चुनाव को लेकर खुद को किंगमेकर की भूमिका में देख रही है।

कांग्रेस और भाजपा से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद

क्षेत्रीय दलों के कुछ नेता लोकसभा चुनावों से पहले एकजुट होकर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि तीसरे मोर्चे के लिए भी अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं, किसी एक झंडे के नीचे आने को लेकर सहमति नहीं बन रही है। इसके पीछे जहां सबके अपने अलग राजनीतिक गणित हैं, वहीं सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। तेलंगाना के क्षेत्रीय दल तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है, के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भाजपा के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने की कवायद में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार सहित विपक्ष के कई नेताओं के साथ इसको लेकर विचार मंथन किया है। हालांकि केसीआर कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते और शिवसेना व एनसीपी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में पिछली सरकार चला चुके हैं इसलिए वे कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते। शरद पवार ने तो साफ कहा है कि कांग्रेस को किसी वैकल्पिक मोर्चे से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में केसीआर को शिवसेना और एनसीपी का साथ मिलेगा, इसमें संदेह है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यह संकेत भी दे दिए हैं कि वह कांग्रेस को छोड़कर केसीआर के साथ नहीं जाएगी। उसने कहा है कि अगर सभी विपक्षी दल समय पर सतर्क नहीं हुए और एकजुट नहीं हुए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। शिवसेना के निशाने पर वे क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस को अस्वीकर कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा है कि, ममता बनर्जी, केसीआर भाजपा से लड़ने के लिए अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस से द्वेष रखकर भाजपा की मौजूदा तानाशाही से कैसे लड़ेंगे? इस पहेली को पहले सुलझाना होगा।

भारत में आएगी कैंसर की सुनामी

अमेरिका के एक नामी कैंसर रोग विशेषज्ञ ने चेताया है कि आने वाले समय में भारत को कैंसर जैसी घातक बीमारियों की सुनामी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने इसकी वजह ग्लोबलाइजेशन, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बूढ़ी हो रही जनसंख्या और भारतीय आबादी के बीच तेजी से बढ़ रही खराब लाइफस्टाइल बताई है। उन्होंने इस सुनामी को रोकने के लिए मेडिकल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अमेरिका के ओहियो स्थित क्लीवलैंड क्लिनिक के हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जामे अब्राहम ने कहा कि भारत में जिस तरह से गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, इसे रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो इसकी रोकथाम और उपचार पर तेजी से काम शुरू करे। भारत को कैंसर के टीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा डिजिटल तकनीक को एडवांस्ड करना जरूरी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने बताया था कि देश में 2020 से 2022 के बीच अनुमानित कैंसर के मामले और इससे होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अनुसार, 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर के अनुमानित मामले 2020 में 13.92 लाख (लगभग 14 लाख) थे जो 2021 में बढ़कर 14.26 लाख हुए और 2022 में बढ़कर 14.61 लाख पर पहुंच गए थे। 2020 में भारत में कैंसर के कारण अनुमानित मृत्यु दर 7.70 लाख (लगभग 7 लाख 70 हजार) थी जो 2021 में बढ़कर 7.89 लाख और 2022 में बढ़कर 8.8 लाख हो गई थी। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट किए जा रहे नए सालाना कैंसर के केसों की 2020 की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद भारत को तीसरे स्थान पर रखा था।

पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पुरूषों में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आए। वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और गर्भाशय के कैंसर के रहे। भारत में साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से 87 हजार महिलाओं की मौत हुई थी। यशोदा हॉस्पिटल, कौशांबी (गाजियाबाद) के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में यूनिट हेड और कन्सल्टेंट डॉ. अभिषेक यादव कहते हैं कि भारत में कैंसर के मामलों में पिछले कुछ सालों में काफी तेजी आई है। यहां हर साल कैंसर के 10 से 15 केस सामने आते हैं। जबकि पूरी दुनिया में 1.8 करोड़ लोग हर साल कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले मुंह के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के हैं।

उन्होंने आगे कहा, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी (जीसीओ), ग्लोबोकॉन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़े बताते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में ही मुंह, फेफड़ों और ब्रेस्ट कैंसर के केस बढ़े हैं। भारत में हर साल करीब तीन लाख केस मुंह के कैंसर के आते हैं। इसके बाद दो लाख केस ब्रेस्ट कैंसर और लगभग एक लाख के करीब मामले फेफड़ों के कैंसर के होते हैं। भारत में पुरूष सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़ों के कैंसर का शिकार होते हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह धूम्रपान और तंबाकू का सेवन है। वहीं, महिलाएं सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं।

डॉ. अभिषेक कहते हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस बीमारी के बढ़ने की वजह गलत खानपान, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रदूषण, पेस्टिसाइड्स और केमिकल से संक्रमित भोजन का सेवन जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। उन्होंने बताया, कुछ तरह के कैंसर बढ़ने की प्रमुख वजहों में ह्यूमन पेपिलोमावायरस इंफेक्शन (एचपीवी), हेपेटाइटिस बी और सी जैसी संक्रमण वाली बीमारियां शामिल हैं। ये लिवर, ब्रेस्ट और सर्वाइकल और मुंह के कैंसरों की वजह बनती हैं। हेपेटाइटिस बी और सी लिवर कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। एचपीवी ओरल और सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने इससे बचने के तरीके बताते हुए कहा कि एचपीवी हेपेटाइटिस बी और सी जैसी वायरल डिसीस से बचने के लिए वैक्सिनेशन जरूरी है। इनकी दो खुराकें ली जाती हैं। वहीं, ब्रेस्ट और सर्वाइकल जैसे कैंसरों से बचने के लिए साल में एक बार स्क्रीनिंग जरूरी है। 55 से ऊपर के बुर्जुगों को साल में एक बार स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। इसके साथ ही हर किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिसमें पौष्टिक खानपान और एक्टिव लाइफस्टाइल शामिल है। धूम्रपान, तंबाकू और शराब से बचना चाहिए।

● **विकास दुबे**

पुरुषों में धूम्रपान की वजह से कैंसर का खतरा ज्यादा

इंसान का शरीर खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर का छोटे से बड़ा अंग करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और विभाजित होती हैं। लेकिन जब शरीर की कोशिकाएं जरूरत के बिना अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगें तो यह कैंसर की शुरुआत होती है। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरने की बजाय जीवित रह जाती हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही यह कोशिकाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यह शरीर के स्वस्थ ऊतकों और कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। कैंसर होने के बाद इसका पूरे शरीर में फैलने का खतरा होता है। कैंसर बेहद खतरनाक और भयानक बीमारी है। दुनियाभर में होने वाली कुल मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। भारत समेत दुनियाभर में कैंसर का सबसे आम प्रकार स्तन, फेफड़े, पेट, गुदा और प्रोस्टेट कैंसर हैं। कैंसर के कारणों में तंबाकू का उपयोग, मोटापा, शराब का सेवन, कम फल और सब्जियों का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी शामिल है। तंबाकू कैंसर की बीमारी के लिए जिम्मेदार कारकों में सबसे अहम है। धूम्रपान और तंबाक की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 40 फीसदी ऐसे मामले हैं जो टोबैको रिलेटेड कैंसर (टीआरसी) यानी तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। युवाओं में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है।

क्षत्रपों को दरकिनार नहीं कर पाएंगी राष्ट्रीय पार्टियां

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो गई हैं। लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, ऐसे में यह बात तो तय है कि आगामी चुनाव में क्षेत्रीय क्षत्रपों का दम दिखेगा। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कारण था कि इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस के क्षत्रपों को किनारे किया जाने लगा और राजीव गांधी के समय में उनकी अनदेखी और तेज हुई। यही स्थिति भाजपा की बन रही है।

कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अपने क्षत्रपों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। क्षत्रप यानी क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले बड़े नेता। आज जैसे नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी अपराजेय लगती है, वैसे ही सत्तर के दशक में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कारण अपराजेय थी। 1977 में आपातकाल और संजय गांधी की ज्यादतियों की बदनामी के कारण इंदिरा गांधी खुद भी हार गई थीं, लेकिन 1980 में पार्टी को फिर जिताकर ले आई थीं। अगर वह कुछ साल और जिंदा रहती, तो कांग्रेस अपराजेय बनी रहती। लेकिन यह इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को मिले रिकार्डतोड़ समर्थन के बावजूद वह उस समर्थन को अपने साथ बनाए नहीं रख सके। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस क्षत्रप विहीन हो गई थी, राज्यों में करिश्माई नेता नहीं रहे, तो कांग्रेस जमीन पर टिक नहीं पाई। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कारण यह था कि इंदिरा गांधी के जमाने में ही कांग्रेस के क्षत्रप इधर-उधर बिखरने लगे थे और राजीव गांधी के समय में उनकी अनदेखी और तेजी से हुई।

जिस पोजीशन में सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस थी, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसी पोजीशन में भाजपा है। जब तक मोदी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा अपराजेय बनी रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी के रहते ही जैसे प्रदेशों में कांग्रेस हारने लगी थी, वही सिलसिला अब भाजपा के साथ शुरू हो गया है। चार साल पहले भाजपा मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारी थी, पिछले साल हिमाचल प्रदेश हारी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार की अलग बात है, इन तीनों राज्यों में भाजपा कभी भी अपने बूते बहुमत में नहीं आई थी। मोदी जब राष्ट्रीय पटल पर आए तब इन तीनों राज्यों में भाजपा सहयोगियों के साथ सत्ता में थी, मोदी के राष्ट्रीय पटल पर आने के बाद भाजपा इन तीनों राज्यों में एक-एक बार सत्ता से बाहर भी हुई है। मोदी की चतुराई से भाजपा कर्नाटक, महाराष्ट्र और मप्र में दोबारा सत्ता में लौटी भी है, लेकिन उधार के समर्थन के साथ। बिहार में सत्ता में लौटकर दोबारा सत्ता से बाहर है। अब हम उन छह राज्यों का विश्लेषण करते हैं, जहां भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी। मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हम एक श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इन तीनों राज्यों में भाजपा बिना किसी के समर्थन से अपने बूते पर ही सत्ता में थी।

महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक को हम दूसरी श्रेणी में रखते हैं, इन तीनों राज्यों में भाजपा को कभी बहुमत नहीं मिला था और वह अपने सहयोगियों के कारण सत्ता में थी। मोदी के राष्ट्रीय पटल पर आने के पहले ही मप्र में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में

केजरीवाल ने सब पर लगाया आरोप

अरविंद केजरीवाल ने शायद ही किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता छोड़ा हो, जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हों। और शायद ही ऐसा कोई बड़ा नेता बचा हो, जिससे कोर्ट में उन्होंने माफी नहीं मांगी हो। वह आजतक मानहानि का एक भी केस नहीं जीते, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने वाला केस भी हार गए। हाईकोर्ट ने मोदी की डिग्री पर बिना वजह का बखेड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल ने खुद पहले ट्वीट लिखकर हाईकोर्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, बाद में प्रेस कांफ्रेंस करके उनके कई भाषणों का जिक्र करते हुए उन्हें फिर से अनपढ़ कहा। अपनी प्रेस कांफ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने ऐसी-ऐसी बातें कहीं हैं कि उनका यहां उल्लेख करना भी शोभा नहीं देता। संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके अदालत पर आरोप लगाया कि केजरीवाल तो केस में पार्टी ही नहीं थे, हाईकोर्ट ने उन पर जुर्माना कैसे कर दिया। लेकिन यह कहानी शुरू होती है सात साल पहले, जब अरविंद केजरीवाल ने खुद मोदी की डिग्री को लेकर आरटीआई लगाई थी। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को आदेश जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने को कहा था।

वसुंधरा राजे क्षत्रप के तौर पर उभर चुके थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद क्षत्रप के तौर पर नहीं उभरे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, जबकि रमन सिंह सामान्य वर्ग से हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा के सभी बड़े नेता सामान्य वर्ग से आते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए क्षत्रप के तौर पर किसी के उभरने का संकट पहले भी था, आज भी है। रमन सिंह अपनी कोई पुख्ता जमीन नहीं होने के कारण केंद्रीय नेतृत्व की कृपा पर ही निर्भर रहे, हालांकि रमेश बैंस बेहतर विकल्प हो सकते थे। एससी, एसटी, ओबीसी नेतृत्व के अभाव में भाजपा सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर चलती तो छत्तीसगढ़ बच सकता था, लेकिन भाजपा ने ऐसा सोचा नहीं और 2018 में हार गई। दूसरी तरफ 2014 से 2018 के दौरान मप्र के क्षत्रप शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की क्षत्रप वसुंधरा राजे को अस्थिर करने की खबरें आती रहीं थीं। मप्र में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने और राजस्थान में वसुंधरा को हटाकर ओम माथुर को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों की खबरें आने लगी थीं। इन दोनों ही राज्यों में गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी थी कि भाजपा हार गई और दोनों ही राज्यों में बाहरी समर्थन के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और 2020 में मप्र में कमलनाथ सरकार गिर गई।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2014 से 2018 के बीच क्षत्रपों को अस्थिर करने की गलती को सुधारकर शिवराज सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया तो भाजपा मप्र में स्थिर सरकार दे सकी। 2020 में राजस्थान कांग्रेस में भी बगावत हो रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने का सिग्नल नहीं गया तो कांग्रेस की सरकार बच गई। अब हम दूसरी श्रेणी के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा 2014 में बिना गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई थी, जिसे उसने 2019 में भी बनाए रखा। बिहार में भाजपा 2020 में गठबंधन के बावजूद बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में वह सहयोगी पार्टी की वजह से बहुमत में थी, दोनों ही राज्यों की सहयोगी पार्टियों ने धोखा दिया, तो सत्ता से बाहर हो गई। महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी शिवसेना को तोड़कर भाजपा दोबारा सत्ता में है और बिहार में पूर्व सहयोगी जदयू टूटने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के आखिर तक जदयू टूट जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी 2 अप्रैल को ही नवादा में रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जदयू के आधे सांसद भाजपा में आने को तैयार बैठे हैं।

राहुल गांधी को सीखनी होगी रणनीतिक चाल

राहुल गांधी की गलती यह है कि उन्होंने केजरीवाल से आरोप लगाना तो सीख लिया, माफी मांगना नहीं सीखा। खुद को गांधी और माफी मांगने वालों को सावरकर कहने वाले राहुल गांधी ने अब वीर सावरकर पर ट्विटर में की गई सारी टिप्पणियां हटा ली हैं। जैसे ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने आंख दिखाई, उन्होंने सावरकर का नाम लेने से तौबा कर ली। अरविंद केजरीवाल आज तक मानहानि का एक भी केस नहीं जीते, यही हाल राहुल गांधी का होने वाला है। मानहानि के एक केस में वह सजायाफ्ता हो चुके हैं, अभी उन पर कम से कम दस केस और चल रहे हैं। एक केस तो सुशील मोदी का बिहार में चल रहा है, जिसकी सुनवाई करीब-करीब पूरी हो चुकी है, फैसला आना बाकी है। दो और बड़े केस दाखिल होने वाले हैं, दोनों केस मोदी चोर वाले केसों से ज्यादा मजबूत होंगे। एक केस वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर दाखिल कर रहे हैं, तो दूसरा केस ललित मोदी लंदन में दाखिल कर रहे हैं। ललित मोदी का केस बहुत मजबूत होने वाला है, क्योंकि जिस बयान पर राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है, उसी भाषण में राहुल गांधी ने बाकायदा उनका नाम लिया था।

कर्नाटक में 2008 से वही हो रहा था, जो 2014 से 2018 के बीच राजस्थान और मप्र में हो रहा था। येदियुरप्पा वहां के क्षत्रप थे, 2008 से वह मुख्यमंत्री थे। 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए तो उन्हें पद से हटना पड़ा। भाजपा ने पहले डीवी सदानंद गौड़ा और फिर जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन क्षत्रप येदियुरप्पा ही थे, इस बीच वह आरोपों से बरी भी हो चुके थे। इसलिए भाजपा ने 2018 के चुनाव में वह गलती नहीं की, जो वह राजस्थान और मप्र में कर रही थी। भाजपा येदियुरप्पा को सामने रखकर ही चुनाव मैदान में उतरी और 104 सीटें जीतकर पहले नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी, हालांकि बहुमत से सिर्फ 8 सीटें दूर रह गई। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन दोनों दलों में दलबदल के कारण 13 महीनों में ही सरकार गिर गई। जुलाई 2019 में जब भाजपा के साथ बहुमत बन चुका था, उस समय अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो सरकार न बनती, न चलती। जैसे 2017 में भाजपा गोवा में अपने क्षत्रप मनोहर पर्रिकर के कारण सरकार बना सकी थी, ठीक उसी तरह 2019 में कर्नाटक के क्षत्रप येदियुरप्पा के कारण भाजपा दोबारा सत्ता में आ सकी। लेकिन भाजपा ने वही गलती की, जिस का एहसास उसे अब विधानसभा चुनावों में हो रहा है। जुलाई 2021 में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि यह बदलाव उन्हें विश्वास में लेकर किया गया, लेकिन भाजपा के क्षत्रप तो येदियुरप्पा ही हैं, बसवराज बोम्मई नहीं। नरेंद्र मोदी ने यह जो 75 साल वाला फॉर्मूला बना रखा है, वह क्षत्रपों के साथ नहीं चलता। इसलिए मजबूरी में 2022 में येदियुरप्पा को भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाना पड़ा और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को येदियुरप्पा के घर जाकर उनकी मान मनोव्वल करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, लेकिन चुनाव की कमान 80 साल के येदियुरप्पा के हाथ में है।

अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ने आरोप लगाया है कि अडानी की कंपनियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा लगा हुआ है। हालांकि दोनों तय नहीं कर पा रहे कि वे कितना पैसा कहें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आजकल कांग्रेस की बैठकों में जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि वह राहुल गांधी के साथ बैठकर तय कर लेते कि कितना पैसा कहना है। संसद से अपनी बर्खास्तगी के बाद बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी के 20 हजार करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगे हैं। लेकिन संजय सिंह ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में यह राशि 42 हजार करोड़ रुपए बताई है।

● **विपिन कंधारी**

इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष गोलबंदी करने में जुटा हुआ है। लेकिन हर बार किसी न किसी कारण विपक्ष की एकता अधर में लटक जाती है। वर्तमान में एनसीपी सुप्रीमो ने अडानी मामले में जेपीसी की मांग को गलत बताकर विपक्षी एकता को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

विपक्ष की एकता अधर में...

अगले आम चुनाव की एक तरह से उलटी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कुछ समय पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित हुई तो हाल में कांग्रेस का महाधिवेशन संपन्न हुआ। दोनों दलों ने अपने इन आयोजनों में अपनी रीति-नीति की कुछ झलकियां पेश कीं। इस बीच विपक्षी एकता के प्रयास भी तेज हुए हैं। निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही इन प्रयासों के केंद्र में है। हालांकि पार्टी के रवैये से कुछ दुविधा दिखाई दे रही है। एक ओर वह विपक्षी एकता के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होने की बात करती है तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों के संदेश के जवाब में तंज भी कसती है। कांग्रेस यही दावा करती रही है कि भाजपा के विरूद्ध किसी भी राजनीतिक गोलबंदी की कवायद उसके बिना मुश्किल है। यह बात सही है कि अखिल भारतीय उपस्थिति और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस विपक्षी एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, फिर भी विपक्षी एकता का प्रश्न बहुत जटिल है। इसकी राह में आ रही बाधाओं के लिहाज से हमें चार पहलुओं पर दृष्टि डालनी होगी।

सबसे पहला तो यही कि कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में कोई समस्या नहीं और वे वर्तमान में भी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे झारखंड में झामुमो और तमिलनाडु में द्रमुक। दोनों ही जगह कांग्रेस राज्य सरकार में कनिष्ठ सहयोगी बनी हुई है। यहां गठबंधन में वरिष्ठ दलों का कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं है तो किसी प्रकार की तल्ख राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या असुरक्षा का मुद्दा गौण हो जाता है। महाराष्ट्र में राकांपा और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी ऐसे ही दलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा पहलू जदयू और राजद जैसे उन दलों से जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस के पाले में हैं तो, लेकिन कुछ किंतु-परंतु के साथ। तीसरा पहलू सपा, बसपा और जनता दल-सेक्युलर जैसे दलों से जुड़ा है, जिनके साथ कांग्रेस ने अतीत में गठबंधन किया, पर वह विशेष चुनावी लाभ में रूपांतरित नहीं हो पाया। चौथा पहलू कांग्रेस के लिहाज से बेहद जटिल है, क्योंकि यहां पेच बीजद, भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस जैसे उन दलों के साथ फंसता है, जिनका अपने राजनीतिक गढ़ में कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी जैसे दल भी हैं जो स्वयं को राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

कुछ राज्यों में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है और यहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर न होने से भाजपा को बढ़त मिलती है और विपक्षी ताकत कमजोर पड़ जाती है। उत्तर-पश्चिम भारत में फिलहाल भाजपा के बढ़ते दबदबे का भी कांग्रेस को कोई तोड़ निकालना होगा। किसी संभावित महागठबंधन को लेकर एक व्यावहारिक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि

राजनीतिक दल गले मिलने को तैयार

महागठबंन के लिए दूसरी कसौटी यही है कि उसके केंद्र में एक प्रमुख दल और सर्वस्वीकार्य नेतृत्व आवश्यक है। निसंदेह कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, मगर उसके नेतृत्व को लेकर विपक्षी खेमे में संदेह है। इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक मोर्चे पर ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन प्रतीत होता है कि उनका नेतृत्व पूरे विपक्षी खेमे को अभी भी स्वीकार्य नहीं। उनकी यात्रा से भी कई प्रमुख दलों ने दूरी बनाए रखी और केवल औपचारिक शुभकामना संदेश के जरिए एकजुटता का प्रदर्शन किया। ऐसे में नेतृत्व और स्वीकार्य चेहरे का संकट बना हुआ है। इस कड़ी में तीसरी कसौटी होगी संसाधनों को जुटाने और उनके साझा उपयोग की। यदि महागठबंधन आकार लेता है तो सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण जैसे उलझाऊ मुद्दों को सुलझाने की चुनौती भी उत्पन्न होगी। अन्य विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस पर दबाव बनाना भी शुरू हो गया है कि उसे केवल 200 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्या कांग्रेस इतनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी के लिए तैयार होगी।

ऐसी कोई पहल अगर विधानसभा चुनाव में सफल हो जाए तो आवश्यक नहीं कि लोकसभा चुनाव में भी उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। उप्र से लेकर बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे इसके तमाम उदाहरण हैं और ये ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की अधिकांश सीटें हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी की निजी लोकप्रियता की काट तलाशना भी विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। यदि विपक्ष इन सभी उलझनों को सुलझाने में सफल रहता है तभी व्यापक विपक्षी एकता की किसी मुहिम को सफलता मिल सकती है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत दिनों मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। केजरीवाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच 2024 की रणनीति और विपक्ष को एकसाथ लाने को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम लंबे समय से मिलना चाहते थे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों मिलना चाहते थे। देशभर से कई अन्य वरिष्ठ नेता मुझसे मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं।

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महमारी के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के काम की प्रशंसा की। केजरीवाल ने कहा कि मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कि दिल्ली ने महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल के दौरान उद्धव सरकार के द्वारा अच्छे अभ्यास शुरू किए गए थे, जिनका हमने पालन किया। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद कई राज्यों पर नजर है। इसको लेकर केजरीवाल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र सहित कई प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल अगले महीने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र का दौरा करेंगे। जहां केजरीवाल आप के लिए जुगलबंदी शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़, मप्र और राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

इन चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में आप के मैदान में होने की वजह से रोचक होने की उम्मीद है जिसका मनोबल पंजाब, गुजरात और गोवा में पिछले साल हुए चुनाव में मिले मतों से ऊंचा है। केजरीवाल नीत पार्टी ने पिछले साल मार्च में पंजाब की सत्ता पर एकतरफा जीत के साथ कब्जा किया था और भाजपा के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी पार्टी दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 13 प्रतिशत मतों के साथ पांच सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। आप ने गोवा विधानसभा में भी पिछले साल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दो सीटों पर जीत दर्ज की। इन तीनों राज्यों में पार्टी को मिली सफलता के बाद निर्वाचन आयोग ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। आप ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव में वह इन राज्यों में अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आप ने कर्नाटक की 224 सीटों में से 28 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 85 पर राजस्थान की 200 सीटों में 142 पर और मप्र की 230 सीटों में से 208 पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही थी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप ने दिल्ली के बाद 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। आप ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में भी दो सीटें जीती थीं। इसके बाद, बीते साल (2022 में) आप ने भाजपा के गढ़ गुजरात में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। गुजरात विधानसभा चुनाव में आप को 5 सीटों पर जीत मिली थी और करीब 14 फीसदी वोट मिले थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आप ने देशभर में अपना विस्तार करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी का लगभग सभी राज्यों में अपना संगठन बन चुका है और इसे मजबूती देने का काम तेजी से चल रहा है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि हमारा लक्ष्य अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देशभर में हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज देश में सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की राजनीति है। नकारात्मक राजनीति में चुनाव के गुणा-भाग, गुंडागर्दी और लड़ाई-झगड़े की गूंज है। वहीं, अरविंद केजरीवाल की सकारात्मक राजनीति में जनता के मुद्दों, पढ़े-लिखे लोगों और स्कूल-अस्पताल की राजनीति हैं। इस राजनीति को देश की जनता पसंद कर रही है। हमें इस सकारात्मक राजनीति को देशभर में घर-घर तक लेकर जाना है। आम आदमी पार्टी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हम अपने संगठन को जमीनी स्तर पर लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

● इन्द्र कुमार

राहुल गांधी के प्रति बदल रहा विपक्ष का मिजाज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नगालैंड में सीधे-सीधे तो नहीं कहा है, लेकिन एक तरीके से प्रधानमंत्री पद पर पार्टी का दावा तो पेश कर ही दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी असल में अपने नेता राहुल गांधी की बातों को ही आगे बढ़ाया है, वे बातें जिसमें क्षेत्रीय दलों की विचारधारा को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी सुनने को मिलती रही हैं। हाल ही में पटना में सीपीआई-एमएल लिबरेशन की रैली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से राहुल गांधी तक अपना मैसेज पहुंचाने को कहा था। नीतीश कुमार का कहना था कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए और विपक्ष एकसाथ मिलकर 2024 में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करे। नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके पास विपक्षी दलों के नेताओं के फोन आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वैसी ही बात की है कि विपक्षी दलों से 2024 की रणनीति को लेकर कांग्रेस की बातचीत चल रही है।

कांग्रेस का गढ़ या भाजपा का?

15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, लेकिन हर चुनाव में कांग्रेस हार का अंतर घटाती रही। क्या भाजपा अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव जीतती थी या वोटकटवा और बाहरी मदद से? कांग्रेस ने ऐसा क्या कमाल किया कि 2018 में बड़ी जीत दर्ज की और 13.92 लाख का बड़ा गड्ढ़ा भाजपा के सामने कर दिया। इसे पाटना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन करते हुए बिलासपुर के सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष और जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। साव साहू समाज के हैं, जबकि चंदेल कुर्मी समाज के हैं। छत्तीसगढ़ में साहू और कुर्मी लगभग 30 सीटों पर स्पष्ट रूप में हार-जीत का समीकरण तय करते हैं।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। अब कुछ सीटें ही बाकी रह गई हैं। भेंट-मुलाकात के साथ-साथ वे एक-एक चुनावी मुद्दों को खत्म कर विपक्ष के लिए नई चुनौतियां पेश करते जा रहे हैं। भाजपा के लिए धान का समर्थन मूल्य एक बड़ी चुनौती थी कि अब 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी को 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए न्याय योजनाएं तो हैं ही। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की भी शुरुआत कर दी गई है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी यह जानती है कि यह आसान नहीं है। इस दिशा में भी सरकार ने अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री खुलकर इन मुद्दों पर लोगों से संवाद कर रहे हैं कि वे शराबबंदी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला चुनाव था। अजीत जोगी सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी थी। विद्याचरण शुक्ल एनसीपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के पैरलल अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। इस चुनाव में भाजपा को 37,89,914 वोट मिले थे। यह 39.26 प्रतिशत था। कांग्रेस को 35,43,754 वोट मिले थे और वोट शेयर 36.71 प्रतिशत था। 2,46,160 वोट ज्यादा पाकर भाजपा जीती थी। वोट शेयर में अंतर 2.55 प्रतिशत का था। भाजपा की 50 सीटें थी। कांग्रेस 37, बसपा 2 और एनसीपी के एक विधायक जीते थे। डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे।

भाजपा की सरकार को 5 साल पूरे हो चुके थे। डॉ. रमन सिंह के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। इस बार भाजपा को वोट मिले 43,33,934। कांग्रेस को 41,50,377 और वोटों का अंतर था - 1,83,557। वोट शेयर का प्रतिशत देखें तो भाजपा को 40.33 प्रतिशत और कांग्रेस का 38.63 प्रतिशत वोट मिले। इस बार अंतर 1.7 प्रतिशत का रह गया। भाजपा को फिर 50 सीटें मिलीं। कांग्रेस को एक सीट ज्यादा। यानी इस बार 38 सीटें। बसपा की दो सीटें थीं। दूसरी बार जीत के बाद डॉ. रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे बदले गए। बाकी वही चेहरे थे। भाजपा की 10 साल की सरकार के काम को लोगों ने देख लिया था। डॉ. रमन सिंह भाजपा के पोस्टर बॉय बन चुके थे। चांउर वाले बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे थे। फिर डॉ. रमन के चेहरे पर भाजपा उतरी। इससे पहले झीरम घाटी की घटना हो चुकी थी। लोगों में नाराजगी थी। कांग्रेस के लोग भी मेहनत कर रहे थे। चुनाव परिणाम आया। भाजपा को 53,65,272 वोट मिले। कांग्रेस को 52,67,698 वोट मिले और अंतर रह गया मात्र 97,574। वोट शेयर का प्रतिशत देखें तो भाजपा को 41.04 और कांग्रेस को 40.29 प्रतिशत वोट मिले। फासला था सिर्फ 0.75 प्रतिशत का। तीसरी बार डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। मंत्रिमंडल में कुछ को छोड़कर बाकी चेहरे बने रहे।

अब बात करते हैं साल 2018 की। भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ लोगों में परिवर्तन का मूड बनने लगा था। दूसरी तरफ कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीएस सिंहदेव संघर्ष कर रहे थे। उन्हें जय-वीरू कहा जाने लगा था। यह भी बात आती है कि राज्य के इंटेलिजेंस ने और मातृ संगठन आरएसएस ने राज्य सरकार को आगाह किया कि स्थिति अच्छी नहीं है। तत्कालीन कर्ता-धर्ता इस बात से सहमत नहीं थे। दूसरी ओर भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस का संघर्ष जारी था। घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में टीएस सिंहदेव सब्जी बाजार से लेकर मनरेगा मजदूरों के बीच जा रहे थे। बड़े-छोटे सभी से मिल रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के मुकाबले जब भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया तभी जानकारों ने यह कयास लगाए थे कि भाजपा चूक रही है। जब नतीजा आया, तब सबने देख भी लिया। कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया, जो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन की तरह था। कांग्रेस 68 सीटें जीतीं। 15 साल सत्ता में रही भाजपा सिर्फ 15 सीटें जीत पाई।

सामान्य तौर पर तीन सवाल आते हैं कि भाजपा क्या अपनी योजनाओं से जीतती थी या कोई बाहरी मदद मिलती थी? छत्तीसगढ़ भाजपा का गढ़ बन गया था या पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है? 2018 के चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, वह फिर दोहराया जाएगा या नहीं? इसके जवाब में दुर्गा कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉ. अजय चंद्राकर कहते हैं कि अविभाजित मप्र के समय से ही छत्तीसगढ़ का हिस्सा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। 2003 के चुनाव से यदि देखें तो अजीत जोगी के शासनकाल में कई विवाद सामने आए। लोगों की नाराजगी भी थी। विद्याचरण शुक्ल एनसीपी में चले गए और पैरलल अपने उम्मीदवार उतारे। इसका लाभ भाजपा को मिला।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

मतदाताओं की नाराजगी पड़ेगी भारी

भाजपा शासनकाल में लोगों को मुफ्त चावल देने का ऐलान हो, धान का बोनस देने का ऐलान हो या फिर विकास की योजनाएं, इनका फायदा भाजपा को मिला। हालांकि धान का बोनस देने का वादा कर बाद में भाजपा शासन ने देना बंद कर दिया। इस पूरे समय में कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल को बड़ा समय मिला। जमीनी स्तर पर मजबूती दी। 15 साल तक सत्ता से बाहर होने के बाद आखिरकार 2018 में सबने मिलकर चुनाव लड़ा। घोषणा पत्र ने भी लोगों को आकर्षित किया। खासकर किसानों को। भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी, कांग्रेस के संघर्ष और लुभावने घोषणा पत्र का ही नतीजा 2018 के चुनाव में कांग्रेस की 68 सीटों के रूप में आया। जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन को दोहराने की बात है तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। किसानों के मुद्दे पर भले ही सरकार मजबूत स्थिति में है, लेकिन कर्मचारी वर्ग नाराज है। डीए-एचआरए की मांग पूरी नहीं हुई है। नियमितीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता विधायकों के खिलाफ नाराजगी की बात स्वीकार करते हैं। ऐसे में प्रत्याशी चयन, भाजपा का संगठनात्मक कौशल और उस पर धर्म का तड़का लग गया तो परिणाम चौंका भी सकते हैं।

विपक्षी एकता में आई दरार

कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि सभी विपक्षी दल राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं। खासकर जब उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हुई, तो तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और समाजवादी पार्टी भी उनके पीछे खड़ी दिखाई देने लगी थीं। ये चारों दल वे हैं, जो गैर कांग्रेस, गैर भाजपा की लाइन अपना रहे थे। लेकिन 15 दिन की विपक्षी एकता में दरार पड़ने लगी है। दरार का कारण भी वही राहुल गांधी हैं, जिनकी वजह से विपक्षी एकता होती दिख रही थी। कारण है राहुल का बड़बोलापन। राहुल गांधी को उनकी हद बताने के लिए महाराष्ट्र ने लीड ली है। पहले उद्धव ठाकरे सामने आए थे और अब शरद पवार सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने जब वीर सावरकर के मुद्दे पर स्टैंड लिया था, तब भी शरद पवार ने उद्धव का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने कान पकड़कर वीर सावरकर पर अपनी गलती मान ली थी और भविष्य में सावरकर पर गलत टिप्पणी न करने का आश्वासन दिया था।

भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के दो बड़े मुद्दे क्या थे। अडानी और सावरकर, यही दो मुद्दे थे, इन दो मुद्दों के अलावा वह कुछ नहीं बोले। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सावरकर पर राहुल गांधी की जुबान बंद करवा दी। अब शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेर लिया है। उन्होंने अडानी के मालिकाना हक वाले एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कुछ स्वार्थी तत्व पर्दे के पीछे से गौतम अडानी को टारगेट कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका यह नया स्टैंड राहुल गांधी के खिलाफ तो है ही। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अडानी को लेकर समूचे विपक्ष की जेपीसी गठित करने की मांग के खिलाफ भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठकों में अडानी ग्रुप की जेपीसी से जांच की मांग करने के मुद्दे पर ही तो विपक्षी एकता हुई थी।

बजट सत्र जेपीसी की मांग के हंगामें में बीत गया। लेकिन सत्र खत्म होते ही शरद पवार ने जेपीसी की मांग से किनारा कर लिया। अलबत्ता इस बेकार के मुद्दे पर संसद का सत्र बर्बाद करने के खिलाफ स्टैंड ले लिया। उनके इस स्टैंड से अब अडानी को लेकर हुई विपक्षी एकता तार तार हो गई। यानी विपक्षी दलों की बैठकों में भी जेपीसी को लेकर एक राय नहीं थी, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा था। क्योंकि शरद पवार ने यह भी कहा है कि वह शुरू से ही जेपीसी की मांग के खिलाफ थे। शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग से खुद को अलग करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दोनों मुद्दों की हवा निकाल दी है। इतना ही नहीं उन्होंने बिना हिंडनबर्ग का नाम लिए यहां तक कहा कि ये कौन लोग हैं, हमने तो कभी उसका नाम नहीं सुना था। उनकी कीमत पर देश की अर्थव्यवस्था को कीमत चुकानी पड़ती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए थे, और 7 अप्रैल तक उन्हें 9 लाख 11 हजार 2.2 करोड़ का नुकसान हुआ। शरद पवार ने कहा है कि जानबूझकर किसी साजिश के तहत अडानी ग्रुप को निशाना बनाया गया और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

शरद पवार ने जैसे ही अडानी के मुद्दे पर विपक्षी एकता की हवा निकाली, कांग्रेस बिलबिला उठी है। क्योंकि अब यहीं से राहुल गांधी के नेता बनने की कोशिशों पर पानी पड़ना शुरू होगा। राहुल गांधी ने जैसे 2019 का चुनाव राफेल के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को चोर कहकर लड़ा था, उसी तरह वह इस बार अडानी मुद्दे पर एक नरेटिव बना रहे थे। राहुल गांधी के विदेशों में भी अवांछनीय कारोबारियों से संबंध, गुलाम नबी आजाद ने परिवार को भी घेरा, जिनको मुद्दा बनाकर विपक्ष नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की रणनीति बना रहा है। उनमें से एक मुद्दा अडानी का भी था, जिस पर विपक्षी एकता ही तार-तार नहीं हुई है, बल्कि शरद पवार ने बिना कहे यह भी कह दिया है कि राहुल गांधी किन्हीं अज्ञात विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। शरद पवार के इस आरोप से भाजपा के उन आरोपों की पुष्टि होती है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अडानी के मुद्दे पर एक स्ट्रांग स्टैंड लेकर शरद पवार ने देश को यह भी बताया है कि राहुल गांधी इतने परिपक्व नेता नहीं बने हैं कि उनके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सकती है। कांग्रेस समझ रही है कि शरद पवार ने कहां चोट की है, इसलिए वह बिलबिला उठी है। जयराम रमेश ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि शरद पवार की अपनी राय हो सकती है, लेकिन 19 विपक्षी दल आश्वस्त हैं कि मोदी और अडानी समूह का मुद्दा वास्तविक और बहुत गंभीर है।

● **बिन्दु माथुर**

विपक्षी दलों के भीतर भी मची खलबली

शरद पवार के नए स्टैंड से सिर्फ विपक्षी एकता तार-तार नहीं हुई है, बल्कि विपक्षी दलों के भीतर भी खलबली मच गई है, और उन्होंने एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। अब यह अलग बात है कि जिस न्यूज चैनल को शरद पवार ने इंटरव्यू दिया वह अब अडानी का हो चुका है। लेकिन शरद पवार जैसा नेता न्यूज चैनल पर कुछ कहे या किसी और चैनल पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अडानी का चैनल अडानी के मित्र का इंटरव्यू कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि अडानी को कैसे टारगेट किया जा रहा है। यानी शरद पवार ने विपक्षी दलों में इतनी खलबली मचा दी है कि मोदी के बाद अब शरद पवार को भी अडानी का मित्र बता दिया गया है। हालांकि अब महुआ मोइत्रा का तृणमूल कांग्रेस में क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी भी अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस से सहमत नहीं हैं।

वाकई गहलोत जादूगर हैं

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसे ही राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता है। उन्हें जब भी मौका मिलता है अपनी राजनीतिक जादूगरी के बल पर विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देते हैं। विरोधी चाहे विपक्षी दलों के हों या उनकी खुद की पार्टी के हों। मौका मिलते ही वह किसी को नहीं बख्शते हैं। पिछले काफी समय से उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर तगड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके उपरांत भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक-एक कर अपने सभी विरोधियों को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दिया। अगले विधानसभा चुनाव में मात्र आठ महीने का समय बचा है। इसीलिए गहलोत राजनीति के मैदान में खुलकर खेल रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने का मिथक चला आ रहा है। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले विधानसभा चुनाव में इस मिथक को तोड़कर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना बजट पास करवाते समय राजस्थान में एक साथ 19 नए जिलों व बांसवाड़ा, पाली, सीकर तीन नए संभागों का गठन कर अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।

अभी राजस्थान में 33 जिले कार्यरत हैं। एक नवंबर 1956 को राजस्थान गठन के समय कुल 26 जिले थे। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग कर धौलपुर प्रदेश का 27वां जिला बना था। 10 अप्रैल 1991 को एक साथ 3 जिले कोटा से अलग होकर बारां, जयपुर से अलग होकर दौसा व उदयपुर से अलग होकर राजसमंद जिले का गठन हुआ था। 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना था। 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली को 32वां जिला बनाया गया था। 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा से अलग होकर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। 2008 में प्रतापगढ़ के बाद से राज्य में कोई नया जिला नहीं बन पाया। वर्तमान में राजस्थान की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 40 सालों में प्रदेश की आबादी तो दोगुनी हो गई लेकिन जिले केवल सात ही बढ़े हैं। 1981 तक राजस्थान में 26 जिले थे तब राजस्थान की जनसंख्या करीब 3.6 करोड़ थी। आज के समय में आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन जिले 33 ही बन पाए। आबादी की तरह जिलों की संख्या नहीं बढ़ी। राजस्थान में अंतिम जिला 15 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ बना था। उसके बाद से प्रदेश में लगातार नए जिले बनाने की मांग उठती रही थी। मगर राजनीतिक विरोध की संभावना के चलते किसी भी सरकार ने नए जिलों के गठन का जोखिम उठाना राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं माना और नए जिलों का गठन टलता रहा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला व आबादी के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा प्रदेश है। जिलों की कमी के चलते प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को दूर-दूर भटकना पड़ता है। कई क्षेत्रों में तो जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर की दूरी तक स्थित होने से आमजन को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदेश के आमजन की परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नए जिलों का गठन कर प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलना तय माना जा रहा है।

देश में एक साथ सबसे अधिक जिलों के गठन का रिकॉर्ड भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम हो गया है। अब तक किसी भी प्रदेश में एक साथ 19 जिलों का गठन नहीं हुआ है। प्रदेश में बनाए गए नए जिलों में जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपूतली जिला बनाया गया है। जोधपुर को तोड़कर जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना-कुचामनसिटी, सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलूंबर, जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से शाहपुरा को काटकर नया जिला बनाया गया है। वहीं उदयपुर को काटकर बांसवाड़ा, जोधपुर को काटकर पाली व जयपुर को काटकर सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। इन संभाग मुख्यालयों के तहत कौन-कौन से जिले काम करेंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नए संभागों के गठन में भी क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है। शेखावाटी क्षेत्र से सीकर, मारवाड़ क्षेत्र से पाली और आदिवासी बहुल मेवाड़ क्षेत्र से बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया गया है। नए जिलों के गठन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक समर्थकों के साथ विरोधियों को भी साधा है। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां भी नए जिलों की घोषणा की गई है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

हमेशा नई लीक खींचकर लक्ष्य बनाते हैं गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं-छात्राओं को आने वाले रक्षाबंधन पर 40 लाख स्मार्ट फोन देने की बड़ी घोषणा की है। गहलोत ने बजट के दिन उज्ज्वला से जुड़ी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। यह प्रदेश की महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति है। महिलाओं पर फोकस करते हुए गहलोत ने बजट में राजस्थान रोडवेज की साधरण श्रेणी की बसों में राजस्थान सीमा के भीतर महिलाओं का बस का किराया आधा कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा नई लीक खींचकर लक्ष्य हासिल करने में विश्वास रखते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार का आम बजट पूरी तरह प्रदेश के आमजन की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से बनाया गया है। इसमें आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। चुनावी साल में सभी सरकारें लोक लुभावन बजट पेश करती हैं। इस बार बचत, राहत और बढ़त की थीम के साथ गहलोत द्वारा पेश बजट ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की चर्चा पर जवाब देते हुए कांग्रेस आलाकमान को भी संदेश दे दिया है कि आज भी उनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता बरकरार है। राजस्थान कांग्रेस में वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो विरोधियों को पटकनी दे सकते हैं।

भाजपा का नया मास्टर स्ट्रोक

100 सदस्यीय उप्र विधान परिषद में इसी हफ्ते राज्यपाल की ओर से 6 सदस्य नामित हुए हैं। इसके साथ ही विधान परिषद में भाजपा के 80 सदस्य हो गए हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा चार मुसलमान एमएलसी भाजपा के ही होंगे। पार्टी के पास तीन मुस्लिम एमएलसी पहले से हैं। इनमें अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, मोहसिन रजा और बुक्कल नवाब शामिल हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. तारिक मंसूर को एमएलसी बनाकर सर्वाधिक चार मुस्लिम एमएलसी बनाने का मास्टर स्ट्रोक मारा है। पसमांदा मुसलमानों के बीच पैठ बनाने में जुटी भाजपा ने प्रो. मंसूर को उच्च सदन में भेजकर विरोधियों के साथ खुद मुस्लिमों को भी चौंकाया है। प्रो. तारिक मंसूर की पहचान उदारवादी मुस्लिम विद्वान के तौर पर है। उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहते प्रो. तारिक मंसूर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कट्टरपंथ का केंद्र नहीं बनने दिया। सबसे महत्व की बात यह भी है कि प्रो. तारिक मंसूर के संघ के साथ भी संबंध बहुत मधुर रहे हैं और संघ के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होती रही है। संघ के एक अधिकारी ने बताया कि उनके ज्ञान को देखते हुए हो सकता है सरकार उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे या उन्हें किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

भारतीय मुस्लिमों में पसमांदा मुस्लिमों की आबादी 80 से 85 प्रतिशत के आसपास है। भाजपा मानती है कि पसमांदा मुसलमानों का एक वर्ग भाजपा को वोट दे रहा है। उप्र के 45 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा को 42 हजार वोटों से जीत और मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही है। इस जीत के बाद भाजपा ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में 8 प्रतिशत पसमांदा का वोट भाजपा को मिला था। इसके अलावा सीएसडीएस लोकनीति सर्वे 2022 ने भी अपने रिपोर्ट में बताया है कि 8 प्रतिशत पसमांदा मुस्लिमों ने उप्र विधानसभा में भाजपा को वोट दिया था। पसमांदा मुसलमानों की वजह से भाजपा कई सीटों पर जीतने में सफल रही थी। उप्र विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमांदा हैं।

उप्र की कुल आबादी में पसमांदा मुस्लिम 18 प्रतिशत हैं। ऐसे में साफ है कि भाजपा न सिर्फ 80 लोकसभा वाले उप्र बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी इस समुदाय को अपनी ओर लाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रो. तारिक मंसूर को विधान परिषद भेजने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में मोदी के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को भी उच्च सदन भेजना भाजपा की दीर्घकालीन रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका श्रावस्ती सीट से टिकट तय माना जा रहा था। उस समय अमित शाह ने अपने उप्र प्रवास के दौरान साकेत मिश्रा से उप्र में ध्यान देने को कहा था। तब से यह तय माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में साकेत मिश्रा को उप्र में सक्रिय किया जाएगा। अब उन्हें विधान परिषद भेजकर उसकी शुरुआत की गई है।

साकेत मिश्रा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकॉनोमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके बाद वे आईआईएम कोलकाता पहुंचे। आईआईएम से पढ़ाई के बाद उन्होंने यूपीएससी की तरफ रुख किया, वर्ष 1994 के सिविल सर्विसेज परीक्षा में साकेत मिश्रा ने सफलता दर्ज की। वे आईपीएस बने, लेकिन सिविल सर्विसेज उन्हें रास नहीं आई। उप्र पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य रहे साकेत मिश्रा अब विधान परिषद के जरिए उप्र में राजनीति करेंगे। इसकी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि साकेत मिश्रा वित्त के अच्छे जानकार हैं। वो कई अंततराष्ट्रीय बैंकों के साथ काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने मोदी को कई वित्तीय सुझाव दिए थे जिसे मोदी ने नीति आयोग से लागू करने के लिए भी कहा था।

जानकारों का कहना है कि साकेत मिश्रा को उच्च सदन में भेजकर भाजपा आने वाले दिनों में ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि आने वाले समय में साकेत मिश्रा ब्राह्मणों के भाजपा में सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्र के बेटे को योगी कैबिनेट में आर्थिक प्रबंधन संबंधी अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति

उप्र में भाजपा छोटी से छोटी पिछड़ी जाति को साथ लेकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में भाजपा की विधान परिषद में भेजे गए नाम बताते हैं कि भाजपा सोशल इंजीनियरिंग को बेहद महत्व दे रही है और बेहद योजनाबद्ध तरीके से उसे साध रही है। इसमें एक और अहम नाम हंसराज विश्वकर्मा का है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी रहे हंसराज विश्वकर्मा काशी के भाजपा जिलाध्यक्ष भी हैं। उनको उच्च सदन भेजना इसी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के संगठनात्मक दायित्वों को बेहतर ढ़ग से निभाने के साथ बढ़ई लोहार समाज को भी सकारात्मक संदेश देने की भाजपा ने कोशिश की है। हांलाकि वोट के रूप में यह समाज उप्र में कोई बड़ी ताकत नहीं रखता है लेकिन भाजपा ने महत्व देकर इस समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। दलित मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने दलित चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले लालजी निर्मल को विधान परिषद भेजा है। लालजी निर्मल अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के साथ ही राजधानी में निर्माणाधीन डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे निर्मल का उच्च सदन में जाना भाजपा की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा वैश्य समाज से ताल्लुक रखने वाले रजनीकांत माहेश्वरी को भी उच्च सदन भेजा गया है।

जाति जनगणना का प्रपंच

बिहार के लिए जाति एक विकट प्रश्न है। इसे सीधे समाजशास्त्रियों वाले अध्ययन के तौर पर परिभाषित करने के बदले लोकोक्तियों से उधार लें, तो जाति के बारे में कहा जाता है कि जो कभी नहीं जाती, उसे जाति कहते हैं। बिहार में जाति जनगणना की मांग अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों ने की, हालांकि उससे लाभ क्या होगा, इस विषय पर सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही मौन साध लेते हैं। सड़कों-चौराहों पर होने वाली चर्चाओं की मानें तो कहा जा रहा है कि इस बार भी जब जातीय जनगणना पूरी होगी, तो आम लोगों को जातियों की गिनती नहीं बताई जाएगी। जनता के टैक्स के पैसे से हुई इस जनगणना का अज्ञात लाभ लेने का विशेषाधिकार केवल नेताजी को ही मिलेगा।

वैसे इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो वर्ष के अंत तक पता चल पाएगा, फिलहाल जमीन पर यह दिख रहा है कि पहले चरण में केवल परिवार के मुखिया का नाम और सदस्यों की गिनती पूछी गई और अब कुछ रोज पहले सरकार बहादुर ने हर जाति के लिए एक कोड जारी किया है। इससे पहले कि जनगणनाओं की बात की जाए उससे पहले हम लोगों को सीधे 100 वर्ष से भी पीछे जाना होगा। जब 1911 में बिहार की जनगणना हुई तो जातियों की संख्या थी 205। इस बार जातियों की संख्या 216 हो गई है। ये जातियां बढ़ कैसे गईं, ये समाजशास्त्रियों के लिए एक अलग अध्ययन का विषय हो सकता है। अगर वापस 1911 वाली जनगणना की बात करें तो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार जातियों की संख्या 261 होनी चाहिए, जिसमें से 194 हिंदू जातियां हैं। ये हिंदू जातियां और बाकी की जातियां जैसे ही बताई जाती हैं, तो समाज अपने आप ही एक नए सवाल पर पहुंच जाता है।

बिहार का विभाजन काफी बाद की घटना है इसलिए जब हम लोग 1911 की जनगणना को देखते हैं, तो पाते हैं कि उस समय उत्तर बिहार में आबादी का 83 प्रतिशत और दक्षिण बिहार में 91 प्रतिशत हिंदुओं का था। ईसाई और अन्य मतावलंबियों की गिनती मात्र 0.25 फीसदी थी इसलिए बाकी की आबादी मुहम्मडेन थी ऐसा कहा जा सकता है। अब बिहार का कई बार विभाजन हो चुका है और झारखंड भी अलग राज्य है, इसलिए ये जनसंख्या बदल चुकी है। जातीय जनगणना में जो जातियां नहीं दिख रहीं, उसका एक कारण ये भी था कि जिन जातियों की आबादी जिले में 50,000 से कम थी, और जिन जनजातियों की आबादी जिले में 25000 से कम थी, उन्हें छोड़ दिया गया था। इस सारे जोड़-घटाव के बाद बिहार में केवल सत्रह महत्वपूर्ण जातियां और जनजातियां बचती थीं। जनजातियां मुख्यत: छोटानागपुर इलाके में केंद्रित थीं, इसलिए अब के बिहार की तुलना उस दौर के बिहार से करेंगे तो सिर्फ तेरह की ही तुलना होगी। इसके बाद जब 1931 में जनगणना हुई तब हमें थोड़ी और स्पष्ट तस्वीर दिखती है। इस समय बिहार में ग्वाला (करीब 34.5 लाख), ब्राह्मण (करीब 21 लाख), संथाल (करीब 17 लाख), कुर्मी (करीब 14.5 लाख), राजपूत (करीब 14 लाख), कोइरी (करीब 13 लाख), चमार (करीब 13 लाख), दुसाध (करीब 13 लाख), तेली (करीब 12 लाख), जुलाहा (करीब 10 लाख), बाभन (करीब 10 लाख), मुसहर (करीब 7 लाख), उरांव (करीब 6.4 लाख), भुइंया (करीब 6.2 लाख), मुंडा (करीब 5.5 लाख), और हो (करीब 5.2 लाख) थे।

इस विवरण में ब्राह्मणों और बाभनों की जो दो अलग-अलग संख्याएं दिखती हैं, उसका कारण ये है कि ब्राह्मणों और भूमिहारों (बाभनों) को अलग-अलग जाति माना गया। बाभन बिहार की एकमात्र ऐसी जाति थी जिनकी जनसंख्या 1921-31 के बीच 8.5 प्रतिशत घट गई। श्रीकांत की पुस्तक के अनुसार दरभंगा जिले में एक लाख से भी अधिक (यानि हर तीन में से एक) बाभनों ने अपना नाम ब्राह्मणों के रूप में दर्ज करवा लिया। 1901 में पटना, गया, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर जिलों में बाभनों की आबादी जो 10,99,010 थी वो 1931 में घटकर 8,51,343 रह गई। ये सबसे अधिक दरभंगा में ही दिखा था। दरभंगा में 1931 में ब्राह्मणों की संख्या में 62.34 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस दौर में जिले की कुल आबादी केवल 8.7 प्रतिशत बढ़ी थी। ग्वाला मुख्यत: दरभंगा (करीब 4 लाख) और भागलपुर प्रमंडल के सहरसा-मधेपुरा में केंद्रित थे। कुल 31 दलित जातियों की आबादी 65 लाख के लगभग होती और उसमें से चार जातियों (दुसाध, चमार, मुसहर और भुइंया) की आबादी ही करीब 39-40 लाख थी। दलित जातियां गया, पलामू और मानभूम जिलों में आबादी का 20 फीसदी से अधिक थीं। पटना, शाहाबाद, चंपारण, मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिलों में भी उनकी आबादी 15-20 फीसदी की थी। मुहम्मडेन आबादी में जुलाहे करीब 25 फीसदी थे।

● **विनोद बक्सरी**

करवट ले रही जातिवाद की राजनीति

बहरहाल बिहार जातिवाद की राजनीति को करवट लेते देख रहा है, और प्रतीक्षा में है। लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव नजदीक हैं और ये जनगणना कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाए या न बनाए लेकिन कई समीकरण बिगाड़ जरूर देगी। इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि आंकड़े जो भी होंगे, उन्हें नेता सार्वजनिक करने की बजाय अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। अब जब कोड बांटकर नई जनगणना शुरू हो गई है तो सवाल ये है कि इसके परिणाम किस रूप में सामने आएंगे? इसके लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट वाले दौर को याद किया जा सकता है। बिहार के ही सहरसा जिले के सबसे बड़े जमींदार परिवारों में से एक से आने वाले मंडल ने जो रिपोर्ट 1980 के दौर में दी, उसके आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। इन आरक्षित वर्गों में मंडल, यादव भी शामिल थे। ये रिपोर्ट 50 वर्ष पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाकर देश पर थोपी गई। इसका जो व्यापक राजनीतिक परिणाम हुआ, उसने वीपी सिंह सहित कई समाजवादियों का राजनीतिक भविष्य लील लिया। फिलहाल जो आरक्षित सीटों के नियम लागू हैं, उनमें बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। अगर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए, तो निसंदेह ये मांग भी उठेगी।

खालिस्तान के एजेंडे पर कायम पाकिस्तान

कूटनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं पर फोकस जरूरी

बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन देशों के साथ उस सीमा तक जा पाएगा, जिनसे उसके व्यापक हित जुड़े हुए हैं? जो भी हो, ऐसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए, भले ही वे कुछ तबकों को असहज करें। यह किसी से छिपा नहीं कि एक बड़ी संख्या में भारतीय इन पश्चिमी देशों में वैध या अवैध तरीके से बसना चाहते हैं। इससे इन देशों को भी एक संदेश जाता है। यहां यह अर्थ न निकाला जाए कि इन देशों को अपने कूटनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं के लिहाज से भारत की आवश्यकता नहीं। उन्हें भी भारत की उतनी ही आवश्यकता है और यह पहलू भारत को कुछ बढ़त दिलाता है। हालांकि, समग्रता में देखें तो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के हाथ उन तमाम लोगों की वजह से कुछ बंध जाते हैं, जो इन देशों में बसना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह वहां का वीजा मिल जाए। यह बहस चाहे जहां तक जाए, लेकिन यह तय है कि पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान की गतिविधियां कभी भी भारत के प्रति सिख समुदाय के भरोसे और समर्पण को नहीं डिगा सकतीं। इसका यह अर्थ भी नहीं कि भारत आत्मसंतुष्ट होकर बैठ जाए, क्योंकि अमृतपाल जैसे लोगों की करतूतें देश को क्षति पहुंचा सकती हैं।

खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह इन दिनों जहां-तहां छिपता फिर रहा है। सुरक्षा बलों की यथोचित सख्ती के बाद वह फरार हो गया। उसने वीडियो के जरिए कहा कि वह देश से भागा नहीं है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह भी एक तथ्य है कि भारत के सिख समुदाय में खालिस्तान के लिए कोई समर्थन नहीं है। सिख समुदाय की देशभक्ति असंदिग्ध है। पिछली सदी के नौवें दशक में जिन समस्याओं ने पंजाब को अपनी चपेट में लिया था, उसे बीते हुए काफी वक्त हो गया है। जहां तक अमृतपाल की बात है तो यही खबरें हैं कि उसे पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया। पाकिस्तान का हमेशा यही मकसद रहा है कि हिंदुओं और सिखों में फूट डालकर सिख समुदाय का भारत से मोहभंग कराए। वह अपने इस कुत्सित एजेंडे में कभी कामयाब नहीं होगा। इसके बावजूद वह खालिस्तान के मुद्दे को कायम रखे हुए है। अतीत में भी वह न केवल खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान में पनाह देता रहा है, बल्कि अपने देश से लेकर पश्चिमी देशों में उन्हें पालता-पोसता भी आया है।

कुछ पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों ने पूर्व में अफसोस जताया था कि विभाजन के समय मुस्लिम लीग ने अपने कार्यकर्ताओं को पंजाब में सिखों पर हमले करने और उनकी हत्या करने से नहीं रोका। उनका यही मानना रहा कि नवगठित देश में सिख समुदाय को बने रहने और उनका भरोसा जीतने के हरसंभव उपाय करने चाहिए थे, क्योंकि कालांतर में यह वर्ग पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड साबित होता। हालांकि, ऐसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि सिखों और हिंदुओं के रिश्ते ऐतिहासिक कड़ियों से जुड़े होने के साथ ही हमेशा मजबूत रहे हैं। हिंदुओं और सिखों में 'रोटी-बेटी का रिश्ता' वाली बात कही जाती है।

आदत से मजबूर पाकिस्तान रह-रहकर खालिस्तान के मुद्दे को तूल देता आया है। ननकाना साहिब पहुंचे सिख जत्थों के दौरे पर भी उसने खालिस्तान समर्थकों को दुष्प्रचार करने दिया। भारत की आपत्ति और जत्थे के सदस्यों की नाखुशी के बावजूद खालिस्तानी प्रोपेगंडा जारी रहा। पश्चिमी देशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों के साथ भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां संपर्क में रहती हैं। इन संगठनों के नेताओं को अक्सर पाकिस्तान बुलाकर सम्मानित किया जाता है। पश्चिमी देशों में सिखों को लुभाने और उनमें सद्भावना बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार ननकाना साहिब में बाबा गुरुनानक यूनिवर्सिटी बना रही है।

पाकिस्तान की इन कवायदों का लक्ष्य भारत के प्रति सिखों की भावनाएं भड़काना है। लेकिन यह सभी जानते हैं कि सिखों की भारत के प्रति वफादारी कमजोर करने और खालिस्तान की उनकी मुहिम कभी सफल नहीं होगी। पाकिस्तान के एक राजनयिक से जब यह पूछा गया कि जब पंजाब सीमा पर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं तो पाकिस्तान क्यों खालिस्तान के मुद्दे को भड़का रहा है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी से जवाब मिल गया कि पाकिस्तान कभी यह मुद्दा नहीं छोड़ेगा। राजनयिकों के बीच अक्सर ऐसे अनौपचारिक संवाद होते हैं, जिनसे इरादों की झलक मिलती है। जब ऐसे मुद्दे औपचारिक रूप से उठाए जाते हैं, तब आधिकारिक रुख रखा जाता है।

अब अमृतपाल और उसके संगठन पर कार्रवाई के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान **समर्थकों** की प्रतिक्रिया कहीं न कहीं यही दर्शाती है कि भारत से बाहर खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों को पाकिस्तान का सहयोग मिला हुआ है। ये पश्चिमी देश उस वियना कन्वेंशन का अनुपालन करने में भी नाकाम रहे हैं, जिसमें दूसरे देश के प्रतिष्ठानों, राजनयिकों और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा का पूरा दायित्व मेजबान देश का होता है। ऐसे में भारत की नाराजगी और आपत्ति बिल्कुल उचित है। खासतौर से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को खासी शह मिली है, जहां अभिव्यक्ति के अधिकार की आड़ में वे इसकी गुंजाइश लेते हैं, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता उस हद तक नहीं दी जा सकती, जो मित्र देशों की क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने वाली हो।

कुछ सिख समूह पाकिस्तानी मदद से बुने गए जाल में भी फंस गए हैं। वहां कई निर्वाचन क्षेत्रों में सिख समूहों के प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक दल भी मजबूर दिखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत खालिस्तान की इस मुहिम को कैसे काबू करे? उसे पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना होगा कि वे ऐसे उपाय करें, जिनसे अराजक समूह भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने में सफल न हो सकें, ताकि लंदन में भारतीय उच्चायोग और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की पुनरावृत्ति न हो। भारत को कनाडा को स्पष्टता से कह देना चाहिए कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को एक कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने जैसी घटनाएं कतई अस्वीकार्य हैं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

रूस और यूएस के बीच बढ़ी टकराहट

रूस के लड़ाकू विमान से गत दिनों अमेरिका का मानवरहित निगरानी ड्रोन टकरा गया था। ये टक्कर ब्लैक सी के ऊपर हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून की अनुमति होगी अमेरिकी विमान वहां उड़ेंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रूस को चेतावनी दी कि उसके जेट की वजह से अमेरिकी ड्रोन मार गिराया गया। इसके बाद वो आगे से सावधानीपूर्वक काम करें।

रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ब्लैक सी के ऊपर ड्रोन वाले मामले के तुरंत बाद घटना के बारे में रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु के साथ फोन पर बात की। दो रूसी लड़ाकू विमान की वजह से मानवरहित अमेरिकी निगरानी ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें ड्रोन के प्रोपेलर को नुकसान पहुंचा। वहीं टकराने के तुरंत बाद अमेरिकी निगरानी ड्रोन नीचे के पानी में गिर गया। इस घटना के बाद अमेरिका ने इसे लापरवाह और अनप्रोफेशनल करार दिया, जबकी रूस ने अमेरिका के आरोपों का खंडन करते हुए इनकार किया और अमेरिका पर ही क्षेत्र में गलत धारणा के साथ उड़ान भरने का आरोप लगाया।

यूएस डिफेंस सचिव ऑस्टिन ने शोइगु के साथ कॉल के बाद मीडिया से कहा कि अमेरिका को जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून की अनुमति मिलेगी, वहां वो उड़ान भरेगा और अपने काम को जारी रखेगा। अब ये रूस पर निर्भर करता है कि वो अपने सैन्य विमानों को सुरक्षित और पेशेवर तरीके से संचालित करे। अमेरिकी संयुक्त प्रमुखों के अध्यक्ष मार्क मिले ने कहा कि पेंटागन अभी भी ड्रोन से वीडियो और डेटा का विश्लेषण कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें नहीं पता कि ये जानबूझकर किया गया था या नहीं। मिले ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते हैं कि ये रूकावट जानबूझकर पैदा की गई थी। ये उनके तरफ से आक्रामक व्यवहार जानबूझकर किया गया था। हम यह भी जानते हैं कि यह बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत अनसेफ था। रूस-यूक्रेन युद्ध के एक साल बाद अमेरिका का रूस से किसी मुद्दे को लेकर बात करना और उस पर से दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क बेहद दुर्लभ है। इस पर रक्षा सचिव ऑस्टिन ने कहा कि हम तनाव बढ़ने की किसी भी संभावना को बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसलिए मेरा मानना है कि संचार के रास्ते खुले रखना महत्वपूर्ण है। दरअसल ये दुर्घटना तो छोटी थी और इंटरनेशनल एयरस्पेस में हुई थी। हमने अनुमान भी लगाया कि अगर ये इंटरनेशनल एयरस्पेस में नहीं होता या इंटरनेशनल वॉटर्स के ऊपर नहीं होता तो क्या होता। इसी प्रकार की दुर्घटनाएं दुनिया को युद्ध के कगार पर ले आती हैं। अगर आपको याद हो कि एक दुर्घटना ही थी, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी।

इस तरह की दुर्घटनाओं को हम ये नहीं कह सकते हैं होगी ही नहीं, या ऐसी आशंकाएं निर्मूल हैं, ऐसी होती रहेंगी। सवाल है कि दोनों देश कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जो विशेष घटना, जिसकी अभी चर्चा हो रही है उसमें अमेरिका का कहना है कि एमक्यू-9 उनका ड्रोन है। दो रूसी फाइटर प्लेन्स ने उनका 30 से 35 मिनट तक पीछा किया या उसके चारों तरफ घूमे। उन पर जो ईंधन होता है वो गिराया ताकि उसको किसी तरह नष्ट किया जा सके।

रूसी कहते हैं कि ये उनके टेरिटरी की तरफ यानी यूक्रेन से कैप्चर वाले क्रीमिया की तरफ बढ़ रहा था। वो नहीं चाहते थे कि वो उसके एयरस्पेस में जाए। लेकिन ये सिर्फ अनमैन्ड एरियल वीकल नहीं है। जिन रूसी टोही विमानों ने उसको गिराया है, पहले अंदाजा लगाया है कि एमक्यू-9 में एक अपाचे हेलिकॉप्टर जितनी 16 मिसाइलें भरी जा सकती हैं। ये पूरी तरह से एक उकसावे वाली कार्यवाही थी जो अमेरिका ने की थी और जो दिख गया। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अनमैन्ड एरियल वीकल से देखा जाता है कि ब्लैक सी से कई बार रूस ने क्रूज मिसाइल छोड़ी है। उसका अनुमान लगाने के लिए भी ये किया जाता है। रूस ने अपनी तरफ से कहा है कि यह उतनी सीरियस घटना नहीं है, लेकिन अमेरिका इसको सीरियस घटना मान रहा है। ऐसी दुर्घटनाओं का इतिहास भी रहा है। जैसे अगर 2015 में हम देखें तो सीरिया तुर्की के बॉर्डर पर एक रूसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया था। उस समय तुर्की चूंकि नाटो का सदस्य है तो रूस में कोई लड़ाई जैसी बात नहीं हुई। लेकिन अभी विश्व एक ऐसे मुहाने पर है जहां युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा है, खासकर रूस और अमेरिका का आमने-सामने आना एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मान लीजिए इसमें 16 हार्पून मिसाइल होती जो जेनरली अनमैन्ड एरियल वीकल कैरी करते हैं तो क्या होता। दुर्घटनाओं पर अगर ध्यान न दिया जाए, अगर सिर्फ इस घटना पर ही ध्यान दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी घटना है।

● **कुमार विनोद**

दोनों देशों को संयम रखने की जरूरत

पूरे युद्ध प्रकरण में अगर देखें तो ड्रोन्स का महत्व बहुत बढ़ गया है। उस लिहाज से हो सकता है कि आगे भी ऐसी घटनाएं हों। अगर इंटरनेशनल वॉटर्स में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या इंटरनेशनल एयरस्पेस में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही टोही ड्रोन अगर यूक्रेन में टकराया होता अमेरिकी प्लेन से तो शायद चीजें अलग तरह से देखी जातीं। लेकिन इस तरह की चीजें सबको पता है कि रूस भी करता है, अमेरिका भी करता है। इस तरह के इंटरसेप्शन का, इस तरह के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का। जब क्रूज मिसाइल या अन्य मिसाइलें छोड़ी जाती हैं जो आजकल रिमोटली कंट्रोल होती हैं उनमें सैटेलाइट्स का और ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। उनके रास्ते को, उनकी स्पीड को उनके घुमाव को वो देखते हैं। वैसे लग रहा है कि दोनों देशों ने संयम से काम लिया है। अब तक बहुत संयम से काम लिया है। लेकिन अमेरिका का नुकसान हुआ है। वो अपनी जनता को दिखाना चाहता है या नाटो को दिखाना चाहता है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने संयम से काम लिया। रूस ने तो बिलकुल डाउनप्ले किया है। हालांकि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस में रूस ये दिखाएगा कि देखो हमने अमेरिका का एक ड्रोन गिराया है।

महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की जरूरत

महिलाओं में वित्तीय साक्षरता न होने के दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो यह कि महिलाएं रुपए-पैसे के लेनदेन में पूरी तरह पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाती हैं। उनको ऐसा कुछ भी काम करने का आत्मविश्वास ही नहीं रहता और किसी वजह से वे रिश्तेदार नहीं रहते, तो उनका पूरा वित्तीय कामकाज ठप्प हो जाता है। दूसरे, वित्तीय साक्षरता की कमी की जिम्मेदार कई बार खुद कुछ महिलाएं भी होती हैं। वे इस काम को सीखने और करने में आलस करती हैं। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, मगर फिर भी कई मामलों में वे पीछे रह जाती हैं। उनमें एक मुख्य क्षेत्र है महिलाओं की वित्तीय साक्षरता का। इस मामले में न केवल गरीब, ग्रामीण और अनपढ़ महिलाएं पीछे हैं, बल्कि शहरी मध्यवर्ग और उच्च वर्ग की पढ़ी-लिखी महिलाओं में भी वित्तीय साक्षरता और जानकारी का अभाव देखा जाता है।

'ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर' (जीएफएलई) द्वारा 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वयस्क आबादी का केवल चौबीस प्रतिशत वित्तीय मामलों में साक्षर है। अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की **वित्तीय साक्षरता** दर सबसे कम है। महिलाओं के मामले में तो स्थिति और चिंताजनक है। यह राज्यवार 4 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे महानगरीय क्षेत्रों में क्रमश: 17 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की वित्तीय साक्षरता दर है। बिहार, राजस्थान, झारखंड और उप्र जैसे राज्य, जहां गरीबी अधिक है, वहां साक्षरता दर कम है। ये आंकड़े अंतरराज्यीय असमानताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। गोवा में महिलाओं की 50 प्रतिशत की उच्चतम वित्तीय साक्षरता दर है, जबकि छत्तीसगढ़ में वित्तीय साक्षरता की भारी कमी है। वहां वित्तीय साक्षरता दर सबसे कम, मात्र 4 प्रतिशत है। आजकल जब बैंकों के माध्यम से लेनदेन बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का चलन आम हो गया है और अब तो इसके आगे 'कैशलेस' लेनदेन पर जोर बढ़ रहा है, तब महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बैंक के सामान्य कामकाज भी नहीं कर पाता। बैंक में रुपया जमा कराने या निकालने का काम हो या एटीएम कार्ड का उपयोग करना, सभी कामों के लिए अधिकांश महिलाएं अपने पति, पुत्र, भाई या किसी अन्य रिश्तेदार पर निर्भर हैं। इसका महिलाओं को कई बार खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। उनके खाते से बड़ी रकम का गबन भी हो जाता है। कम निकालने का कहकर ज्यादा रकम उनके खाते से निकाल ली जाती है। एटीएम का गलत उपयोग कर लिया जाता है। बिना उस महिला की जानकारी के उसके खाते में अपना नामांकन करा लिया जाता है। खाली चेक पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, फिर मनमानी रकम भरकर निकाल ली जाती है।

थोड़ा बहुत ऑनलाइन व्यवहार करने वाली महिला को 'रिवार्ड पाइंट' के आधार पर या नकद राशि मिलने के नाम पर 'ओटीपी' मांग कर या कोई लिंक भेजकर उस पर क्लिक करवाकर उसके बैंक खाते में जमा रकम साफ कर दी जाती है। इस तरह की बहुत-सी घटनाओं की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। अधिकतर मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती और पीड़िता का पैसा डूब जाता है। कई बार महिला के पुरुष रिश्तेदार जानबूझकर उसे बैंक की कार्यप्रणाली से परिचित होने नहीं देते। महिलाओं में वित्तीय साक्षरता न होने के दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो यह कि महिलाएं रुपए-पैसे के लेनदेन में पूरी तरह पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाती हैं। उनको ऐसा कुछ भी काम करने का आत्मविश्वास ही नहीं रहता और किसी वजह से वे रिश्तेदार नहीं रहते, तो उनका पूरा वित्तीय कामकाज ठप्प हो जाता है। दूसरे, वित्तीय साक्षरता की कमी की जिम्मेदार कई बार खुद महिलाएं भी होती हैं। वे इस काम को सीखने और करने में आलस करती हैं। कुछ तकनीकी बातें सीखने और समझने की कोशिश ही नहीं करतीं। इस उदासीनता का नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। जब बैंक आदि के सामान्य कामों में महिलाओं की यह स्थिति है तो भला वे निवेश कहां करना है, कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है, कितना बीमा करवाना है जैसी बातों की उनसे जानकारी की अपेक्षा करना तो बेमानी है। इस कारण भी महिलाएं गलत जगह और गलत आदमी के माध्यम से निवेश करके या तो अपना पैसा डुबा देती हैं या फंसा लेती हैं।

आजकल विधवा और परित्यक्ता महिलाओं द्वारा एकाकी जीवन बिताने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनको अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह, आवास निर्माण आदि कार्यों के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ती है। बचत न होने के कारण उनको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। वित्तीय साक्षरता के अभाव में वे सेठ-साहूकारों या निजी संस्थाओं के चंगुल में फंस जाती हैं। वहां उनको भारी ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ सकता है, जिसको चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि उनकी संपति कुर्क होने की नौबत आ जाती है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

उपयुक्त बीमा कवर होना भी जरूरी

एक मजबूत वित्तीय शिक्षा की व्यवस्था महिलाओं को प्रभावी ढंग से अपनी बचत और निवेश का प्रबंधन करने में सहायक हो सकती है। इससे वे अपनी बचत को इस प्रकार निवेश कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने अधिक से अधिक लाभ मिल सके और जमा राशि भी सुरक्षित रहे। इसी प्रकार महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उनका उपयुक्त बीमा कवर होना भी जरूरी है। बीमारी की दशा में इलाज पर खर्च होने वाली भारी-भरकम राशि की व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य बीमा का कवर भी जरूरी है, ताकि उनको और उनके परिवार को बीमारी की दशा में इलाज करवाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह भी महिलाओं की वित्तीय साक्षरता द्वारा ही संभव है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के आम बजट में लोगों में आर्थिक साक्षरता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी स्वयात्तशासी संस्थाओं के माध्यम से इस दिशा में प्रयास के प्रावधान किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता योजना' नामक एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षाकर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों में केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025 बनाई गई है।

मानव सभ्यता के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं राम

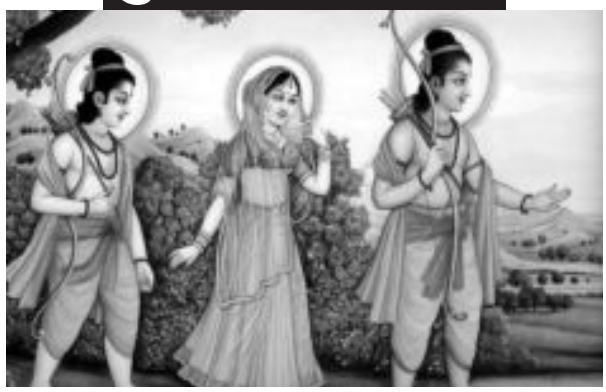

चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। हालांकि भारत में राम के अस्तित्व को लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी गई। राम के ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के विमर्श में विभिन्न तथ्य पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही ढूंढे। उनके आधार पर तर्क गढ़े गए। और आज भी राम की वास्तविकता, आध्यात्मिकता और उनके विष्णु अवतार स्वरूप, मात्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सनातनधर्मियों के लिए आधार स्तंभ है। जब हम राम की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बात आती है-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा के श्रेष्ठ उदाहरण की। मर्यादापुरुषोत्तम राम न सिर्फ भारतीय राज्यों में प्रतिस्थापित हैं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों विशेषकर नेपाल, लाओस, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरीशस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि की लोक-संस्कृति और ग्रंथों में भी राम उसी भाव से प्रतिष्ठापित हैं। श्रीराम ऐसे अवतारी चरित्र हैं जो सनातन संस्कृति की चेतना की प्रदीप्त लौ हैं। जो इस संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए हुए है।

यह विडंबना ही है कि राम जन्मभूमि को लेकर उसी क्षेत्र में विश्वास-अविश्वास की बहस होती है, जहां जनमानस राम को अपना आराध्य होने के साथ-साथ उन्हें अपना पूर्वज और पितृ पुरुष भी मानते आए हैं। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम से मिशनरी प्रचार के लिए भारत आए ईसाई फादर कामिल बुल्के श्रीराम की प्रमाणिकता पर शोध करते हैं। तार्किक व वैज्ञानिक प्रविधि आधारित उनका शोध संकलन 'रामकथा: उत्पत्ति और विकास' इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राम वाल्मीकि के कल्पित पात्र नहीं, बल्कि इतिहास पुरूष थे। राम का जन्म स्थान वर्तमान भारत के अयोध्या में माना गया। जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। किंतु राम की चेतना और उनका चरित अर्थात् रामकथा मात्र भारत में नहीं, बल्कि यह देश की सीमाओं से परे अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक अवबोधन से संपृक्त कथा है। इससे संबंधित हॉलैन्ड के डॉक्टर होयकास का एक प्रसंग उद्धृत किया जाने योग्य है। डॉ. होयकास संस्कृत और इंडोनेशियाई भाषाओं के विद्वान थे। एक दिन वह केंद्रीय इंडोनेशिया में शाम के समय टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक मौलाना जिनके बगल में कुरान रखी है, इंडोनेशियाई रामायण पढ़ रहे थे। डॉ. होयकास ने उनसे पूछा, मौलाना आप तो मुसलमान हैं, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं। उस मौलाना ने एक वाक्य में इस बात का उत्तर दिया- और भी अच्छा मनुष्य बनने के लिए! विभिन्न शोध में यह सामने आया कि पूरी दुनिया में रामायण से संबंधित लगभग 300 से अधिक रूप आज भी प्रचलित हैं। इस संबंध में आज भी कई शोध चल रहे हैं। काल गणना के अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर की सहायता से नवीनतम शोध के अनुसार श्रीराम के जन्म का दिन और समय अभी के प्रचलित कैलेंडर के अनुरूप निकाला गया है। इसके अनुसार 5114 बीसीई, 10 जनवरी के दिन दोपहर 12.05 पर भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। वेदों पर वैज्ञानिक शोध करने वाले संस्थान आई-सर्व ने यह शोध प्रकाशित किया है। हालांकि कुछ शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि श्रीराम का जन्म 7323 बीसीई में हुआ था। चैत्र मास की नवमीं को रामनवमीं के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार को हिंदू पंचांग अपने काल गणना में सूर्य-चंद्र नक्षत्रीय गणना को दिनमान के समय घटा बढ़ाकर समाविष्ट करते हैं। यह दिनमान का अंतर 72 वर्ष में 1 डिग्री का होता है। जो कालगणना में लगभग 80 से 100 वर्षों में पूरे 24 घंटे का हो जाता है। इसी कारक के प्रभाव से अभी का प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर में सूर्य गणना आधारित हिंदू पर्वों की तारीख में भेद होता है। जैसा कि मकर संक्रांति के संबंध में देखा जा सकता है। राम जन्म की वास्तविक गणना निकालने के लिए कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने वाल्मीकि द्वारा रामजन्म के समय बताए गए ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से जो डेट निकाली है। वह 4 दिसंबर 7323 बीसीई (ई.पू.) अर्थात् आज से 9339 वर्ष पूर्व संभावित है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में बाल कांड 18/श्लोक 8, 9 के अनुसार श्रीराम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी उद्धृत किया है कि उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र में पांच ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री अंश, मंगल मकर में 28 डिग्री अंश, ब्रहस्पति कर्क में 5 डिग्री अंश पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री अंश पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री अंश पर था। राम के जन्म की भारतीय पंचांग तिथि तो नियत है। पर राम नाम के अर्थ और महत्व को लेकर भी कई विमर्श होते हैं। राम वास्तव में क्या हैं? राम अग्नि, पुरुष, ऋतु, शक्ति को सहज धारण करने वाले मर्यादापुरुषोत्तम के प्रतीक हैं! भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द दो बीजाक्षरों अग्नि बीज और सोम बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर मस्तिष्क, शरीर और चेतना को शक्ति प्रदान करते हैं। बीज अक्षर ही लाखों मंत्रों को प्राण ऊर्जा देते हैं। बिहार शरीफ में रामनवमीं की हिंसा में कैसे उजड़ गया एक गुलशन इस आधार पर कहा गया है कि राम नाम का तीन बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान है। यह महाभारत में भी वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम तीन बार उच्चारण करने से सहस्त्र देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शिव स्वयं भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। राम स्वर ध्वनि विज्ञान के बीज अक्षर में वाक ऊर्जा का सूत्र है। पौराणिक आख्यान असल में कालातीत यथार्थ होते हैं। इसे सत्य और असत्य की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इतिहास होने के लिए जो समय सीमा की निश्चितता है, ऐसे प्रसंग उस देश काल निर्धारण के परे लोक के लिए सर्वकालिक, सार्वभौमिक रूप में स्थापित हो जाते हैं। राम भी उसी प्रकार विभिन्न ग्रंथों में, भिन्न काल में देश की सीमाओं से ऊपर लोक के मानस में व्याप्त हैं। राम का अर्थ है प्रकाश। किरण, कांति एवं आभा जैसे शब्दों के मूल में राम है। अग्नि तत्व बीज अक्षर रा का अर्थ है आभा और सोम तत्व बीजाक्षर म का अर्थ है मैं, मेरा और मैं स्वयं। अर्थात् मेरे भीतर प्रकाश, मेरे अनाहत् में प्रकाश। रामायण एक शाश्वत कथा के रूप में लोक मानस में अंकित है। हम सब भी रामचरित के प्रसंग सुनते हुए बड़े हुए हैं। जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हमारे दादी-नानी के बचपन में रहे होंगे। रामायण का भावार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। रामकथा आभ्यंतरिक प्रकाश अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की अनुशंसा करता है। आत्मज्ञान से ही सभी प्रकार की नकारात्मकता और मन के विरूपण पर नियंत्रण संभव हो सकता है। राम को अन्य किसी विशेषण से नहीं अलंकृत नहीं किया गया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम की कथा, मर्यादा के साथ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है। यही सनातन धर्म है और राम इस धर्म के कालातीत सर्वस्वीकृत सर्वोच्च लोकनायक।

● **ओम**

दोष

संजना कई दिनों से अनमने-सी थी। अपने पिता और भाइयों से थोड़ी नाराज। पिछले कुछ दिनों से न तो पिताजी का फोन आ रहा था ना ही किसी भाई-भाभी का। वह सोच-सोच के परेशान हो रही थी ऐसा उसने क्या कर दिया की मायके वालों ने उसकी सुध ही लेनी छोड़ दी। मां के गुजरने के बाद मानो सबकुछ बदल गया, पिताजी के रवैए में भी अजीब परिवर्तन आ गया है।

कई दिनों से इंतजार करने के बाद संजना से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने ही पिताजी को फोन किया पापा आप कैसे हैं? भैया-भाभी कैसे हैं!

मैं ठीक ही हूं, तुम्हारी मां के जाने के बाद यहां पर बहुत अच्छा कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारी भाभियों की मनमानी बढ़ गई है दिनेश और कैलाश दोनों ही अपनी पत्नियों से परेशान रहते हैं। गहरी सांस लेते हुए पिताजी ने कहा।

आप भाभियों को क्यों दोष दे रहे है? दिनेश और कैलाश भैया के रवैए में कितना परिवर्तन आ गया है, पहले तो हमेशा मेरे पास फोन कर हालचाल पूछते रहते थे अब तो कई-कई महीने हो जाते हैं उनसे बातचीत हुए, कभी मैं फोन करूं तो ठीक से जवाब तक नहीं देते।

इसमें इन बेचारों क्या दोष? बहुओं ने उनका जीना मुहाल किया है, सारा दिन उनसे बिना बात के झगड़ती रहती हैं उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देतीं। हमने गलत लड़कियों को अपने घर की बहू बना लिया है। नाराज होते हुए पापा ने कहा।

संजना सोचने लगी पिताजी कैसे सारा दोष बहुओं पर लगाकर बेटों को मासूम बता रहे हैं। क्या हर वक्त बहुएं ही गलत होती हैं?

- विभा कुमारी 'नीरजा'

किसको फिर से राम बनाऊं

सोच रहे हैं नारायण भी
कैसे भारत भूमि बचाऊं
हर युग में अवतार धरूं क्या
बार-बार धरती पर आऊं
आज सनातन शिथिल पड़ा है
कैसे उसको पुन: जगाऊं
कौन बनेगा तारणहारा
किसको फिर से राम बनाऊं
राम बहुत चिंता में बैठे
देख विधर्मी के दल को
व्याकुल होकर आज देखते
बलशाली होते खल को
दुष्ट बहुत इतराया घूमे
सहमा-सहमा सनातनी है
राम नाम लेने भर से ही
आर्यावृत में तनातनी है
कितना रक्तिम दिनकर होगा
कितना शोणित और बहेगा
कितनी लाशों पर रूदन का
कष्ट सनातन और सहेगा
अंधकारमय कल दिखता है
किसको अपनी व्यथा सुनाऊं
कौन बनेगा तारणहारा
किसको फिर से राम बनाऊं

- मनोज डागा राजस्थानी

कहां गए वो दिन

आज बहुत दिन बाद मंजरी मायके जा रही थी। वह देश से ही बाहर थी। जब भारत लौटी अपने सब काम से निपटकर सोचा चलो बहुत साल बाद आई हूं पूरे परिवार से मिलती हूं। फोन पर सबकी बातें पता चल जाती थी फिर भी लंबी बात नहीं होती थी। मां का स्वर्गवास हो गया। बड़ी मां और बड़े पापा भी नहीं रहे। बहुत रोई थी वह। जैसे ही उसे पुनीत से पता चला कि अब वह भारत जाकर रहेंगे तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा।

पुराने दिन याद आते रहे तीनों चाचियां, मां और बड़ी मां सब कितने मिलजुल कर रहते थे। सब त्यौहार पर क्या गजब का हंगामा होता था। घर में इतने भाई-बहन मस्ती ही मस्ती। उसके दोनों भाईयों की शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई और वह विदेश चली गई।

आज जब वह स्टेशन उतरी तो बस जल्दी सबसे मिलने की थी। घर पहुंची एक अजीब सी शांति थी आंगन में दीवार लग गई थी। दोनों भाभियां और बच्चे आंगन में आ गए पर चेहरों में अधिक उल्लास नहीं। थोड़ी सी बात करने के बाद बड़ी भाभी ने मंजरी से कहा- 'दीदी आप छोटी के पास रूकेंगी या मेरे पास?'

मंजरी एकदम सन्नाटे में आ गई वह बोली- 'क्या तुम दोनों साथ नहीं रहती और चाचियां कहां हैं?'

बड़ी भाभी ने कहा- 'अरे सब अलग रहते हैं इतना बड़ा परिवार कैसे साथ रह सकता है। हमारी अपनी जिंदगी है।'

वह सोच रही थी मैं इतने साल बाहर रही वहां परिवार के लिए तरस गई सब भाई-बहनों के साथ बिताए पल याद आते रहे यहां सब पाश्चात्य संस्कृति में रंग गए। कहां गए वो दिन।

- डॉ. मधु आंधीवाल

संघर्ष का नाम है रिंकू सिंह

> *दुनिया का दस्तूर यही है कि जब इंसान कामयाब होता है तो उसके बारे में खूब बातें होती हैं। लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। रिंकू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मीडिया के कैमरों ने रिंकू को घेर लिया है। हर कोई उनसे कामयाबी का मूल मंत्र सीखना चाह रहा है।*

आईपीएल 2023 में गुजरात के खिलाफ अंतिम ओवर में 5 छक्कों की बदौलत 31 रन जुटाना और 3 विकटों से मैच अपने नाम करना भर था। क्रिकेट फैंस के बीच रिंकू-रिंकू की सदाएं गूंज रही हैं। चाहे वो रणवीर सिंह और शाहरुख खान जैसे सितारें रहे हों, या फिर देश का आम आदमी, जिस तरह बीते दिनों स्टेडियम में रिंकू के बल्ले ने आग उगली, हैरत में हर आदमी है। चर्चा तेज हो गई है कि यदि रिंकू ने ऐसा ही प्रदर्शन आगे भी बरकरार रखा तो शायद ही कोई उन्हें या उनके खेल को पकड़ पाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि रिंकू ने अपने खेल की बदौलत इतिहास रचा है लेकिन सोशल मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। रिंकू के मामले में दुर्भाग्यपूर्ण ये देखना है कि सोशल मीडिया विशेषकर ट्विटर पर रिंकू का खेल नहीं बल्कि उनकी जाति सुर्खियों में है।

चूंकि दुनिया का दस्तूर यही है कि जब इंसान कामयाब होता है तो उसके बारे में खूब बातें होती हैं। लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। रिंकू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मीडिया के कैमरों ने रिंकू को घेर लिया है। हर कोई उनसे कामयाबी का मूल मंत्र सीखना चाह रहा है। रिंकू सिंह कैसे इस मुकाम पर पहुंचे? इसे समझने के लिए हमें उस वीडियो को देखना होगा जो कोलकाता नाईट राइडर्स ने यूट्यूब पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में रिंकू ने अपने क्रिकेट कैरियर के शुरूआती दिनों पर बात की है और बताया है कि कैसे तमाम चुनौतियां थीं जिनको पार लगाते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं।

ध्यान रहे रिंकू उप्र के अलीगढ़ के एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां संसाधनों के नाम पर यदि कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष हैं। परिवार भी कैसा है इसे ऐसे समझिए कि परिवार में पिता हॉकर हैं। मां हाउस वाइफ क्योंकि रिंकू के कई भाई थे और पिता अकेले ही सबकी चटनी रोटी का भार अपने कंधों पर उठाए थे तो उन्हें कभी भी रिंकू का क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगा।

पिता यही चाहते थे कि जब वो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं तो बच्चे भी पढ़ाई करें। शायद आपको जानकर हैरत हो, रिंकू के जीवन में कई मौके ऐसे भी आए जब उन्हें सिर्फ इसलिए पिता द्वारा बुरी तरह मारा गया क्योंकि उनके हाथ में बल्ला था और वो कहीं से मैच खेलकर आए थे। रिंकू का मामला देखते हुए हमें इस बात को भी अपने जेहन में रखना होगा कि उसके घर वालों को उसका क्रिकेट इसलिए भी नहीं पसंद था क्योंकि वो लोग बेहद गरीब थे, उनके सामने चुनौती रोटी थी। हर वक्त प्रश्न ये रहता था कि चलो आज का तो हो गया अब आगे क्या होगा?

खेल के लिहाज से कभी भी रिंकू को अपने पिता का समर्थन नहीं मिला, हां लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो अपनी मां को समझाने में कामयाब हुए और उनके जीवन में कुछ एक मौके ऐसे भी आए जब टूर्नामेंट की एंट्री फीस देने के लिए उनकी मां ने आस पड़ोस के लोगों से पैसे उधार लिए। आज हम भले ही रिंकू की तारीफों के पुल बांध रहे हों लेकिन भारत जैसे देश में एक गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे का खेल की दुनिया में जाना आसान नहीं है। खुद सोचिए, जो लड़का अपनी प्रैक्टिस के लिए अच्छे स्टेडियम नहीं जा सकता, यदि वो कामयाब हुआ है तो कारण बस ये है कि उसने खूब मेहनत की और हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा किया।

अपने इंटरव्यू में रिंकू ने इस बात को भी बताया है कि, मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया इसलिए कहीं न कहीं सारी उम्मीदें क्रिकेट से ही थीं, मुझे विश्वास था कि यही मुझे आगे ले जाएगा। बस फिर पूरा फोकस और मेहनत खेल में लगा दी और आज लग रहा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। रिंकू का परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था इसलिए रिंकू ने नौकरी करने का भी फैसला किया। उन्हें एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू-पोछा लगाने का काम मिल गया। लेकिन उनका दिल क्रिकेट में ही लगा रहता था। इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं की और तमाम तरह की आलोचना का सामना करते हुए अपना सारा ध्यान क्रिकेट में ही लगाया। कह सकते हैं कि भले ही आज अपने अंतिम ओवर में 5 छक्के मारने के बाद रिंकू सिंह सुर्खियों में आए हों लेकिन जैसा उनका जीवन रहा उन्होंने समय-समय पर छक्के जड़े और आगे बढ़ते गए।

बाकी विषय रिंकू की जाति से शुरू हुआ तो यदि हम रिंकू के जीवन को देखें तो उसमें हमें तमाम रंग दिखते हैं। चाहे वो कोच के रूप में मसूद अमिनी रहे हों या फिर मोहम्मद जीशान, अर्जुन सिंह फकीरा, स्वप्निल जैन और अनिल सिंह इन सभी लोगों ने रिंकू के टैलेंट को न केवल पहचाना बल्कि उसे आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर रिंकू का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिनमें आगे बढ़ने की ललक है और जो बिना रुके मेहनत का दामन थामे आगे जाना चाहते हैं।

● **आशीष नेमा**

...तो सलमान खान नहीं, गोविंदा होते सुपरहिट फिल्म का हिस्सा

भाईजान ने पहली बार डबल रोल निभाकर फैंस का जीता था दिल

गोविंदा आज भले ही एक्टिंग से काफी दूर हैं। लेकिन एक समय में उनके पास फिल्मों की लंबी लिस्ट होती थी। अपने समय में उन्होंने कई ऐसी फिल्में भी रिजेक्ट कीं हैं, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उनकी कुछ रिजेक्ट की हुई फिल्मों में तो बाद में कई बड़े स्टार नजर आए और वह फिल्म उनके कैरियर की सफल फिल्मों में से एक बनी थीं।

साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुड़वा भी ऐसी ही हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें पहले गोविंदा नजर आने वाले थे। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म जुड़वां में सलमान खान डबल रोल में नजर आए थे। ये उनके कैरियर की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में सलमान के काम को काफी सराहा गया था। 1997 में रिलीज हुई यह फिल्म हिट रही थी, पर उस दौर के सुपरस्टार गोविंदा ने एक बड़ा खुलासा करके सबको हैरान कर दिया था। 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था। बाद में ये फिल्म सलमान खान को दे दी गई थी। दरअसल, डेविड धवन और नंदू तोलानी ये फिल्म गोविंदा के साथ बनाना चाहते थे। लेकिन फिल्म में गोविंदा से बात हो चुकी थी। कहा जाता है कि जुड़वा में काम करने के लिए खुद सलमान ने गोविंदा से गुजारिश की वो इस फिल्म को न करें।

ऋषि करते थे फ्लर्ट, नीतू को था सब पता, फिर भी रहती थीं चुप

फिल्मी दुनिया में कपूर खानदान का अपना एक अलग नाम है। इस परिवार का सालों से मनोरजंन की दुनिया में दबदबा रहा है और अब भी इस परिवार के सदस्य एक्टिंग से जुड़े हैं। इस परिवार के अधिकांश सदस्यों ने एक्टिंग की दुनिया में धाक जमाई है। इसके साथ ही कपूर खानदार के पुरुषों के लव अफेयर्स भी काफी चर्चा में रहे हैं। पिता राज कपूर हों या फिर उनके सबसे छोटे बेटे ऋषि कपूर। फिल्मों में काम करते हुए इनके लव अफेयर्स के किस्से आज भी सुनाई देते हैं। इसी को लेकर नीतू कपूर का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

नीतू कपूर ने एक न्यूजपेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पति ऋषि कपूर के अफेयर्स पर अपनी बात रखी थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस पुराने इंटरव्यू की कटिंग वायरल हो रही है। इसके जरिए पता चल रहा है कि नीतू को पता था कि उनके पति अपनी साथी अभिनेत्रियों के साथ फ्लर्ट किया करते थे लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर करना सीख लिया था। नीतू का जो पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है उसके अनुसार, मैंने उन्हें अनगिनत बार फ्लर्ट करते हुए पकड़ा है। मैं सबसे पहली शख्स होती थी, जिसे उनके अफेयर्स का पता चलता था, जो आउटडोर शूटिंग के दौरान होते थे। लेकिन मैं जानती थी कि वे वन नाइट स्टैंड्स हैं।

1 बड़ा फैसला, फिर हिट पे हिट देते चले गए सैफ अली खान

बॉलीवुड में सैफ अली खान और अमृता सिंह की लव स्टोरी काफी मशहूर है। उनकी शादी से लेकर उनके डिवार्स तक की चर्चा आए दिन होती ही रहती है। बता दें, अमृता ने सैफ से तब शादी रचाई थी, जब वह अपने फिल्मी कैरियर के बिलकुल पीक पर थीं, और उस दौरान सैफ अपना फिल्मी कैरियर तैयार करने में जुटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमृता ने साल 1991 में अपने उम्र से 13 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान से शादी रचाई थी और शादी के बाद इन दोनों के एक बेटे इब्राहिम अली खान और बेटी सारा अली खान हुईं। अपने माता-पिता की तरह सारा ने भी अपना कैरियर फिल्मों में बनाने की ठानी और इसमें वह सफल भी रहीं और आज उनका नाम मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है। वहीं, दूसरी और अमृता से शादी रचाने के बाद मानो सैफ की तो किस्मत ही चमक उठी। उनके पास फिल्मों की लाइन लगने लगी और बॉक्स ऑफिस पर वह लगातार हिट पे हिट फिल्में देने लगे। देखते ही देखते सैफ अली खान उस स्टारडम को जीने लगे, जो कभी अमृता सिंह जिया करती थीं। आशिक आवारा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तू चोर मैं सिपाही सहित कई फिल्मों ने सैफ अली खान को सुपरस्टार बना दिया और आज भी सैफ फिल्मों में सक्रिय हैं।

कट, कॉपी, पेस्ट : अपना काम बेस्ट!

कट, कॉपी और पेस्ट आज के कम्प्यूटर युग के लिए नए नहीं हैं। जो लोग कम्प्यूटर और मोबाइल चलाने का अल्प ज्ञान भी रखते हैं, वे भी इन तीन शब्दों से सुपरिचित हैं। सुपरिचित ही नहीं, बल्कि वे उसे बखूबी भुना भी रहे हैं। जुबान के गूंगे भी सुमधुर गीत गुनगुना रहे हैं। महफिल में गजब ढा रहे हैं। मेडल और शील्ड जीत फनफना रहे हैं। हे भगवान! ये कैसे दिन आ रहे हैं। जब चने के खेत में भाड़ भुने जा रहे हैं।

मेरे मतानुसार वर्तमान युग का प्राय: प्रत्येक व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया इन तीन बातों से संचालित है। 1.कट, कॉपी और पेस्ट 2. रेडीमेड और 3. शॉर्ट कट। ये तीनों ही बातें आपस में इस प्रकार घुल-मिल गई हैं कि वे परस्पर पूरक बनकर मानव-समाज की संचालिका बनकर उभरी हैं। आदमी को कामचोर बनाने वाली संस्कृति और कामचोरों के मजे हैं। वही तो आज सर्वत्र फिरते सजे-धजे हैं। काम करने वालों के फजीते ही फजीते हैं। वे कितना भी काम करें; पर वहां नहीं उजीते हैं। कामचोरों की मौज है। आज हर घर, गांव, गली, नगर, सड़क या डगर-डगर उनकी ही फौज है। इधर से चुराया, उधर भिजवाया। किसी और के निर्माण पर अपना लेबिल सजाया। दर्शकों और श्रोताओं को मूर्ख बनाया। इसी को कहते हैं, राम-राम जपना, पराया माल अपना। नकलीपन की नकली संस्कृति का युग। सब कुछ ठगाई। दूसरे की वस्तु अपनी बनाई।

काम न करना पड़े। पसीना न बहाना पड़े, दिमाग न लगाना पड़े; बस इसी जुगत में दिन-रात एक किए हुए हैं। इसलिए उन्हें एकमात्र रेडीमेड की दरकार है, जहां भी देखिए कामचोरों की सरकार है। खान-पान में फास्ट फूड, पास्ता, मेकरोनी, नूडल्स, चाऊमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और न जाने क्या-क्या! सूची लंबी है। बस इतने से ही समझ लें कि हम क्या-क्या नहीं खा रहे! और अनगिनत बीमारियों को अपने देह धाम में असमय बुला रहे। इसी प्रकार का है हमारा पहनावा। भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का धावा! जींस, टॉप, स्कर्ट, लैगी, टीशर्ट, प्लाजो आदि का बुलावा। पहन रहे हैं किशोर, युवा, प्रौढ़ या दादी-बाबा।

राजमार्ग से कोई नहीं चलना चाहता। सबको पगडंडियां चाहिए। शॉर्टकट ही चाहिए। इसलिए तीव्र गति वाहन का है सर्वत्र संचलन। भागे चले जा रहे हैं, किंतु किसी को नहीं पता कि जाना कहां है? उनकी मंजिल कहां है? बस चलते चले जाना है। न किसी की सुनना है न किसी को कुछ सुनाना है। अब घर नहीं, घोंसलों में रहने का फैशन है। सब अपने-अपने दरबों में बंद हैं। जीवन में गति है, लय है न छंद है। सब कुछ अतुकांत नहीं, सर्वथा बेतुका। वह तो कुचल ही गया; जो थोड़ा-सा भी रुका, झुका या इधर-उधर उझका। फ्लैट-फैशन ने उन्हें मुर्गी का दरबावासी बना दिया है। फ्लैटों ने सबकुछ फ्लैट कर दिया है। बस अपनी इतनी सी दुनिया में अंडे देते और सेते रहो। अपनी नाव अपने आप खेते रहो। स्वार्थी हो, कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। कोई क्यों व्यर्थ कोर्ट-कचहरी से अपने कचों का हरण कराएगा!

सिनेमाई (फिल्मी) संस्कृति इस कदर हावी है कि मौलिकता का अंतिम संस्कार ही कर दिया गया है। कहीं किसी कॉलेज, विद्यालय, मेले, प्रदर्शनी, आदि में केवल नृत्य के नाम पर देह-संचालन ही बचा है। जैसे फिल्मों में गीतकार, संवाद-लेखक, गायक, अभिनेता, अभिनेत्री, अलग-अलग होते हैं। वहां सबका काम अलग-अलग होता है। अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के मात्र होठ हिलते हैं। स्वर किसी और का होता है। लेखक कोई और होता है। आज गीत और संवाद किसी चिप या रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। युवक और युवतियां केवल अपने कटि-संचालन से ही सारा श्रेय लूटने की जुगत लगाए रहते हैं। यहां उनके देह-संचालन के अतिरिक्त उनका कुछ भी अपना नहीं है। न शब्द, न वाक्य, न गीत, न संवाद, न स्वर, न गला; निजता और मौलिकता के नाम पर सब कुछ शून्य। यही शार्टकट-संस्कृति है। यही कॉपी, कट, पेस्ट, रेडीमेड और लघुकाट संस्कृति है। सबकुछ उधार का। सनातन अमर संस्कृति की बखिया उधेड़ता उखाड़ता। आज इसी के घंटे घनघना रहे हैं। और लोग अपनी नकली प्रतिभा के डंके पिटवा रहे हैं। तुम्हें ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, वीणा, यहां तक कि चिमटा बजाना भी नहीं आता। हां, गाल बजाना अवश्य आता है।

मौलिकता मर चुकी है। नकली कट-कॉपी कर ली और पेस्ट कर दी। मात्र धोखा। पर आज तक किसी ने कभी नहीं रोका। यथार्थ धुआं-धुआं हो रहा है। और आदमी सपरेटा संस्कृति का दूध पी-पीकर पुष्ट हो रहा है। हमें तो लगता है संस्कृति के नाम पर सब गुड़ गोबर हो रहा है। ऐ मानव! तू कहां किस खुमारी में सो रहा है। स्वर्ग की तरह पाताल के भी सात स्तर हैं, तू कहां किस पाताल की तली में जाकर उसकी शोभा-वृद्धि करेगा, कोई नहीं जानता!

● **डॉ.भगवत स्वरूप 'शुभम'**

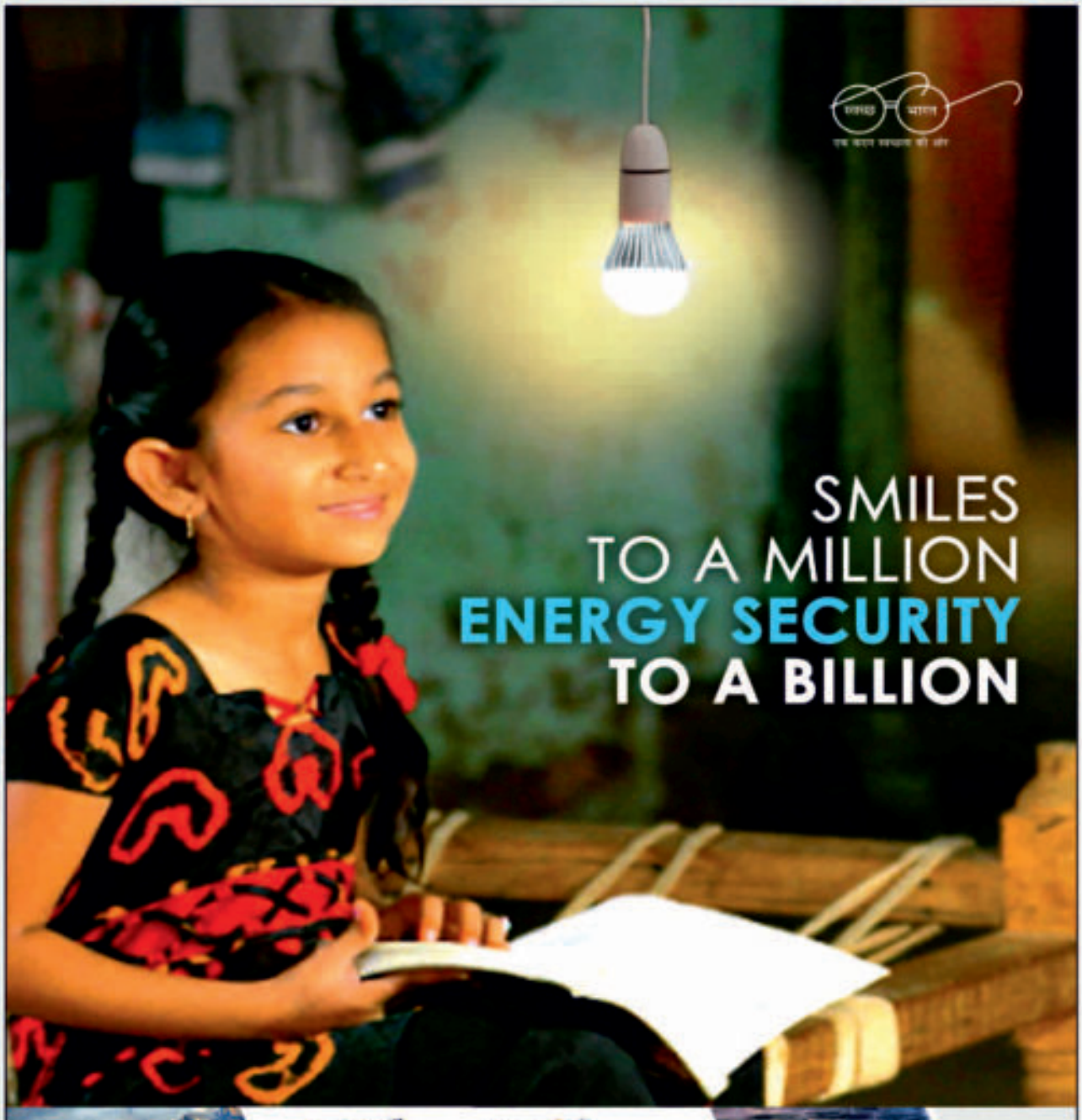

MCL

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in mahanadicoal mahanadicoal

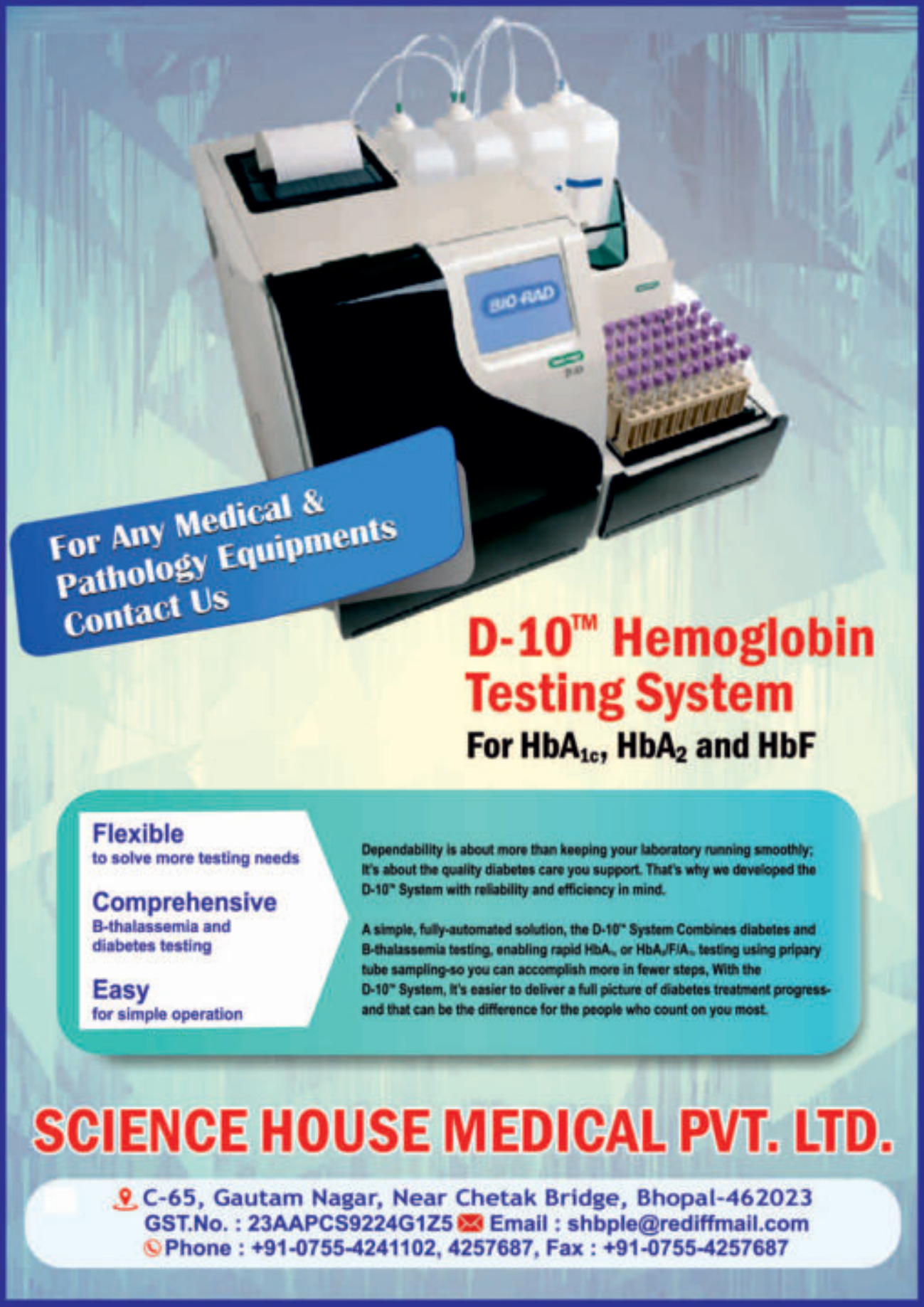

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687